राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 232

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 29 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

धौनी की सीट पर अब भी कोई नहीं बैठता : चहल

>> 14

सीएए से दूर हुआ ऐतिहासिक अन्याय : मोदी

पीएम बोले ▶ वोट बैंक की राजनीति के लिए विरोध कर रहीं कुछ पार्टियां

पाकिस्तान को चेतावनी– हिमाकत न करे, 10 दिन में ही तोड़ देगा दम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध से बाज आने की चेतावनी देते हुए कहा कि जंग हुई तो हमारी सेनाओं के सामने पाकिस्तान 10 दिन के अंदर दम तोड़ देगा। आतंकवाद पर नकेल और अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात सुधरने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, न्यू इंडिया समस्याओं को टालना नहीं उससे टकराना व समाधान निकालना जानता है। इसीलिए वह सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिये आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। पीएम ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के चौतरफा विरोध को खारिज करते हुए कहा, ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने के लिए यह कानून लाया गया है। वोट बैंक की राजनीति में इसका विरोध कर रहे दलों को पाकिस्तान में गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली कैंट में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल एनसीसी कैडेटों की रैली को संबोधित करते हुए कश्मीर को भारत का मुकुट मणि बताया। उन्होंने कहा, कि वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था, इसीलिए अनुच्छेद-370 हटाने का फैसला किया। पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन-तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते दस दिन से ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए वह दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। लेकिन हमारी सख्त नीतियों के चलते आज सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी अलगाववाद-आतंकवाद को बहुत सीमित कर दिया गया है। भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकने के बड़े फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया।

सीएए को लेकर विरोधी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसे वापस लिए जाने की गुंजाइश नहीं है। स्वतंत्रता के बाद ही भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं-सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि अगर उन्हें जरूरत होगी तो वे भारत आ सकते हैं। महात्मा गांधी की भी यही इच्छा थी और 1950 में हुए नेहरू-लियाकत समझौते की भी यही भावना थी। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए हम उन्हें नागरिकता दे रहें हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ आस्था की वजह से ही पाकिस्तान में बेटियों पर जुल्म और दुष्कर्म नहीं होते? सीएए से दलितों के प्रभावित होने की बात खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दलितों की आवाज बनने का ढोंग करने वालों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देते।

युवाओं के नजरिये को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत थके-हारे और कुछ नहीं करने वालों को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। वह समस्याओं को टालने नहीं, उससे टकराते हुए समाधान चाहता है। आतंकवादी, नक्सली-माओवादी हमले, अलगाववादियों के भारत के खिलाफ जहर उगलने से लेकर तिरंगे के अपमान को न्यू इंडिया स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही हालात से कश्मीर को बाहर लाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अनुच्छेद-370 यह कहकर लागू हुआ था कि यह अस्थायी है, लेकिन इसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई।

नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उनके साथ हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टीनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। प्रेट्र

मोदी बोले, रामजन्मभूमि मामले की राह से हटाए कानूनी रोड़े पेज>>3

सिंध में हिंदू लड़की के अपहरण पर भारत ने पाक से जताया विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान में सिंध प्रांत के हाला शहर में हिंदू लड़की को शादी के मंडप से अगवा किए जाने की घटना पर भारत ने मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को समन कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सूत्रों ने बताया कि पाक सरकार से मामले की जांच करने के साथ ही अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय समेत उसके सभी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। पाक से इस नीचतापूर्ण व जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के कदम उठाने का आग्रह भी किया गया है। भारत ने 26 जनवरी को सिंध प्रांत में ही थारपारकर स्थित माता रानी भाटियानी मंदिर को अपवित्र करने के संबंध में भी विरोध जताया है। ज्ञात हो,भारती बाई (24) नामक हिंदू युवती को हथियारबंद लोगों ने रविवार को हाला शहर में उसके विवाह स्थल से अगवा कर लिया था। बाद में जबरन धर्मांतरण कराकर उसकी शादी शाहरुख गुल नामक व्यक्ति से करा दी। सिंध के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हरि राम किशोरी ने मंगलवार को पुलिस से इस मामले की रिपोर्ट तलब की। इस बीच, शाहरुख ने सोशल मीडिया पर उन दस्तावेजों की तस्वीरें पोस्ट की हैं जो दिखाते हैं कि भारती का दिसंबर, 2019 में कराची के बनूरी कस्बे में धर्मांतरण हो गया था और उसने बुशरा नाम अपना लिया था।

वुहान से निकाले जाएंगे भारतीय नागरिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चीन में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में फंसे 300 से ज्यादा भारतीय छात्रों, कारोबारियों व सैलानियों को वापस लाने के भारत के प्रस्ताव को चीन सरकार ने मंजूरी दे दी है। बुधवार सुबह एयर इंडिया के विमान के वुहान रवाना होने की संभावना है। स्वदेश लौटने के बाद सभी लोगों को कम से कम 14 दिनों तक अलग चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। भारत के अलावा अन्य देशों ने भी चीन से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है।

इससे पहले दिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों को बताया कि अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार लगातार चीन सरकार के संपर्क में है। लोगों को भारत सरकार पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में फंसे छात्रों के अभिभावकों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक किसी भी भारतीय छात्र या नागरिक के इस वायरस से संक्रमित होने की सूचना नहीं है।

हालात पर सरकार की नजर पेज>>13

सरोकार

पौड़ी में स्थापित किया उम्मीदों का सोलर प्लांट

पौड़ी : कुछ अपना करेंगे...। आज हर युवा में इसकी चाहत क्यों बढ़ रही है, यह कोई धीरेंद्र सिंह रावत से समझे। 31 वर्ष तक दिल्ली में संघर्ष के बाद गांव लौटे तो सोलर प्लांट लगाया। आज यह प्लांट उनके व अन्य लोगों के लिए भी नई उम्मीदें बना है। (पेज-11)

जागरण विशेष

यहां वसंत पंचमी पर रहती है दशहरे जैसी धूम

कटिहार : बिहार के कटिहार जिले में वसंत पंचमी पर दशहरे जैसी धूम रहती है। जगह-जगह सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। चार दिनों तक मेले जैसा नजारा रहता है। जिले में 350 से अधिक सार्वजनिक पंडालों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

महिलाओं से धार्मिक भेदभाव पर 10 दिन में पूरी होगी सुनवाई

नई दिल्ली : विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों में प्रवेश को लेकर महिलाओं से होने वाले भेदभाव के मामले की नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद दस दिन में पूरी कर ली जाएगी। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संकेत दिए।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका पर फैसला आज

नई दिल्ली : निर्भया कांड के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। मुकेश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दया याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

फ्रॉड जांच की निगरानी के लिए जवाबदेह नहीं होंगे बैंक प्रमुख

नई दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए बड़े फ्रॉड के मामलों की जांच के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही बैंक के एमडी और सीईओ की नहीं होगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

इजरायली पीएम पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ

यरुशलम : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने इन मामलों में राहत पाने की संसद से अपनी याचिका वापस ले ली है। इस कदम के बाद भ्रष्टाचार के तीन मामलों में उन्हें आरोपित कर दिया गया है।

विश्व कप की तैयारी
तीसरा टी-20
भारत vs न्यूजीलैंड
दोपहर 12:30 बजे से
स्थान : हैमिल्टन
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

शरजील इमाम बिहार से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जहानाबाद

- शरजील ने भागने की तैयारी में बदल लिया था हुलिया, कार भी जब्त
- दिल्ली पुलिस ने पैतृक आवास से किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी
- सीजेएम ने 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंपा

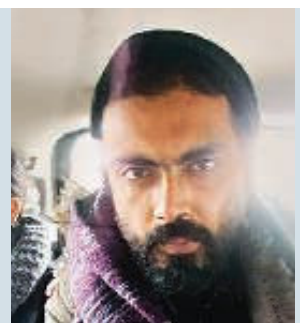

बिहार के जहानाबाद जिले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया शरजील इमाम। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने बिहार पुलिस की मदद से शरजील को दबोचा है। जागरण

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध प्रदर्शनों में असम को देश से काटने का भाषण देने के आरोपित शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। शरजील इमाम को बिहार पुलिस की मदद से जहानाबाद जिले के काको गांव से मंगलवार की दोपहर बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस कार को भी जब्त कर लिया है, जिससे वह भागने की तैयारी में था।

पुलिस टीम ने काको थाने में पूछताछ के बाद देर शाम उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के समक्ष पेश कर 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। मेडिकल कराने के बाद उसे पटना ले जाया गया। सुरक्षा के लिहाज से उसे महिला थाने में रखा गया है। बुधवार को विमान से दिल्ली ले जाया जाएगा। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी छोटी करवा ली थी।

दिल्ली क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि शरजील इमाम को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच की पांच टीमें बनाई गई थीं। पुलिस की टीम ने पटना, जहानाबाद, मुंबई सहित उसके अन्य ठिकानों पर रविवार और सोमवार को छापेमारी की थी। इस बीच पुलिस को पता चला था कि आरोपित सीएए के विरोध में आयोजित एक रैली में पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में देखा गया है। इस जानकारी पर क्राइम ब्रांच टीम ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर फुलवारी शरीफ सहित उसके पैतृक गांव काको के मलिक टोला में छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके भाई मुजम्मिल और एक साथी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। इसमें पुलिस को शरजील के संबंध में अहम सुराग मिला। इसके बाद सोमवार रात उसे काको गांव के मलिक टोला से दबोच लिया गया।

पांच राज्यों में दर्ज है मुकदमा पेज>>5

राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा एक हफ्ते में संभव

- केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्ट के गठन की घोषणा होगी
- नई मस्जिद के लिए पांच एकड़ की तीन वैकल्पिक जमीनें भी होंगी प्रस्तावित

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा करने वाली है। इसके साथ ही वह अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन की भी पेशकश करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए ढाई महीने से ज्यादा हो गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को अयोध्या से संबंधित कुछ बड़े काम करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। अब केंद्र सरकार उन जिम्मेदारियों को तेजी से पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है। राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है और इसे मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने राम मंदिर निर्माण संबंधी ट्रस्ट के गठन के लिए खाका तैयार कर लिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए पांच एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली है।

एक अधिकारी ने बताया कि संभवतः एक हफ्ते के अंदर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ का प्लॉट देने की भी पेशकश कर दी जाएगी। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीन अलग-अलग प्लॉट के विकल्प दिए जाएंगे। ताकि वह अपनी पसंद की जमीन चुन सकें।

ज्ञात हो, सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने रामजन्मभूमि विवाद को सुलझाते हुए नौ नवंबर को ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा, मंदिर बनाने के लिए तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार अयोध्या में ही पांच एकड़ का प्लॉट नई मस्जिद बनाने के लिए आवंटित करे।

ट्रस्ट का पूरा खाका होगा तैयार : कोर्ट के आदेशानुसार रामजन्मभूमि को लेकर केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वह एक ट्रस्ट का गठन करके उसके सदस्यों का निर्धारण करे। उसके कामकाज और उस ट्रस्ट की शक्तियों और ट्रस्ट के ट्रस्टीज के अधिकारों को परिभाषित करे। फिर मंदिर निर्माण के लिए रामजन्मभूमि को उस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दे। साथ ही इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं, घटनाओं और अनुपूरक मामलों का भी निस्तारण करे। एक अधिकारी ने बताया कि अब इन मामलों को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, ताकि अंतिम फैसला लिया जा सके।

अयोध्या पर डेस्क सक्रिय : केंद्रीय गृह मंत्रालय इसी महीने की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और मस्जिद के लिए भूमि आवंटन के लिए एक अलग डेस्क बना चुका है। अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रालय के तीन अधिकारी इस कार्ययोजना को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अयोध्या से जुड़े हर मामले की सुनवाई यही नई डेस्क कर रही है।

नारायण मूर्ति ने रतन टाटा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को टाइ (द इंडस इंटरप्रेन्योर्स) कॉन अवार्ड समारोह के दौरान टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति। इस मौके पर नारायण मूर्ति ने रतन टाटा को टाइ कॉन मुंबई 2020 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम में उद्योग जगत की कई नामी हस्तियां मौजूद थीं। प्रेट्र

पीके पर बोले नीतीश–पार्टी में रहें तो ठीक, न रहें तब भी ठीक

राज्य ब्यूरो, पटना

पटना में प्रेसवार्ता करते जदयू के मुखिया नीतीश कुमार। प्रेट्र

- नीतीश बोले : अमित शाह के कहने पर किया था जदयू में शामिल
- पीके का पलटवार, झूठ बोल रहे हैं नीतीश
- पीके के जदयू से निलंबन की चर्चा शुरू

प्रशांत किशोर फाइल फोटो

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और अन्य मसलों पर पार्टी की राय से अलग विचार रख लगातार ट्वीट करने वाले प्रशांत किशोर (पीके) पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी राय स्पष्ट कर दी। जदयू की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में नीतीश ने कहा, अगर पीके को जदयू में रहना है तो उन्हें जदयू के बुनियादी ढांचे को स्वीकार करना होगा। वह अगर पार्टी में रहेंगे तो ठीक और अगर नहीं रहेंगे तो भी ठीक। जदयू की मंगलवार को हुई बैठक में पीके शामिल नहीं हुए थे। नीतीश के इस बयान के बाद पीके ने अवसरवादी अंदाज में सीएम के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई कि पीके को जदयू से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाल ही में नीतीश ने जदयू के पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा के बारे में भी कहा था कि उन्हें जहां जाना हैं जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीके को उन्होंने अमित शाह के कहने पर ही जदयू में शामिल किया था। हो सकता है अब उनका कहीं और जाने का मन होगा। आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। वैसे जब तक इच्छा करे पार्टी में रहें।

जदयू साधारण लोगों का दल : पीके द्वारा लगातार ट्वीट किए जाने पर चुटकी लेते हुए नीतीश ने कहा कि हमारी पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है। ट्वीट का क्या है? जदयू इंटेलेक्चुअल लोगों का दल नहीं है।

पीके ने ट्वीट कर साधा निशाना : नीतीश कुमार के इस वक्तव्य के बाद पीके ने देर शाम किए ट्वीट में कहा, नीतीश कुमार इतने नीचे आ गए हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं। जदयू में मुझे क्यों शामिल कराया, इसे अपने अंदाज में रंग देने का क्षुद्र प्रयास कर रहे हैं। अगर वह यह कह रहे कि अमित शाह के कहने पर मुझे उन्होंने जदयू में शामिल किया तो कोई कैसे यह यकीन करेगा कि उनके पास अब भी यह साहस है कि वैसे व्यक्ति की बात नहीं सुनें, जिसकी अनुशंसा अमित शाह ने की है।

भारत को टुकड़े-टुकड़े करने का किसी में दम नहीं : देश विरोधी वक्तव्यों के मामले में गिरफ्तार शरजील के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अपनी राय रखना अलग बात है पर देश का जो संविधान है उससे अलग नहीं होना चाहिए। देश के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे इतना दम किसी में नहीं है। नीतीश ने कहा, जिसने कुछ असंवैधानिक कहा है उस पर कानून के तहत मुकदमा हुआ है। अदालत अपना काम करेगी। देश के कानून को समझना चाहिए। देशहित से बाहर की बात नहीं होनी चाहिए।

तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी देश नामीबिया से चीतों को लाकर बसाने की योजना को दी मंजूरी, गठित की तीन सदस्यीय कमेटी, 1947 में आखिरी तीन चीतों के शिकार के बाद से भारत में विलुप्त हो चुका है यह शिकारी जीव

73 साल बाद ... फिर से देश में दिखेगी चीते की रफ्तार

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ, तो भारत की धरती से 73 साल पहले विलुप्त हो चुका चीता फिर से रफ्तार भरता दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में भारत में अफ्रीका से चीता को लाकर बसाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने पहले उनके लिए उपयुक्त ठिकाने की तलाश करने को कहा है। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है, जो हर चार माह में इससे जुड़ी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को देगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, देश में चीता को अंतिम बार 1947 में देखा गया था, जब सरगुजा महाराज ने देश में बचे तीन चीतों को शिकार में मार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीतों को बसाने की यह अनुमति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें अफ्रीकी देश नामीबिया से चीतों को लाने की अनुमति मांगी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के कूनो-पालपुर में एशियाई शेरों की जगह चीता को बसाने के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय पीठ के इस ताजा आदेश से चीता को लाने की उम्मीद फिर जगी है।

प्रतीकात्मक फोटो

इस मामले की प्रगति पर नजर रखने के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी में भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक रंजीत सिंह, वर्तमान महानिदेशक धनंजय मोहन और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में वन्यजीव के डीआइजी को शामिल किया है। यह तो तय नहीं है कि चीतों को कहां रखा जाएगा लेकिन अधिकारियों के अनुसार कई अनुकूल क्षेत्र हैं। इनमें मध्य प्रदेश का कूनो-पालपुर भी है। यहां काफी पहले चीता मिलने के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि रहवास की अनुकूलता उस क्षेत्र में मिलने वाले उपयुक्त भोजन पर निर्भर होगी। बता दें कि चीता का पसंदीदा भोजन चिंकारा और ब्लैक बक (काला हिरन) होता है। साथ ही इसके लिए मैदान भी चाहिए, ताकि वह अपने शिकार को दौड़ाकर पकड़ सके।

चीता को लाने की योजना पर कब दिखी तेजी : भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को लाने की चर्चा वैसे 2001 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसे अमलीजामा 2009 में उस समय पहनाया गया, जब शेरों के दूसरे ठिकाने के रूप में तैयार किए गए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो-पालपुर को गुजरात ने एशियाई शेरों को देने से मना कर दिया। इसके बाद योजना बनाई गई कि यहां अफ्रीका से चीतों को लाकर रखा जाए। शेरों के न आने से कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य से विस्थापित ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने लगा था। वह जमीन वापस मांग रहे थे।

300 करोड़ की थी योजना, अब बढ़ेगी लागत : देश में चीतों को बसाने की यह पूरी योजना वैसे तो 300 करोड़ रुपये की है, हालांकि 2009 से अब तक में यह लागत बढ़ जाएगी। फिलहाल उस समय इस योजना के तहत चीता को बसाने के जिन तीन स्थानों का चयन किया गया था, उनमें कूनो-पालपुर, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और राजस्थान के जैसलमेर जिले में शाहगढ़ को शामिल किया था।

12 चीता को लाने की है योजना : प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना के तहत करीब 12 चीते लाए जाने हैं। इनमें नर और मादा दोनों शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, नामीबिया ने भारत को मुफ्त में चीता देने पर सहमति जताई है। दुनिया में अभी 7,000 से ज्यादा चीते हैं। इनकी बड़ी संख्या अफ्रीकी देशों में ही पाई जाती है।

चीतों की सुनिए चीत्कार पेज>>5

उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर–सिपाही को भी देना होगा संपत्ति का ब्योरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर से सिपाही तक के अराजपत्रित पुलिस अफसरों व कर्मियों के लिए प्रति वर्ष चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देने का नियम लागू करने की सिफारिश की है। साथ ही पीपीएस संवर्ग के अफसरों के लिए पांच वर्षों के बजाय सालाना चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने की अनिवार्यता लागू किए जाने की बात भी कही है। अब तक अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को संपत्ति का कोई ब्योरा नहीं देना होता था।

लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इस वर्ष पुलिस महकमे के लिए यह दूसरी बड़ी खबर है। ज्ञात हो, बीते दिनों गौतमबुद्धनगर के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने गोपनीय पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले को उठाया था। पांच आइपीएस अधिकारी भी आरोपों से घिरे हैं। थानों पर भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले भी उजागर हो चुके हैं। ऐसे में अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लिए हर साल चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने की सिफारिश बेहद अहम मानी जा रही है।

डीजीपी ने मंगलवार को शासन को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि उप्र पुलिस में संपूर्ण सुचिता व पादर्शिता लाने के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण नियमित रूप से दिए जाने के लिए नियमावली को और मजबूत बनाने की जरूरत है।

आइपीएस अफसर हर साल देते हैं संपत्ति का विवरण : आइपीएस अफसरों के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण हर वर्ष 15 जनवरी तक देना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पीपीएस संवर्ग के कर्मचारियों को नियमावली के अनुसार, ऐसा विवरण पांच साल की अवधि में देना होता है।

19.75 लाख रुपये की नकदी बरामद की है शाहदरा निर्वाचन कार्यालय की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान दो गाड़ियों से। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 जनवरी 2020

स्कूलों पर भाजपा सांसदों की रिपोर्ट झूठी : केजरीवाल

दो टूक ▶ भाजपा सांसदों ने सरकारी स्कूलों में जाकर वीडियो किया था ट्वीट, प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने इन्हें बताया फर्जी

बोले–1024 सरकारी स्कूलों में से महज आठ में ही खोज पाएं कुछ खामियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही आप और भाजपा में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पिछले चार दिन से सरकारी स्कूलों का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया कि हमारे आठ सांसदों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा देखी है। स्कूल बदतर पाए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर पलटवार किया।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का गलत वीडियो बनाकर शिक्षा व्यवस्था पर अंगुली उठाने के लिए भाजपा ने फर्जीवाड़ा किया है। भाजपा दिल्ली सरकार के 1024 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ आठ में कुछ कमियां ही खोज पाई। इनमें से भी कई आरोप को गलत पाया गया है। केजरीवाल ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह मेरे साथ किसी स्कूल में चलें और दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर देखें। अगर वहां कमियां भी मिले तो वह बताएं। उसे हम ठीक कर देंगे लेकिन झूठ ने फैलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने अपनी पार्टी के सारे सांसदों और कार्यकर्ताओं को सारे स्कूलों में कमियां निकालने के लिए भेज दिया। शाह ने जांच की पूरी रिपोर्ट आज ट्वीट की है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के सांसदों ने सच को छिपाया है और शिक्षा के प्रति धोखा किया है। उन्होंने एक-एक करके सभी स्कूलों के वीडियो के बारे में अपनी बात रखी। सिसोदिया ने कहा कि अमित शाह की पूरी की पूरी रिपोर्ट झूठी है। उनको शिक्षा की बात करने की हिम्मत नहीं होती है। इन्होंने लिखा है कि कल दिल्ली भाजपा के आठ-आठ सांसद अलग-अलग स्कूलों में गए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ सात ही सांसद हैं। चुनाव का माहौल है। शायद शाह भूल गए होंगे। **सिसोदिया ने भाजपा सांसदों के आरोपों को बताया गलत** : सिसोदिया ने कहा कि सांसद गौतम गंभीर ने स्कूल का वीडियो ट्वीट कर उसे बदहाल बताया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस स्कूल के गेट पर नोटिस लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यह स्कूल बंद है। यह 9 अक्टूबर 2019 से एसबीवी जेजे कॉलोनी में लगेगा। यह स्कूल स्थानांतरित किया जा चुका है। उन्होंने बंद स्कूल का फर्जी वीडियो बनाया।

सिसोदिया ने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा मटियाला के जिस स्कूल में गए,, वहां पर एक तरफ पुरानी बिल्डिंग है और दूसरी तरफ हमने शानदार बिल्डिंग बनवाई है। पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरे अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक पुरानी बिल्डिंग के सामने से फेसबुक लाइव किया। मुझे वहां के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि सांसद अपने लोगों को डांट भी रहे थे कि नई बिल्डिंग न दिखे। सिसोदिया ने कहा कि इसी स्कूल के सामने नगर निगम के स्कूल का बुरा हाल है। वह उन्होंने नहीं देखा।

उन्होंने कहा कि सांसद रमेश बिधूड़ी जिस स्कूल की फोटो लेकर आए हैं, वहां पर नई बिल्डिंग बन रही है। वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। उसकी उन्होंने फोटो खींच ली। उन्होंने कहा कि सांसद हंसराज हंस रात को 7.30 बजे मंगोलपुरी के ब्लॉक-के स्कूल में गए। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है । रात में वहां पर प्रधानाचार्य नहीं थे। उन्होंने एस्टेट मैनेजर के साथ गाली-गलौज की। स्कूल में मल्टीपरपज रूम में दरी बिछी होती है। दरी पर बच्चे प्रैक्टिस आदि करते हैं। उसे उन्होंने खुलवाया और उसका वीडियो बनाकर ट्वीट किया कि स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं।

नई दिल्ली स्थित आप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (दाएं)। साथ में हैं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।। जागरण

सिसोदिया जब चाहें उनके साथ स्कूल का दौरा करेंगे : तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आप ने भाजपा सांसदों पर स्कूलों को लेकर फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनौती दी कि वह जब चाहें सांसदों के साथ स्कूल का दौरा कर लें। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को विश्वस्तरीय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनका दौरा करने का निमंत्रण दिया। इसे स्वीकार करके भाजपा सांसदों ने स्कूलों का दौरा करके सच्चाई जनता के सामने रख दी है। स्कूलों के बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों की सच्चाई भी सामने लाने की तैयारी है।

अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों की सच्चाई सामने लाने की भी बात कही

उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों की खस्ता हालत से केजरीवाल सरकार के विश्वस्तरीय स्कूल के दावों के पोल खुल गई। कई स्कूलों में इमारत की कमी की वजह से बच्चे दो से तीन घंटे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक कमरे में दो-दो कक्षाएं लग रही हैं। स्कूलों में पेयजल व अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अतिथि शिक्षक अपनी नौकरी को लेकर असमंजस में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने सच्चाई छिपाने के लिए खजूरी खास के एक स्कूल में पहुंचकर गेट बंद कर दिया। उस स्कूल में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 20 स्कूलों को सजाकर नहीं बल्कि सभी 1020 स्कूलों को दुरुस्त करने से दिल्ली की शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

दिल्लीवालों के अपमान के लिए भाजपा ने बाहर से बुलाए नेता : सीएम

जासं, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को करावल नगर और गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दूसरी सभी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप को हराने के लिए ये सभी पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। भाजपा को दिल्ली वालों का साथ नहीं मिला तो उसने बाहर से 200 सांसद, 70 केंद्रीय मंत्री और 11 मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए बुलाया है। जब ये लोग आपके घर वोट मांगने आएं, तो इन से पूछना कि इनके राज्य में बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की क्या हालत है। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। रोड शो में उन्होंने करावल नगर के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक और गोकलपुर के प्रत्याशी चौधरी सुरेंद्र सिंह के लिए लोगों से समर्थन मांगा।

मुख्यमंत्री के रोड शो की शुरुआत सोनिया विहार से हुई। इसके बाद अन्य इलाकों से गुजरते हुए सोनिया विहार में ही इसका समापन हुआ। इसके बाद केजरीवाल गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां शिव विहार पुलिया के पास रोड शो की शुरुआत करते हुए उन्होंने दूसरी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने आपका बेटा बनकर काम किया। ईमानदारी से काम करते हुए खूब मेहनत की। आपका बेटा बनकर बिजली और पानी का बिल भर दिया। बच्चों के स्कूल का बंदोबस्त किया। बड़ा बेटा बनकर बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराई।

चुनावी हलचल

तीर्थ यात्रा योजना पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस योजना के लिए यात्री को चुनने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा लीगल सेल के संयोजक राजेश कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत आवेदन लेने और चुनने सहित पूरी प्रक्रिया सरकार और कार्यकर्ताओं के नियंत्रण में है। (जासं)

दिल्ली के हित में केंद्र ने उठाए कई कदम : जावडेकर

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार केंद्र के काम में बाधा डालती रही है, बावजूद इसके लोगों के हित में कई काम किए गए हैं। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। (राब्यू)

देश की खातिर राष्ट्रभक्तों का चुनाव करें : नड्डा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का इतिहास गौरवशाली रहा है और भविष्य भी गौरवशाली रहेगा। उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाने का सबसे बड़ा कारण उनकी राष्ट्र भक्ति को बताया। नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा के लिए देश पहले पार्टी बाद में है। ऐसे में जरूरी है कि देश की खातिर राष्ट्रभक्तों का चुनाव करें।

नड्डा ने कहा कि दिल्ली के राजनीतिक दल ने पांच साल के दौरान राजधानी के लोगों को छला है। एक बार फिर से इसी राजनीतिक दल ने फिर से गुमराह करना शुरू कर दिया है। नड्डा ने कहा कि दिल्ली का पानी जहरीला है और अब वही राजनीतिक दल दिल्ली के निवासियों को आरओ का पानी देने का वायदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पांच साल के दौरान यमुना का पानी साफ करने का वादा किया था, लेकिन पांच साल बाद यमुना उससे भी ज्यादा गंदी हो गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आठ फीसद बच्चे कम हो गए। 20 हजार शिक्षकों को स्थाई करने को कहा था पर अब तक एक भी शिक्षक को स्थाई नहीं किया। कृत्रिम बारिश कराने और कृत्रिम रूप से हवा साफ (आर्टिफिशियल एयर प्यूरीफायर) कराने की योजना पर काम नहीं किया। मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार में अड़ंगा डाल दिया। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया, इस वजह से दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज संभव नहीं हो सका।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि एक साल होने को है और जेएनयू कैंपस में देश के टुकड़े-टुकड़े करने का नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार और उमर खालिद के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति नहीं दी। शाहीन बाग में जहां से अरविंद केजरीवाल भाषण दिया करते थे, उसी जगह से शरजील भाषण देता था, अब आरोपित शरजील पकड़ा गया है। अब वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि उनका शरजील से क्या संबध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत कठपुतली कॉलोनी में 500 मकान बना दिए गए। दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिला दिया गया। इसी दिल्ली को जाम और प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बनवाया, जहां से प्रतिदिन 60 हजार वाहन दिल्ली के बाहर से निकल रहे हैं। 2014 में सरकार बनाने के साथ नरेंद्र मोदी ने दंगा पीड़ित परिजनों को 127 करोड़ का राहत पैकेज दिया।

हरि नगर में आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (बाएं)। साथ में हरि नगर विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (बाएं से दूसरे)। जागरण

अनुराग ठाकुर मामले में चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट

जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली की चुनावी रैली में लोगों से विवादित नारा लगवाने के मामले में मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी (सीईओ)ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी।

अनुराग ठाकुर सोमवार को दिल्ली में रिठाला विधानसभा सीट से प्रत्याशी मनीष चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय मंच से उन्होंने कथित रूप से देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगवाए थे। वहीं, पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को सभा के दौरान विवादित बयान दिया था। इसमें कहा था कि शाहीन बाग जैसी स्थिति पूरी दिल्ली में हो सकती है। अगर अभी संभले नहीं तो ये लोग घरों में घुसकर डराएंगे। इसलिए दिल्ली के लोगों को सोचना होगा और फैसला करना होगा। दिल्ली सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इसकी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का जिक्र है। अब आगे चुनाव आयोग निर्णय लेगा।

सरकार बनी तो एक घंटे में खाली हो जाएगा शाहीन बाग : प्रवेश वर्मा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली

पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने रणहौला में आयोजित सभा के दौरान अपने संबोधन में शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनी तो एक घंटे के अंदर पूरे शाहीन बाग को खाली करा लिया जाएगा। शाहीन बाग में एक भी आदमी नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आज शाहीन बाग में पांच लाख लोग जुटे हैं, यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वहां 20 लाख लोग जुटेंगे। ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने।

विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में आयोजित सभा में प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर दिल्ली की जनता नहीं जागी तो शाहीन बाग की आग पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लेगी। शाहीन बाग में जो भीड़ जुट रही है, उसके तेवर में धमकी है। वे भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस ताकत का इस्तेमाल दिल्ली की जनता को डराने में किया जा रहा है, जो सही नहीं है। प्रवेश वर्मा यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि आग केवल ओखला में लगी है। उस आग से हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल्द ही यह आग हमारे क्षेत्र को भी चपेट में ले लेगी और तब हमें डरकर रहना होगा। तब हम उस दिन को कोसेंगे और खुद से ही यह सवाल करेंगे कि आखिर इनका विरोध क्यों नहीं किया गया। प्रवेश वर्मा ने अपने संबोधन में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिदों व कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो एक महीने के अंदर उनके क्षेत्र में सरकारी जमीन पर जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई अन्य उत्तेजक बयान दिए हैं।

प्रवेश वर्मा। जागरण

15 मंत्री, 66 विधायक करेंगे कांग्रेस के प्रचार अभियान की निगरानी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

जमीनी स्तर पर भले ही कांग्रेस का प्रचार अभियान अब तक जोर न पकड़ पाया हो, लेकिन अंतिम दौर में पार्टी ने प्रचार को मजबूती देने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद अब पार्टी ने चार राज्यों के विधायकों और तीन राज्यों के मंत्रियों को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी है। पर्यवेक्षक के तौर पर ये सभी वरिष्ठ नेता अभियान को असरदार बनाने के लिए काम करेंगे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ से 66 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इसी तरह मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 15 मंत्री भी आ गए हैं। इन सभी को दिल्ली चुनाव के प्रचार अभियान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हरियाणा से केवल स्टार प्रचारक ही लिए गए हैं, किसी को पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया। सूत्र बताते हैं कि एआइसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल और राज्यसभा सदस्य रहे जेडी सीलम ने सोमवार देर रात इन सभी की बैठक भी ली। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित एआइसीसी के वार रूम में हुई इस बैठक के दौरान कम समय में भी पार्टी के प्रचार को मजबूत और धारदार बनाने पर वृहद चर्चा हुई। बता दें कि सीलम राजनीति में आने से पहले कनार्टक कैडर के आइएएस अधिकारी रह चुके हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, सभी स्टार प्रचारकों की उपलब्धता के अनुरूप उनके शेडयूल को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रचार अभियान में सर्वाधिक मांग प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। प्रियंका इस बार पदयात्रा भी करेंगी ताकि दिल्ली वासियों के साथ संवाद किया जा सके। पार्टी नेताओं का प्रयास है कि सभी स्टार प्रचारकों की रैलियां, जनसभा और पदयात्रा कुछ इस तरह से तय की जाएं ताकि कम से कम सातों लोकसभा क्षेत्र कवर हो जाएं। संभावना जताई जा रही है कि अगले एक-दो दिनों में ही इस बाबत आधिकारिक शेडयूल भी जारी हो जाएगा।

भाजपा के झूठे प्रचार से नहीं पड़ेगा प्रभाव : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग से मिला और ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने भाजपा द्वारा सांप्रदायिक, धार्मिक उन्माद एवं हिंसा बढ़ाने वाले भाषणों तथा प्रचार सामग्री को लेकर विरोध दर्ज कराया। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन भी मौजूद थे।

पत्रकारों से बातचीत में सुभाष चोपड़ा ने कहा कि भाजपा ने विभिन्न समाचार पत्रों में झूठे और बदनाम करने वाले विज्ञापनों को प्रकाशन कराया है, वह आधारहीन है और आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस के विरुद्ध द्वेषपूर्ण, अप्रमाणिक एवं भ्रम पैदा करने की कोशिश है। चोपड़ा ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने भी सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी कर पहली ही दृष्टि में इसे मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह गैरकानूनी काम किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चोपड़ा व अजय माकन ने चुनाव आयोग से मांग की कि शीघ्र ही भाजपा एवं इसके लिए जिम्मेदार दोषी भाजपा नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि उनकी आपतियां को चुनाव आयोग ने ध्यान से सुना और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। चोपड़ा ने कहा कि भाजपा नेता अमित शाह सहित कई नेता भड़काऊ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे संभावित हार से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश और दिल्ली में कांग्रेस व धर्मनिरपेक्ष लोग दिल्ली नागरिक संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं तथा शाहीन बाग में आंदोलन करती महिलाओं एवं युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, उससे पूरी दिल्ली में भाजपा के विरुद्ध नाराजगी पैदा हो रही है। इससे घबराकर भाजपा ओछी राजनीति पर आ गई है। चोपड़ा और माकन ने कहा कि भाजपा के इन हथकंडों से कांग्रेस की न लोकप्रियता प्रभावित होगी और न ही विधानसभा चुनाव में जीत।

केंद्रीय चुनाव आयोग को भाजपा के खिलाफ ज्ञापन देकर वापस लौटते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा (बीच में सफेद कुर्ते में), पूर्व अध्यक्ष अजय माकन (बाएं से दूसरे गले में मफलर डाले हुए)। जागरण

नेशनल कैपिटल

जेवर एयरपोर्ट की एसपीवी ने किया सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बनाई गई स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए सोमवार को आवेदन किया है। जांच की औपचारिकता पूरी होने के बाद कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया जाएगा।

ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने 29 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिड जीती थी। कंपनी को अवार्ड लेटर जारी होने से पहले उसे एसपीवी के गठन व सिक्योरिटी क्लीयरेंस की शर्त को पूरा करना था। इसके लिए विकासकर्ता कंपनी को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। लेकिन कंपनी ने इससे पहले ही एसपीवी के गठन एवं सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन कर दिया है। विकासकर्ता ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एसपीवी गठित की है। एसपीवी कंपनी ने सोमवार को सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन कर दिया। जबकि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी पहले ही सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन कर चुकी है। दोनों कंपनियों का सिक्योरिटी कलीयरेंस होने के बाद लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता खुल जाएगा। एयरपोर्ट का मास्टर प्लान विकासकर्ता कंपनी तैयार कर रही है।

> एसपीवी ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन कर दिया है। ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी पहले ही सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन कर चुकी है। सिक्योरिटी क्लीयरेंस के आवेदन के लिए कंपनी को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था।
> –शैलेंद्र भाटिया, नोडल अफसर नियाल

मालिकाना हक के लिए कन्वेंस डीड देने का काम फिर शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को कन्वेंस डीड देने का काम डीडीए ने फिर शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इन कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक दिए जाने का जो कार्य बीच में ही रुक गया था, डीडीए ने मंगलवार से दोबारा शुरू कर दिया है। मंगलवार को डीडीए की ओर से दो लोगों को कन्वेंस डीड जारी की गई। दरअसल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली ने डीडीए को कन्वेंस डीड जारी करने की इजाजत दे दी है। माना जा रहा है कि चुनाव संपन्न होने तक अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब एक हजार लोगों को डीडीए की ओर से कन्वेंस डीड जारी कर दी जाएगी, जिसके आधार पर वे अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। मालूम हो कि छह जनवरी को दिल्ली में आचार संहिता लागू होने के बाद से संपत्ति के मालिकाना हक दिए जाने का काम रुक गया था।

गलत जानकारी दी तो दर्ज होगा आपराधिक मामला

जासं, नई दिल्ली : राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा एक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) व दिव्यांग श्रेणी (डीजी) के तहत 25 फीसद सीटों को भरने की प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू हो गई है। इस संबंध में पहली सूची 29 फरवरी को जारी होगी। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, दाखिले के लिए केवल वही आवेदन कर सकते हैं, जो इसके योग्य हैं। ऐसे में अभिभावकों को आवेदन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाखिला फॉर्म भरते समय अगर अभिभावक कोई भी गलत जानकारी भरते हैं और बच्चे का नाम ड्रॉ में आने के बाद अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं, तो उन पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फॉर्म भरने के समय केवल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी होती है। जबकि दाखिले के समय डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है।

लाइफस्टाइल

जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान भोजन और ड्रेस कोड से नहीं करते हैं भाजपा प्रत्याशी कोई समझौता

चुनावी भागदौड़ में भी आशीष सूद रखते हैं फिटनेस का ख्याल

प्रियंका दुबे मेहता, नई दिल्ली

जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आशीष सूद अपनी सक्रियता के लिए युवाओं में सराहे जाते हैं। वे चुनावी भागदौड़ में भी खुद को थकने नहीं देते। उनका कहना है कि आप फिट हैं, तो आपका मन आपको थकने नहीं देता। ऐसे में वे भले ही पूरी रात न सोएं, लेकिन सुबह जल्दी उठकर आधा घंटा फिटनेस पर लगाते हैं। इसमें दस मिनट का योग शामिल रहता है। इस समय ड्रेस कोड का भी वे विशेष ख्याल रखते हैं, और सोशल मीडिया से कदमताल उन्हें सबसे बड़ी जरूरत लगती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं।

साइकिलिंग और योग से रहते हैं फिट : कितनी भी व्यस्तता हो, आशीष दिन की शुरुआत साइकिलिंग और योग से ही करते हैं। चुनावों के दौरान वे दस मिनट की साइकिलिंग, दस मिनट का योग और दस मिनट भगवान की आराधना में बिताते हैं। उनका कहना है कि इन तीनों चीजों से उन्हें दिन भर की ऊर्जा मिल जाती है। साइकिलिंग के लिए वे घर पर ही बने जिम का उपयोग करते हैं और योग के लिए शांत कमरे में अपने आपको कुछ पल बंद रखते हैं।

इस समय केवल हल्का भोजन : आशीष शाकाहारी हैं और पौष्टिक भोजन को तरजीह देते हैं, लेकिन कई बार 'डाइट चीटिंग' कर लेते हैं। वे अपनी पसंद का राजमा चावल, छोले भठूरे और अन्य भोजन कई बार ले लेते हैं, लेकिन चुनावों के दौरान वे पूरी तरह से हल्के व ऊर्जादायक भोजन पर हैं। इस समय वे हरी सब्जी, हल्की दाल, स्प्राउट्स आदि पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि भोजन के प्रकार से ज्यादा उसके ग्रहण करने के समय पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऐसे में वे डिनर शाम साढ़े सात बजे गाड़ी में ही कर लेते हैं, ताकि अगले दिन के लिए वे अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ व ऊर्जावान रख सकें।

फॉर्मल से लेकर कैजुअल परिधानों तक का शौक : पहनावे में आशीष की पसंद व्यापक है, वे दिन में तीन से चार अवतार में नजर आ सकते हैं। जिमिंग के समय ट्रैक सूट, सामान्य तौर पर जींस टीशर्ट और योग करते हुए आरामदायक परिधानों को पहनना पसंद करते हैं। चुनावी सभाओं और पदयात्रा में सफेद कुर्ता पायजामा। आशीष का कहना है कि उनके कपड़ों का चयन उनकी दोनों बेटियां करती हैं। फुटवियर्स भी वे बच्चों की पसंद का ही पहनते हैं। पसंदीदा पोशाक में जैकेट, कुर्ता पायजामा और बंद गले का कोट है। गुलाबी और काला रंग उन्हें बेहद पसंद है। आशीष का परिवार इस समय उनका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। उनके बच्चे सोशल मीडिया के जरिए उन्हें सहयोग दे रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को वे क्वालिटी समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बच्चे उन्हें पूरा समय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों को पोस्ट करने से लेकर जानकारी का ट्रैक रखने में सहायता दे रहे हैं।

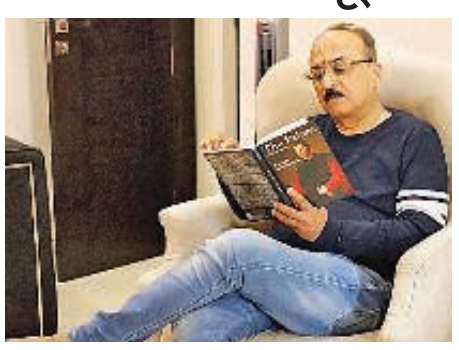

पुस्तक पढ़ते हुए आशीष सूद। जागरण

फिल्म, संगीत और किताबों का शौक : चुनावी गतिविधियों के बीच थोड़े फुर्सत के पल चुरा लेते हैं। इस दौरान वे आंखें बंद कर पुराने फिल्मी गाने सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा हरिओम शरण के भजन व दुर्गा चालीसा से उन्हें एनर्जी मिलती है। किताबों की पर्सनल लाइब्रेरी में बैठने मात्र से दिन भर की थकान उतर जाती है। उनका कहना है कि घर में उनकी पसंदीदा जगह हैं, जहां बैठने मात्र से दिलो दिमाग तरोताजा हो जाता है।

1000 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो में। इसका आयोजन पांच से नौ फरवरी के बीच होगा। भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या भी बढ़कर 165 हो गई है।

सीबीआइ ने इंटर्नशिप कार्यक्रमों के फर्जी दावों को लेकर किया सतर्क

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने मंगलवार को उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम से संबंधित फर्जी दावों वाले विज्ञापनों को लेकर लोगों को सतर्क किया है। इन फर्जी विज्ञापनों में इंटर्नशिप कार्यक्रम को सीबीआइ में नौकरी का अवसर बताया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इंटर्नशिप कार्यक्रम के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसा दावा करने वाली वेबसाइटों से सतर्क रहने को कहा है। एजेंसी ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है, जिनमें सीबीआइ का आला अधिकारी बनकर मासूम लोगों से पैसे ठगे गए हैं। सीबीआइ का यह बयान उसकी वेबसाइट पर दिए गए एक विज्ञापन के बाद आया है। विज्ञापन में कहा गया था कि सीबीआइ अकादमी और इंटर्नशाला डॉट कॉम वर्ष 2020 से सीबीआइ की इंटर्नशिप योजना प्रारंभ करने वाली हैं।

सीबीआइ की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ वेबसाइट पर गलत तरीके से इस इंटर्नशिप योजना को सीबीआइ में रोजगार का मौका बताया जा रहा है। फर्जी दावा किया जा रहा है कि प्रशिक्षुओं को पैसे और इंटर्नशिप पूरा होने के बाद सीबीआइ में नौकरी दी जाएगी।' एजेंसी ने साफ किया है कि इंटर्नशिप की छह-आठ हफ्ते की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

महिलाओं से धार्मिक भेदभाव पर दस दिन में पूरी होगी सुनवाई

संकेत ▸ विभिन्न धर्म स्थलों में प्रवेश में महिलाओं से भेदभाव का है मामला

सरकार ने कोर्ट को बताया, वकीलों की बैठक में नहीं तय हो पाए सुनवाई के सात कानूनी प्रश्न

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर महिलाओं से भेदभाव के मामले की नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद दस दिन में पूरी कर ली जाएगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि यह मामला पूरी तरह कानूनी है ऐसे में मामले की सुनवाई दस दिन में पूरी कर ली जाएगी। शीर्ष अदालत ने ये संकेत उस वक्त दिए जब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए वकीलों की बैठक में कानूनी प्रश्न तय करने पर आमराय न बन पाने की बात कही। कोर्ट इस मामले में तीन फरवरी को सुनवाई करेगा।

यह मामला केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, मस्जिद मजारों में

▸ इसमें सबरीमाला समेत मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, बोहरा मुसलिम व पारसी महिलाओं के कई मामले

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

महिलाओं के प्रवेश, बोहरा मुसलमानों में महिलाओं का खतना और पारसी महिलाओं के गैर पारसी से शादी करने पर अग्रहारी में प्रवेश पर पाबंदी से जुड़ा हुआ है।

हालांकि कोर्ट ने धार्मिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव के व्यापक प्रश्न को संवैधानिक अधिकारों की निगाह से परखने के लिए नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा था। कोर्ट ने व्यापक मुद्दे को समेटते हुए सात कानूनी प्रश्न तय किए थे। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इंद्रा जयसिंह, सीएस वैद्यनाथन, अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि वह 17 जनवरी को बैठक करके संविधान पीठ को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों को रिफ्रेम करने या उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत पर विचार करके सुनवाई के प्रश्न तैयार कर लें।

मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नौ न्यायाधीशों की पीठ के विचार के लिए प्रश्न तैयार करने पर वकीलों की बैठक हुई, लेकिन बैठक में सुनवाई के लिए प्रश्न तय होने पर आमराय नहीं बन सकी। तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही प्रश्न तय कर ले। तभी कोर्ट ने कहा कि जब भी यह मामला सुनवाई पर आएगा, मामले की सुनवाई दस दिन में पूरी कर ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि यह मामला पूरी तरह कानूनी है इसलिए दस दिन में सुनवाई पूरी हो जाएगी। इसमें इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

बजट सत्र से पहले बिरला और वेंकैया विभिन्न दलों संग करेंगे बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिरला ने 30 जनवरी की शाम व नायडू ने 31 को अपने आवास पर बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने भी 30 जनवरी की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों का उद्देश्य संसद के आगामी सत्र के दौरान सदन में कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करना है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ऐसी ही बैठक बुलाई है।

पिछले दो सत्रों के दौरान राज्यसभा में कामकाज की उत्पादकता 100 फीसद रही है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक के दौरान राज्यसभा के सभापति नायडू विभिन्न दलों के नेताओं से बजट सत्र के दौरान सकारात्मकता बनाए रखने का आह्वान कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। एक अंतराल के बाद इसका दूसरा हिस्सा दो मार्च से शुरू होगा और तीन अप्रैल तक चलेगा।

पाकिस्तान आतंकी संगठनों के खिलाफ कदम उठाए : राजनाथ

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को सरकारी नीति बनाने पर पाकिस्तान को जमकर फटकारा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए।

12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन में मंगलवार को रक्षा मंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि आतंकवादियों, उनकी विचारधारा और उनके वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उन्हें किसी भी तरह से सरकारी मदद न मिले। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश को छोड़कर अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिये क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। राजनाथ ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा का सच्चा रास्ता एक-दूसरे की संवेदनशीलता को समझने में है। एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न देना ही मूल सिद्धांत है।

उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में दक्षिण एशिया क्षेत्र को एकजुट होना होगा। मुंबई, पठानकोट, उरी और पुलवामा आतंकी हमले पड़ोसी देश के प्रायोजित आतंकवाद की बार-बार याद दिलाते हैं। पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ स्पष्ट रूप से कड़े कदम उठाने चाहिए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ एक देश (पाकिस्तान) की नीतियों के कारण दक्षेस

▸ रक्षा मंत्री बोले-आतंकियों व उनके वित्तीय नेटवर्क को खत्म करना जरूरी

▸ कहा-सिर्फ एक देश की नीतियों के कारण दक्षेस का पूरा उपयोग नहीं

नई दिल्ली में मंगलवार को रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में 12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एएनआइ

के पूरे सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया जा सका है। सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को फलीभूत किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति में पड़ोसी देशों से संबंधों को खासी अहमियत दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इसी नीति के तहत 2014 में दक्षेस और 2019 में शपथग्रहण समारोह में बिम्सटेक के नेताओं को आमंत्रित किया था। भारत ने अपनी समृद्धि को अपने पड़ोसियों से हमेशा साझा करने का प्रयास किया है। चूंकि यह अपने विकास और विस्तार के लिए भी जरूरी है।

राहुल ने केंद्र पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप

जागरण संवाददाता, जयपुर

▸ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने जयपुर में 'युवा आक्रोश रैली' को किया संबोधित

▸ कहा- देश की छवि खराब कर रहे हैं मोदी सीएए व बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया

जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस की युवा आक्रोश रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। प्रेट्र

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को जयपुर में युवा आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सीएए और एनआरसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हिंदुस्तान की सरकार हिंसा फैला रही है। पहले हिंदुस्तान की भाईचारे की छवि थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। मेक इन इंडिया, रेप इन इंडिया बन गया है ।

राहुल ने बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र सरकार एवं पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, पिछले साल देश के एक करोड़ युवाओं का रोजगार छिन गया, लेकिन मोदी मौन हैं। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है। यूपीए सरकार के समय देश की विकास दर नौ फीसद थी, जो अब पांच फीसद रह गई है। हम गरीबों को पैसा देते थे, जिससे बाजार की खपत बढ़ती थी और ग्रोथ होती थी। लेकिन, मोदी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि गरीब लोगों के पास पैसा जाएगा तो खरीद की क्षमता बढ़ेगी।

हिंदुस्तान की पूंजी है युवा : जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, हर देश के पास कोई ना कोई पूंजी होती है। अमेरिका के पास आधुनिक हथियार और सेना है। सऊदी अरब के पास तेल है, लेकिन, हिंदुस्तान के पास करोड़ों युवा हैं। युवा दुनिया को बदल सकते हैं । पहले पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान में निवेश करने आते थे, क्योंकि वे युवाओं पर भरोसा करते थे, लेकिन आज मैं दुख से कहता हूं कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपनी पूंजी बर्बाद कर रहा है। युवा जो इस देश के लिए कर सकते हैं, उसे सरकार और हमारे पीएम होने नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, चाइना का मुकाबला हिंदुस्तान के युवा ही कर सकते हैं । युवा जब पीएम मोदी से सवाल करते हैं कि देश की इमेज क्यों खराब की तो उन पर गोली चलाई जाती है । नोटबंदी और जीएसटी पर भी उन्होंने सरकार को घेरा।

एनआरयू लांच किया : राहुल ने युवक कांग्रेस के प्रोजेक्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ अनइंप्लॉयमेंट (एनआरयू) को लांच किया। इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। इसे लेकर देशभर में अभियान चलाया जाएगा। फिर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

भाजयुमो ने बेरोजगारों को 'भारतीय कांग्रेस बैंक' के बांटे चेक : भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने राहुल का अनूठा विरोध किया। भाजयुमो ने युवाओं को 'भारतीय कांग्रेस बैंक नाम से चैक बांटे। इन पर 28 जनवरी, 2020 की तारीख अंकित थी। इनमें 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता अंकित था।

देश पर बढ़ा कर्ज का बोझ : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक मंदी और बेरोजगारी पर पहले से हमलावर कांग्रेस ने बजट से ठीक पहले देश पर बढ़ते कर्ज को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार के साढ़े पांच साल के कार्यकाल में भारत का कर्ज 71 फीसद बढ़ गया है। इस तरह सरकार के आंकड़ों के हिसाब से इन पांच सालों में हर भारतीय पर 27,200 रुपये के कर्ज का बोझ बढ़ा है। कांग्रेस के मुताबिक अर्थव्यवस्था की डावांडोल हालत में कर्ज का बढ़ता बोझ बेहद चिंता की बात है। आर्थिक और रोजगार की खराब स्थिति को लेकर सरकार की घेराबंदी करने के कांग्रेस के अभियान के तहत प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि 2014 में भारत का कुल कर्ज 53 लाख करोड़ रुपये था जो 2019 में बढ़कर 91 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस तरह प्रति वर्ष कर्ज की दर 10.3 फीसद से बढ़ा है। वहीं विकास दर औसतन 5.3 फीसद रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कर्ज बढ़ने से अर्थव्यवस्था में नए निवेश नहीं होंगे जिससे नुकसान होगा।

केंद्र सरकार उल्फा-आई से शांति वार्ता करने के लिए तैयार : हेमंत

गुवाहाटी, प्रेट्र : बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद असम के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार उल्फा-आई गुट के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति की खातिर उन्होंने उल्फा-आई गुट के नेता परेश बरुआ से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की।

पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (नेडा) के संयोजक सरमा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर उल्फा-आई वार्ता के लिए तैयार है, तो केंद्र उनसे कहीं अधिक इच्छुक है। उन्होंने कहा, 'यह पहली बार है कि सरकार उल्फा-आई से वार्ता के लिए सार्वजनिक रूप से अपील कर रही है। यदि वे लोग बातचीत के इच्छुक हैं, तो केंद्र असम और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति की इच्छा के साथ इस पर आगे बढ़ेगा।'

राज्य के शिक्षा मंत्री सरमा ने बोडो समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सभी गुटों के साथ सोमवार को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा, 'इस संदर्भ में मैं बरुआ और उनके वार्ता-विरोधी गुट से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे एक सार्थक वार्ता में शामिल होने पर फिर से विचार करें। केंद्र और राज्य सरकार इस क्षेत्र में शांति चाहती है।'

उन्होंने कहा कि असम और मणिपुर के कुछ उग्रवादी संगठनों को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकतर उग्रवादी संगठन बातचीत कर रहे हैं। लेकिन, अगर हम इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं, तो वार्ता में सभी गुटों और संगठनों को शामिल होना होगा। सरमा ने कहा, 'अब केवल असम और मणिपुर में ही कुछ उग्रवादी गतिविधियों की सूचना है। इसलिए हम उनसे (विद्रोहियों) मुख्यधारा में शामिल होने और स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार के साथ चर्चा करने का अनुरोध कर रहे हैं।' उन्होंने जनता से भी अपील की कि वह उल्फा-आई से सरकार से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह करें। हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाला उल्फा का वार्ता-समर्थक गुट पहले से ही केंद्र के साथ बातचीत में शामिल है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन, स्थायी शांति के लिए, यह आवश्यक है कि सभी संगठन और उनके गुट बातचीत की मेज पर आएं।

▸ पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए परेश बरुआ से आगे आने की अपील

गुवाहाटी में मंगलवार को प्रेसवार्ता करते असम के शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा। एएनआइ

शांति समझौते से पूरी होगी बोडो और गैर बोडो लोगों की इच्छा

हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि बोडो शांति समझौते ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में रहने वाले बोडो और गैर बोडो लोगों की इच्छाओं को पूरा किया है। इससे पहले 2003 में हुए एक समझौते से जब बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था, तो गई गैर बोडो गांवों को इसमें शामिल कर लिया गया था और कई बोडो गांव इससे बाहर रह गए थे। सोमवार को हुए समझौते से इसे सही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार गैर बोडो गांवों के पास इससे बाहर आने का विकल्प होगा और परिषद से बाहर रह गए बोडो गांवों को इसमें शामिल किया जा सकेगा।

राम जन्म भूमि मामले की राह से हटाए कानूनी रोड़े

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

राम जन्मभूमि मामले के अदालती समाधान का श्रेय भी मोदी ने अपनी सरकार को दिया और कहा, दशकों से कानूनी राह में अटकाए जा रहे रोड़ों को उनकी सरकार ने हटाया। सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा देश देख और समझ रहा है। वोट बैंक के लिए मनगढ़ंत झूठ फैलाए गए हैं, यह भी देश जान गया है।

सैन्य सुधारों के लिए उठाए अहम कदम : पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी गुटों से हुए समझौते से बदले हालत और शांति बहाली की खासतौर पर चर्चा की। अपने कार्यकाल में सैन्य सुधार के लिए उठाए गए कदमों चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ के गठन, राफेल जेट खरीद, बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी दूर करने से लेकर वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने की चर्चा की। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत बेनामी संपत्ति कानून लागू करने और साढ़े तीन लाख से ज्यादा संदिग्ध मुखौटा कंपनियों को बंद करने और जनधन के जरिये योजनाओं के भ्रष्टाचार में कमी की बात भी कही।

प्रोपेगेंडा किया जा रहा, सरकार के फैसलों से पहुंची मोदी की प्रतिष्ठा को चोट : विदेशी मीडिया में हो रहे दुष्प्रचार की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिए उसने मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। मगर वह साफ करते हैं कि मोदी इन बातों के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। जितना ये लोग खुद को नहीं जानते, उससे ज्यादा मैं इनकी रग-रग और हर तिकड़म से वाकिफ हूं और वे किसी भी भ्रम में न रहें।

मनी लांड्रिंग मामले में पीएफआइ, एनजीओ के सात पदाधिकारी तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) और उससे जुड़े एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के सात पदाधिकारियों को तलब किया है। इन सभी के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच चल रही है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि केरल स्थित पीएफआइ और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारियों को इस मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारी के सामने बुधवार को पेश होने को कहा गया है।

पीएमएलए जांच के तहत इन पदाधिकारियों को ऐसे समय में तलब किया गया है, जबकि ईडी ने एक दिन पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून

▸ ईडी के जांच अधिकारी के सामने आज पेश होने का आदेश

▸ पीएफआइ और रिहैब इंडिया के खिलाफ 2018 में दर्ज हुआ था केस

(सीएए) के खिलाफ चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के पीछे पीएफआइ का हाथ है। इन प्रदर्शनों के लिए पीएफआइ की तरफ से पैसे दिए जाने के सुबूत भी ईडी को मिले हैं। हालांकि, पीएफआइ ने ईडी के इन आरोपों को आधारहीन करार दिया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा उसके संगठन को दबाने की कोशिश का यह हिस्सा है।

ईडी ने साल 2018 में पीएफआइ के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी रिहैब इंडिया के नौ बैंक खातों से किए गए लेन-देन की भी जांच कर रही है।

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े हैं पीएफआइ के तार

बता दें कि ईडी ने पीएफआइ, उससे जुड़े संगठनों और व्यक्तियों के 73 बैंक खातों की गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में इन खातों में 120 करोड़ रुपये जमा कराए गए। यह नहीं इतनी बड़ी रकम जमा कराए जाने के दिन ही या उसके एक-दो दिन के भीतर निकाल भी ली गई। पीएफआइ के दस और रिहैब इंडिया के पांच बैंक खातों में तो चार दिसंबर से छह जनवरी के बीच एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। ये पैसे उसी दिन या उसके एक-दो नि के भीतर निकाल भी लिए गए। पैसे उस-उस दिन निकाले गए जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

लोस चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट जाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली एक अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शिकायतें लेकर पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाली अनिवासी भारतीय याचिकाकर्ता से कहा, 'आप अनुच्छेद-32 की याचिका लेकर क्यों आई हैं? आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गईं?' इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पिछले लोकसभा चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया था और चुनावों में भ्रष्टाचार भी हुआ जिसकी वजह से भारत के लोगों के साथ छल हुआ। इस पर पीठ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है। आप अपनी याचिका वापस लीजिए और हाई कोर्ट जाइए।'

याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर उनसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाएगा तो यह न्याय नहीं होगा क्योंकि उन्हें यह केस लड़ने के लिए विदेश से आना पड़ा। इस पर पीठ ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि आपको बाहर से आना पड़ा, यह अन्याय हो गया? आप यहां खुद आई हैं। न्याय कानून के मुताबिक किया जाता है। हम इस मामले को स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपको इसे वापस लेने की अनुमति देते हैं और हाई कोर्ट जाइए।' जब याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि उनके पास इस बात के सुबूत हैं कि कैसे पिछले लोकसभा चुनावों में भारत के लोगों को छला गया, तो पीठ ने कहा, 'आप भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। आप तो यहां रहती भी नहीं हैं।' याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके माता-पिता भारत में रहते हैं। इसके बाद पीठ ने अदालत में मौजूद वकील से कहा कि वह याचिकाकर्ता को समझाएं कि वह कैसे हाई कोर्ट जा सकती हैं।

उलझन

रेलवे का तीन साल में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करने का लक्ष्य, वाराणसी के डीजल इंजन कारखाने में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का प्रस्ताव

पूर्ण विद्युतीकरण के साथ डीजल इंजन खपाने की चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तीन साल में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करने का रेलवे का लक्ष्य जहां सुखद है, वहीं यह नई मुश्किलें भी खड़ी करेगा। इसमें एक तरफ अनुपयोगी हो चुके डीजल इंजनों को खपाने की समस्या होगी, तो दूसरी तरफ डीजल इंजन कारखानों को इलेक्ट्रिक इंजन कारखानों में तब्दील करने की चुनौती होगी।

रेलवे के कुल 69,182 किलोमीटर के नेटवर्क में करीब 49 फीसद नेटवर्क ही विद्युतीकृत है। इसे सौ फीसद करने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016 शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की योजना बनाई थी। बाद में पीयूष गोयल ने 2021-22 शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए वार्षिक लक्ष्य बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि कुछ देरी के बावजूद यह लक्ष्य 2023-24 तक जरूर पूरा हो जाएगा। 2017 के बाद हर साल 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लाइनें विद्युतीकृत होने लगीं। वर्ष 2018-19 में 5,276 किलोमीटर लाइनों का

10,500 किलोमीटर सालाना के हिसाब से दो वर्षों में संपूर्ण लाइनों का हो जाएगा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण हुआ। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 7,000 किलोमीटर लाइनों के विद्युतीकरण की उम्मीद है। अगले दो वर्षों में सालाना 10,500 किलोमीटर के हिसाब से संपूर्ण लाइनों का विद्युतीकरण हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2018 में 12,134 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की थी।

ऐसे में जाहिर है कि 2024 तक देश में सारी यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां बिजली से चलने लगेंगी। लेकिन इस उपलब्धि के साथ कुछ समस्याएं भी आएंगी, जिनका समाधान रेलवे को करना होगा।

इनमें सबसे प्रमुख समस्या है डीजल इंजनों को खपाने की। विद्युतीकरण बढ़ने के साथ डीजल इंजनों की उपयोगिता खत्म होती जा रही है और उन्हें खड़ा करना पड़ रहा है। पिछले पांच सालों में तकरीबन ढाई हजार डीजल इंजन अनुपयोगी हो चुके हैं। अधिकारियों की मानें तो अगले दो सालों में डेढ़ हजार डीजल इंजन और उपयोग से बाहर हो जाएंगे। इस तरह रेलवे के समक्ष 4,000 डीजल इंजनों को खपाने की चुनौती होगी। एक डीजल इंजन की उम्र 25-30 वर्ष होती है। ज्यादातर इंजन 10-15 वर्ष पुराने हैं।

पिछले दिनों रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 'परिवर्तन संगोष्ठी' में भी यह मुद्दा उठा था कि इन डीजल इंजनों का क्या किया जाए। यदि इन्हें निर्यात नहीं किया गया, तो कबाड़ के भाव बेचना पड़ेगा। एक डीजल इंजन बनाने पर 10 करोड़ रुपये की लागत आती है। निर्यात में प्रत्येक इंजन के दो-ढाई करोड़ रुपये मिलने से 8,000-9,000 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं, जबकि कबाड़ में प्रति इंजन 50 लाख रुपये मिलना भी मुश्किल है।

दूसरी चुनौती डीजल इंजन कारखानों में बन रहे डीजल इंजनों को खपाने तथा भविष्य में इन्हें इलेक्ट्रिक इंजन कारखानों में तब्दील करने की है। फिलहाल रेलवे के दो ही कारखानों में डीजल इंजन बनाए जा रहे हैं। एक वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी डीएलडब्ल्यू में और दूसरे मढ़ौरा डीजल लोको फैक्ट्री में। डीएलडब्ल्यू पूर्णतया रेलवे का कारखाना है। लिहाजा वहां डीजल इंजनों को इलेक्ट्रिक इंजनों में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कुछ इंजन बनाए भी जा चुके हैं। आगे यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की योजना है। परंतु मढ़ौरा फैक्ट्री के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संयुक्त उद्यम समझौता होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा।

वहां 10 वर्ष में बनने वाले 4,500 हॉर्सपावर के 700 इंजनों और 6,000 हॉर्सपावर के 300 इंजनों को रेलवे को लेना ही पड़ेगा। परंतु रेलवे अधिकारी इससे जरा भी परेशान नहीं हैं। उनका कहना है कि विद्युतीकरण के बावजूद आपात उपयोग के लिए जीई के 1,000 हैवी हॉल डीजल इंजनों की रेलवे को जरूरत रहेगी। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर फ्रेट कॉरिडोर पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

1 माह का अतिरिक्त वेतन या अधिकतम 50 हजार रुपये कुंभ के कर्मिकों को देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आयोजन को सफल बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सौगात दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 जनवरी 2020

हेमंत कैबिनेट का विस्तार, सात मंत्रियों ने ली शपथ

राज्य ब्यूरो, रांची

- चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, जगरनाथ महतो, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख व मिथिलेश ठाकुर बने मंत्री
- झामुमो कोटे से पांच तथा कांग्रेस से दो और विधायक बने मंत्री
- राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ
- तीन विधायक पहली बार बने मंत्री, जोबा एकमात्र महिला मंत्री

झारखंड में सरकार के गठन के एक माह बाद मंगलवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो गया। हेमंत कैबिनेट के पहले विस्तार में सात मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शाम चार बजे राजभवन के खचाखच भरे बिरसा मंडप में सातों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

झामुमो कोटे से पांच विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, जगरनाथ महतो, जोबा मांझी और मिथिलेश ठाकुर शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले दो विधायकों में बन्ना गुप्ता तथा बादल पत्रलेख शामिल हैं।

हेमंत की टीम के मंत्रियों में जगरनाथ महतो, बादल पत्रलेख और मिथिलेश कुमार ठाकुर पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि अन्य को पहले भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल चुका है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में जगह पाने वाली एकमात्र महिला जोबा मांझी हैं। जोबा भी पूर्व की कई सरकारों में भी मंत्री रह चुकी हैं।

सुरक्षित रखा गया मंत्री का एक पद : हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री का एक पद अभी सुरक्षित रखा गया है। झारखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 पद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम तथा राजद के सत्यानंद भोक्ता 29 दिसंबर को ही शपथ ले चुके थे, जबकि सात ने मंगलवार को शपथ ली। इस तरह अब हेमंत मंत्रिमंडल में सीएम समेत कुल 11 मंत्री हैं। मंत्री का एक पद सुरक्षित रखे जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस मंत्री के एक और पद पर अड़ी हुई है। यह विवाद नहीं सुलझने के कारण ही एक जगह सुरक्षित रखी गई है। इसके पीछे एक सोच यह भी हो सकती है कि एक पद छोड़कर रखा जाए ताकि विपरीत परिस्थितियों के अनुसार उलटफेर में कोई परेशानी न हो।

रांची में मंगलवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के पहले गंगा जल से आचमन करते विधायक जगरनाथ महतो। साथ में विधायक बैजनाथ राम (सबसे बाएं), बादल पत्रलेख (बाएं से तीसरे) और प्रदीप यादव (सबसे दाएं)। जागरण

कांग्रेस के खाते में मंत्री के कुल चार पद

कांग्रेस के दो अन्य विधायकों के मंत्री पद पर शपथ लेने के बाद कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों की कुल संख्या चार हो गई है। वहीं, झामुमो के खाते में मंत्रियों के पांच पद गए हैं। एक पद राजद को मिला है। स्पीकर का पद भी झामुमो के पास है।

उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी पढ़ेंगे सोशल मीडिया के सुरक्षित प्रयोग का पाठ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- स्कूलों व डिग्री कॉलेजों में समझाया जाएगा कैसे करें प्रयोग
- आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने जारी किए निर्देश

सोशल मीडिया पर बिना जाने समझे टिप्पणी करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। दरअसल, बीते दिनों सीएए को लेकर बिना जाने समझे सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक व सद्भाव बिगाड़ने वाली टिप्पणी के कारण माहौल बिगड़ा, जिसके कारण कई लोगों पर आइटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे में नासमझी कितनी खतरनाक हो सकती है, यह उन्हें समझाया जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य विभाग भी जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को जागरूक करेंगे। इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आइटी) व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव (आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) आलोक सिन्हा की ओर से सभी विभागों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करें। इसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल व कॉलेजों में विद्यार्थियों को समझाया जाएगा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते समय सबके सम्मान का ख्याल रखें। कोई जरूरी नहीं कि हर पोस्ट पर जवाब दें। ऐसा पोस्ट जो प्रमाणिक नहीं है और दुर्भावना पूर्ण हो, उससे दूर रहें। फर्जी खबरों से बचें। हमेशा सही व प्रमाणिक तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। ऐसे पोस्ट जो समाज में सद्भाव बिगाड़ने वाले हैं, अश्लील हैं और दूसरे की निजता को भंग करते हैं, उनसे दूर रहें। यही नहीं सोशल मीडिया पर अपने पासवर्ड को बनाते समय उसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का प्रयोग करें। एडवोकेट प्रांशु अग्रवाल कहते हैं कि आइटी एक्ट की धारा 67 में पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार ऐसा कृत्य करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना व दस साल तक सजा हो सकती है।

न्यूज गैलरी

एनआरआइ कारोबारी थांपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली : रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार एनआरआइ कारोबारी सीसी थांपी का रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने थांपी को 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और जमानत अर्जी पर फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। ईडी का कहना था कि पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। अभी कई दस्तावेज और लोगों से आरोपित का सामना करवाना है। इसलिए फिर से रिमांड पर भेजा जाए। वहीं, थांपी के वकीलों ने अदालत में कहा कि अगर ईडी को लगता है कि दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो यह गलत है। (जासं)

छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा सीबीएसई

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक फरवरी से हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगा। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर विशेषज्ञों के साथ अकादमिक और स्कूल संबंधी या व्यक्तिगत परेशानियों को साझा करने का मौका मिलेगा। वहीं, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अगर विद्यार्थियों को किसी भी तरह का तनाव या शिकायत हो, तो वे काउंसलर से खुलकर बात कर सकते हैं। (जासं)

'विकास के मुद्दों पर राज्यों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार'

आश्वासन ▶ मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिलाया भरोसा

राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने और बकाया भुगतान शीघ्र करने की मांग की

नईदुनिया, रायपुर

केंद्र सरकार से राज्यों को फंड मिलने में हो रही देर का मुद्दा मंगलवार को मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में उठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति ही नहीं विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाला फंड भी समय पर नहीं आ रहा है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को भी बढ़ाने की मांग रखी। इस दौरान शाह ने कहा कि विकास के मुद्दों पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ खड़ी है। बैठक के बाद शाह भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से संवाद में कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को सीएए के विरोध का राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में मंगलवार को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। कमलनाथ ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को 42 से बढ़ाकर 50 फीसद करने की मांग उठाई। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि समेत विभिन्न योजनाओं का करीब 2300 करोड़ रुपये अब तक नहीं मिलने का मसला उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को मध्य क्षेत्र की परिषद से अलग करने की भी मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यहां नक्सलवाद है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं सात राज्यों से लगती हैं। सीमावर्ती राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां और समस्याएं लगभग एक समान हैं।

नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर होंगी बैंकिंग सेवाएं

बैठक में अमित शाह ने सभी गांवों, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों के गांव में पांच किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ी तो जिन शहरों में ज्यादा बैंक हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने राज्यों से पॉक्सो एक्ट के तहत जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समयावधि का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सीआरपीसी और आइपीसी में संशोधन के लिए राज्यों से सुझाव भी मांगे।

उत्तराखंड ने मांगी वित्तीय सहायता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने राज्य में प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए चार धामों के विकास, कुंभ मेले और पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन देने की मांग की। उन्होंने अपराधों से निपटने और अपराधियों से संबंधित जानकारी साझा करने में सीमावर्ती राज्य सरकारों का सहयोग मांगा। रावत ने खाद्यान्न की भंडारण क्षमता बढ़ाने, आइटी अधिनियम और एटीपीएस अधिनियम में संशोधन करने और ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैठक में हुए शामिल

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंगलवार को हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक के दौरान (बाएं से) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। एएनआइ

योगी ने बताई राज्य की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 30 लाख घरों का निर्माण, 2.5 लाख शौचालय और सौभाग्य योजना के तहत 1.20 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। योगी ने आइटी अधिनियम, पुलिस आधुनिकीकरण, आदि में संशोधन की आवश्यकता बताई। यह भी बताया कि पाक्सो एक्ट के तहत 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के सीएम ने मांगी किसानों के लिए सहायता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिक बारिश के कारण फसलों हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की मांग की। उन्होंने लंबे समय बाद बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सुझाव दिया कि वनों से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सभी राज्य सरकारों की एक अलग बैठक आयोजित की जा सकती है।

देवघर में बनेगा संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम में हुआ संशोधन

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना देवघर में होगी। इसका नाम बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया।

राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने, संस्कृत पढ़ाने वाले कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए संस्कृत भाषा के पठन-पाठन के उद्देश्य के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बाद संस्कृत के अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता अब इस विश्वविद्यालय के अधीन आ जाएंगे। पहले संस्कृत कॉलेजों की क्षेत्रीय अधिकारिता हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती थी।

राज्यपाल ने 18 अक्टूबर को अनुमति प्रदान की: इससे संबंधित संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल ने इस पर 18 अक्टूबर को अनुमति प्रदान की। विधि विभाग ने इसे संशोधन अधिनियम के रूप में 31 दिसंबर को अधिसूचित किया, जबकि इस वर्ष 22 जनवरी को इसे गजट में प्रकाशित किया गया। झारखंड विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरा झारखंड होगा।

एमपी पीएससी की भर्तियों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर रोक

नईदुनिया, जबलपुर

- मप्र हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश
- ओबीसी को 14 फीसद से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू
- 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी प्रभावित

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी कर मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की भर्तियों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने पीएससी की भर्तियों में पूर्व निर्धारित 14 फीसद ओबीसी आरक्षण से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू कर दी है। इससे एमपी पीएससी द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी।

याचिकाकर्ता आशिता दुबे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, आदित्य संघी, जाह्न्वी पंडित व सुयश ठाकुर ने पक्ष रखा, जबकि राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा खड़े हुए। पीएससी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रखा, जिन्होंने ओबीसी को 27 की जगह 14 फीसद ओबीसी आरक्षण दिए जाने के कोर्ट के रख के प्रति सहमति जताई।

नवंबर 2019 में जारी हुआ था विज्ञापन

एमपी पीएससी द्वारा नवंबर 2019 में एक विज्ञापन जारी किया गया। इसके जरिये द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद विज्ञापित किए गए। इसके बाद काफी संख्या में आवेदन भरे गए। नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कार भी हो चुके हैं। अंतिम चयन सूची जारी होना शेष है। इसके बावजूद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के स्थान पर बार-बार समय लिया जा रहा था। कोर्ट ने विगत सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से आवश्यक रूप से जवाब पेश किए जाने के निर्देश दिए थे। साथ ही अगली सुनवाई 28 जनवरी को निर्धारित कर दी थी। इसके बावजूद राज्य की ओर से पूर्ववत जवाब नदारद ही रहा। लिहाजा, कोर्ट ने सख्त रख अपनाते हुए आदेश पारित कर दिया।

क्या है मामला

याचिकाकर्ताओं ने मप्र शासन द्वारा जारी आरक्षण संशोधन अधिनियम-2019 को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन के जरिये ओबीसी के लिए पहले से निर्धारित 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसद आरक्षण किया गया था। याचिका में दलील दी गई संशोधन के कारण प्रदेश में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया है। इससे पीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए ओबीसी आरक्षण पूर्ववत लागू करने की व्यवस्था दी जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत के अनुरूप राज्य शासन द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से पूर्व नियमानुसार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श नहीं किया गया। बिना किसी सर्वेक्षण या फील्ड स्टडी किए ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया गया।

सरसंघचालक से विंध्याचल में मिले सरयू राय

राज्य ब्यूरो, रांची : हालिया विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच घंटों राष्ट्रीय मसले पर चर्चा हुई।

सरयू राय ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन यह भी कहा कि इस मुलाकात का राजनीतिक मायने निकालने का कोई तुक नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा में वे वापस लौट सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी शून्य संभावनाएं हैं। सरयू राय ने स्वयं मंगलवार की देर शाम इस बाबत ट्वीट भी किया। उन्होंने जिक्र किया है कि विंध्याचल के ब्रह्मवेता देवराहा हंस बाबा के गोसेवा आश्रम में माननीय सरसंघचालक जी से भेंट हुई। स्नेहपूर्ण वार्ता से पुरानी यादें ताजा हो गईं, अच्छा लगा। बाबा ने सबको साथ लेकर भारत को श्रेष्ठ बनाने का आशीष दिया।

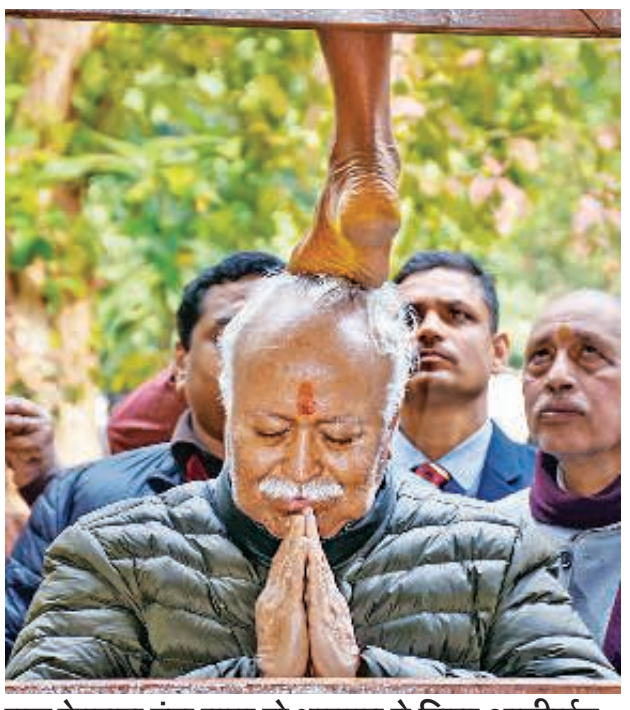

गुरु देवराहा हंस बाबा से भागवत ने लिया आशीर्वाद

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मीरजापुर स्थित विंध्याचल में ब्रह्मवेत्ता देवराहा हंस बाबा के आश्रम पहुंचे। इस दौरान गुरु देवराहा हंस बाबा से आशीर्वाद लेते भागवत। यहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेका और हनुमान मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। बाद में वह वाराणसी के लिए रवाना हो गए। प्रेट्र

बंगाल में अब शिक्षक गृह जिले में पा सकेंगे तैनाती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नई पहल करते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती उनके गृह जिले में करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने तथा आने वाले चुनाव के लिए नया समीकरण साधते हुए यह एलान किया है। शिक्षकों को यह सौगात देकर मुख्यमंत्री ने एक बड़े वर्ग को साधने का उपक्रम किया है।

सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन पूर्व मंगलवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिये यह महत्वपूर्ण घोषणा की। ममता ने शिक्षकों को मुख्य अभिभावक बताते हुए समाज और राष्ट्र में उनके अप्रतिम योगदान की चर्चा की। तर्क दिया कि स्कूल के अलावा शिक्षक अपने परिवार को भी समय दे सकें, इसलिए गृह जिले में तैनाती का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद देश व राज्य के सामूहिक विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की भागीदारी बढ़ेगी। शिक्षक और छात्र-छात्राओं के प्रति गर्व का भाव जाहिर करते हुए ममता ने कहा कि भविष्य के महान व्यक्तित्व के गठन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देश और समाज के विकास में भी उनका बड़ा योगदान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती पूजा का आदर्श समय होने की वजह से यह शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जताने का सही मौका है। इसलिए सरकार अब से राज्य के सभी शिक्षकों को उनके जिलों में स्थित विद्यालयों में तबादले का अवसर देगी।

शिक्षकों में खुशी की लहर : मुख्यमंत्री के इस कदम से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस घोषणा का शिक्षक संगठनों ने खुले दिल से स्वागत किया है। शिक्षकों का कहना है इस फैसले से उनका घंटों बर्बाद होने वाला समय बच जाएगा। घर से दूसरे जिलों में स्थित विद्यालयों में आने-जाने में ही उनका अधिकांश समय और ऊर्जा बर्बाद होती रही है। इससे मानसिक दबाव बना रहता है और परिवार को मिलने वाला समय यात्रा में बीत जाता है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

तल्खी

पंजाब के मुख्यमंत्री ने बुलाई लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की बैठक, प्रताप सिंह बाजवा ने बैठक से पहले फिर दिखाए तेवर

कैप्टन व बाजवा आज होंगे आमने-सामने

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- बाजवा ने कहा, पंजाब में अल्पसंख्यकों के कॉलेज मामले में हो रही नाइंसाफी
- सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली सरकार की छवि खराब हो रही

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले केंद्रीय बजट सत्र के मद्देनजर बुधवार को प्रदेश के लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में संसद में राज्य के मुद्दे उठाने को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद पहुंच रहे हैं। सबकी नजर राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो पर रहेगी, क्योंकि दोनों न सिर्फ पंजाब सरकार, बल्कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यों पर बेबाक टिप्पणी करते रहते हैं।

बाजवा ने बैठक से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरी तरफ पंजाब में ही अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज मामले में नाइंसाफी हो रही है। इससे प्रदेश सरकार की छवि भी खराब हो रही है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

बाजवा यह सवाल भी उठाते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी का दावा था कि शिअद-भाजपा सरकार ने थर्मल प्लांटों के साथ जो समझौते किए हैं या तो उनमें संशोधन किया जाएगा या उन्हें रद किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री मानसून सत्र में श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं। आखिर जो श्वेत पत्र दस दिनों में आ सकता है उसके लिए मानसून सत्र तक इंतजार करने का कोई तर्क नहीं बनता है। चुनाव में हमने जो वादे किए थे, या तो उनका आकलन हम नहीं कर पाए या हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। बाजवा के तेवर इस तरफ साफ संकेत कर रहे हैं कि बुधवार की बैठक निश्चित रूप से हंगामी हो सकती है।

प्रताप सिंह बाजवा फाइल

राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दूलो ने कहा, 'मैं बैठक में जाऊंगा। अभी यह नहीं पता कि एजेंडा क्या है, लेकिन पार्टी की नीति के अनुसार ही अपने विचार रखूंगा।' इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी होंगे।

झारखंड में स्कूल बंद रहने पर मिड डे मील के बदले मिलेगी राशि

राज्य ब्यूरो, रांची

- राज्य के सूखा प्रभावित 18 जिलों में मिलेगा इसका लाभ
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया आदेश

झारखंड के सूखा प्रभावित 18 जिलों में अवकाश के दिनों में सरकारी स्कूल बंद रहने पर मिड डे मील के बदले चावल व कुकिंग कॉस्ट की राशि छात्र-छात्राओं को मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत तीन फरवरी को स्कूलों में समारोह आयोजित कर बच्चों को यह राशि दी जाएगी। इसके तहत कक्षा एक से पांच के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम चावल तथा कुकिंग कास्ट के 4.48 रुपये के हिसाब से राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। वहीं, कक्षा छह से आठ के बच्चों को प्रतिदिन 150 ग्राम चावल तथा कुकिंग कास्ट के रूप में 6.71 रुपये मिलेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सूखाग्रस्त जिलों के लिए अवकाश की अवधि में कुल 25 दिनों का मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दी गई है। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रथम चरण में दुर्गा पूजा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा एंव चित्रगुप्त पूजा के अलावा रविवारीय अवकाश के अलावा दूसरे चरण में दस अन्य अवकाश के लिए मिड डे मील की राशि बच्चों को देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए न्यूनतम 50 फीसद उपस्थिति अनिवार्य किया गया है।

इन जिलों के बच्चों को लाभ

रांची, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा तथा देवघर।

45 दिन हो चुके हैं सीएए को संसद से पास हुए। 13 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। कई राज्यों में अभी भी पुराने नियमों से ही नागरिकता दी जा रही है, जिसमें कम से कम 12 साल का रहवास जरूरी है।

चीतों की सुनिए चीत्कार

110-120 किमी प्रति घंटा
रफ्तार

45-60 किग्रा
वजन

4 फुट
लंबाई

10-20 वर्ष
जीवनकाल

1 लाख
वर्ष 1900 में दुनिया में चीतों की आबादी करीब इतनी थी

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अफ्रीकी चीतों को लाने की मंजूरी तो दे दी लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाने वाला चीता विश्व के कुछ देशों को छोड़कर लगभग विलुप्त हो चुका है। जुओलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन और पैंथरा एंड वाइल्डलाइफ कंजरवेशन सोसायटी की रिपोर्ट की मानें तो इनकी करीब 91 फीसद आबादी खत्म हो चुकी है। पहले तो इंसानों ने इनका जमकर शिकार किया। इनके आवासों पर कब्जा कर लिया। खाने के लाले और प्रतिकूल हालातों के बीच इनकी चीत्कार निकलती रही। अब भी यदि इन जीवों की पुकार नहीं सुनी गई तो दुनिया सिर्फ तस्वीरों में इस खूबसूरत जीव को देख पाएगी। पेश है एक नजर

सिर्फ 7100 चीते बचे

जुओलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन और पैंथरा एंड वाइल्डलाइफ कंजरवेशन सोसायटी की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सिर्फ 7100 चीते बचे हैं। इस प्रजाति की 91 फीसद आबादी खत्म हो चुकी है।

यहां बची है इनकी संख्या

अंधाधुंध शिकार, तस्करी और प्राकृतिक आवास में गिरावट के चलते एशियाई चीते सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। एशिया में केवल ईरान ही है, जहां 50 चीते बचे हैं। इसके अलावा सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में चीते पाए जाते हैं। 20वीं सदी में चीते अफगानिस्तान, इजरायल जैसे देशों में भी मौजूद थे।

चीता एक खासियत अनेक

- बिल्ली के खानदान का यह जीव दहाड़ नहीं सकता। सिर्फ गुर्राता है।
- दौड़ते वक्त आधे समय यह हवा में रहता है।
- ये सिर्फ उजाले में शिकार करते हैं।
- मादा चीते को ज्यादा समय अकेले बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है।

चिंताजनक

- पिछले 16 वर्षों में जिम्बाब्वे में इनकी आबादी 1200 से घटकर 170 पहुंच गई।
- चीता के 77 फीसद प्राकृतिक आवास संरक्षित क्षेत्रों से बाहर मौजूद हैं। इसके चलते ये तस्करों और शिकारियों की नजर में आते हैं।
- संरक्षित आवास के अभाव में कई दफा रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं। वहां लोग इन्हें मार देते हैं।

शान ने छीने निशान

मुगलकाल के दौरान भारत में करीब एक हजार चीते थे। अंग्रेजों के आने के बाद इनका अंधाधुंध शिकार हुआ। देश के आजाद होने तक भारत में इनकी आबादी लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। साल 2000 से सरकार फिर से इन्हें लाने की कोशिशों में जुटी है।

दुनिया भर में चिंता

जर्सी पर चित्र : 2014 के फुटबाल विश्वकप और एशियन गेम्स में ईरान की जर्सी पर चीते का चित्र था। तभी लोग जान सके कि चीता खतरे में है।

क्लोन तैयार करने की योजना : 2000 के शुरुआती वर्षों में हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीकुलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ईरान से एशियाई चीते का क्लोन तैयार करने की योजना बनाई। भारत ने ईरान से चीते का एक जीवित जोड़ा भेजने का अनुरोध किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि यह संभव नहीं है तो उन्हें चीतों की कुछ जीवित कोशिकाएं लेने की ही अनुमति दी जाए। हालांकि ईरान ने दोनों शर्तों के लिए मना कर दिया।

आवास से बाहर प्रजनन : संख्या बढ़ाने के लिए तेहरान के एक बड़े पार्क में चीतों का उनके प्राकृतिक आवास से बाहर प्रजनन कराया जा रहा है।

विलुप्ति की वजहें

शिकार की कमी : चीतों को बचाने के प्रोटेक्शन प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या भूख मिटाने के लिए चीतों के शिकार में कमी की आई। लिहाजा पार्क में हिरण, चिंकारा और खरगोश को पालने का काम करना जरूरी।

आदमियों से सामना : चीता अक्सर अपने आवास से सटे रिहायशी इलाकों में शिकार के लिए चले जाते हैं। जहां किसान और उनके कुत्ते इन्हें मार देते हैं। कुत्तों का एक झुंड आसानी से इन्हें काबू कर सकता है।

सड़क दुर्घटनाएं : ईरान में पिछले 16 साल में करीब 20 चीता सड़क दुर्घटना के शिकार बने।

जंग ने घटाई संख्या : 1980 से 1988 तक चले ईरान-इराक युद्ध के दौरान देश की पश्चिमी सीमा पर व्यापक स्तर पर वन्य जीव मारे गए। इनमें एशियाई चीते भी शिकार बने। आज जंग तो नहीं है लेकिन दिक्कतें और बढ़ गई हैं।

बाघ और चीते में अंतर

चीता	बाघ
जमीन पर मौजूद सबसे तेज रफ्तार जीव चीता बड़ी बिल्लियों में सबसे कमजोर है।	शारीरिक बनावट में बाघ चीते के मुकाबले काफी लंबे और वजनी होते हैं।
लंबी और पतली टांगों वाले चीते के शरीर में पीले बालों के साथ छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं।	बाघ का शरीर नारंगी रंग का होता है जिस पर काले रंग की धारियां होती हैं।
इसमें आंखों से लेकर मुंह तक दोनों तरफ काली लाइनें भी होती हैं।	इसके गले से लेकर नीचे तक का हिस्सा कई जगह से सफेद रहता है।

अनियमितता के आरोपों में घिरा स्वराज भवन का अनाथालय

सख्त रुख ▶ यहां रहने वाली बच्चियों को दूसरी जगह रखने का आदेश

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट को लिखा पत्र

नीलू रंजन, नई दिल्ली

प्रयागराज स्थित स्वराज भवन। फाइल

गांधी परिवार से जुड़े प्रयागराज स्थित स्वराज भवन में चल रहे अनाथालय में घोर अनियमितता सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल अनाथालय में रह रही बच्चियों को जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। 'चिल्ड्रन नेशनल इंस्टीट्यूट' नामक इस अनाथालय का गठन 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

नौ जनवरी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस अनाथालय का दौरा किया। दौरे के बाद कानूनगो ने ट्वीट कर बताया कि 'स्वराज भवन स्थित चिल्ड्रन नेशनल इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा नियम 2016 का गंभीर उल्लंघन, संचालन में लापरवाही व अनियमितता संज्ञान में आई हैं।' ट्वीट में कानूनगो ने चार तस्वीरें भी लगाई हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि अनाथालय के बाथरूम में दरवाजे तक नहीं हैं। जबकि यहां पांच से 17 साल तक की 29 लड़कियां रहती हैं।

आयोग ने 15 जनवरी को प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को अनाथालय के बाथरूम में तत्काल दरवाजा लगवाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जब तक बाथरूम में दरवाजे नहीं लग जाते, तब तक बच्चियों को यहां से बाहर दूसरे स्थान पर रहने का बंदोबस्त किया जाए। साथ ही आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट को इन बच्चियों को जिला बाल समिति के सामने पेश कर निर्देश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है।

दरअसल, अनाथालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोपों पर सुनवाई करते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी छह हजार अनाथालयों के ऑडिट का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत लखनऊ स्थित मेसर्स एएमएस ने स्वराज भवन स्थित अनाथालय का भी ऑडिट किया। तीन महीने पहले एमसीपीसीआर को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई। इसके अनुसार इस अनाथालय में बच्चियों को लाने से पहले बाल कल्याण समिति के सामने पेश नहीं किया गया था, जो अनिवार्य है। इसके साथ ही इन बच्चियों से जुड़े रिकॉर्ड भी वहां नहीं मिले। बच्चियों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था भी खराब पाई गई। 29 बच्चियों की देखभाल के लिए सिर्फ तीन लोग रखे गए थे, जबकि नियमानुसार 10 लोगों को रखा जाना चाहिए था। 1947 में बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों के आने की आशंका के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस अनाथालय की स्थापना की थी। लेकिन पिछले 73 साल में यहां रहने वाली बच्चियों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की अनुपालन रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

शाहीन बाग धरने में पिस्तौल लेकर पहुंच गया युवक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे धरने के दौरान मंगलवार को उस वक्त खलबली मच गई जब 12 लोग घुस आए और एक तरफ की सड़क खोलने की मांग करने लगे। इनमें शामिल एक युवक पिस्तौल लहराते हुए धरना खत्म करने के लिए कहने लगा, जिससे अफरातफरी मच गई। धरने पर बैठी महिलाओं व अन्य के विरोध पर युवक वापस चले गए।

इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। शाहीन बाग धरने के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि ये लोग दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हो सकते हैं। चुनाव को देखते हुए ये लोग दोबारा हमला कर सकते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाहीन बाग व दिल्ली के अन्य धरनास्थलों में पहुंचने की अपील की गई। वहीं, स्थानीय लोग इसे प्रदर्शनकारियों को जुटाने का स्टंट भी बता रहे हैं।

लोगों का कहना है कि जैसे ही धरनास्थल पर लोगों की संख्या कम होने लगती है, प्रदर्शनकारियों की ओर से ऐसी अफवाह उड़ाकर लोगों से अधिक से अधिक संख्या में धरनास्थल पर पहुंचने की अपील की जाती है। कभी टेंट उखाड़ने तो कभी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों के आने की अफवाह फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को धरनास्थल पर पहुंचने की अपील की जाती है। ऐसे मैसेज पाकर लोग तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और धरने में बराबर भीड़ बनी रहती है। इसमें लोगों को बरगलाया जाता है और उन्हें झूठी कहानी बताई जाती है।

मस्जिद में कटती थी शरजील इमाम की रात, परिवार को थी पूरी जानकारी

जासं, जहानाबाद

▶ सब्जीबाग में छिपे होने की सूचना हो गई लीक, भेज दिया था जहानाबाद

भड़काऊ भाषण देने का आरोपी शरजील इमाम चार दिनों से वेश बदलकर अपने गांव काको में ही रह रहा था। उसकी रात मस्जिद में कटती थी। इधर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों से खाक छान रही थी।

पुलिस के भय से शरजील ने काफी हद तक अपना वेश बदल लिया था। उसने दाढ़ी छोटी कर ली थी। चश्मा लगाए बगैर पढ़ने-लिखने में उसे परेशानी होती थी, बावजूद इसके उसने चश्मा लगाना छोड़ दिया था। परिवार के लोगों को उसकी जानकारी थी। यही कारण है कि वे आत्मसमर्पण करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। शरजील गुरुवार को ही यहां आया था। यहां से कार से वह आसनसोल गया था। वहां संविधान बचाओ मोर्चा द्वारा आयोजित धरना में शामिल हुआ था। वापसी के दौरान गया के पास चाकंद बारा में भी धरना में वह शामिल हुआ। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत वह पुनः शनिवार को गांव आया था।

पूर्व वार्ड पार्षद की मदद से शरजील ने पटना में बिताई रात: देशद्रोह में आरोपित शरजील इमाम की टोह में दिल्ली क्राइम ब्रांच और इंटेलीजेंस ब्यूरो की टीम पटना के फुलवारीशरीफ और बारी पथ स्थित अपार्टमेंट पर नजर रख रही थी, लेकिन वह सब्जीबाग में मौजूद था। उसने एक पूर्व वार्ड पार्षद की मदद से सोमवार की रात पटना में ही बिताई थी। अगली सुबह मंगलवार को जब पूर्व वार्ड पार्षद का नाम सामने आने लगा तो अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए उसने शरजील को जहानाबाद भेज दिया। लेकिन, इसकी भनक पुलिस के खुफिया तंत्र को लग गई और मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस गुप्तचरों से पल-पल की जानकारी हासिल कर रही थी। इस बीच मंगलवार की सुबह पता चला कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ शरजील पटना सिविल कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर करेगा। एक पूर्व वार्ड पार्षद की मदद से वह सब्जीबाग में ठहरा हुआ है। इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो पूर्व पार्षद से पूछताछ की गई। ऐसे में उसने घबराकर अपने गुर्गों के साथ शरजील को जहानाबाद भेज दिया।

शरजील की मां बोली, निर्दोष है मेरा बेटा

शरजील इमाम की मां आस्फा अरशद ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा देशभक्त है। कोई पढ़ा-लिखा नौजवान भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता। आस्फा ने कहा कि हमें न्यायालय व अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे को बदनाम किया जा रहा है। इसकी जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगीं। कहा कि वह धरना पर जरूर बैठा था लेकिन किसी प्रकार की भड़काऊ बात नहीं कही थी।

शरजील पर पांच राज्यों में दर्ज है मुकदमा

प्रथम पृष्ठ से आगे

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भाषण देते हुए शरजील का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह असम को भारत से अलग करने की बात करता दिख रहा है। यह वीडियो 16 जनवरी का था। इससे पहले भी उसने दिल्ली के जामिया इलाके में 13 दिसंबर को भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद उसके खिलाफ 25 जनवरी को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। शरजील पर दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं।

कन्हैया से ज्यादा खतरनाक है शरजील का बयान : शाह

रायपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि शरजील का वीडियो देखिए, उसका बयान देखिए। उसने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया से भी ज्यादा खतरनाक बयान दिया है। शरजील चिकन नेक की तरह असम को भारत से काटने की बात कह रहा है। शरजील की सात पुस्तें भी असम को अलग नहीं कर पाएंगी।

सीएए, एनआरसी के विरोध में ममता की पेंटिंग

देश में सीएए और एनआसी को लेकर लोग बेहद रचनात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। ममता ने मंगलवार को कोलकाता में एक आर्ट कैंप में सीएए और एनआसी के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में पेंटिंग बनाई। उन्होंने दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। मेयो रोड पर गांधी मूर्ति के पास आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बंगाल के जोगेन चौधरी, शुभा प्रसन्ना समेत 42 विख्यात पेंटरों ने चित्रकारी के जरिए सीएए का विरोध जताया। ममता ने एक दुखियारी महिला की तस्वीर कैनवस पर उकेरी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके माथे पर सीएए लिखा था। प्रेट्र

बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठंड

जेएनएन, नई दिल्ली

▶ दिल्ली में आज भी बारिश के आसार, और बढ़ेगी ठंड

▶ लाहुल स्पीति में हिमखंड गिरने की आशंका को देख अलर्ट जारी

उत्तरकाशी में मंगलवार को हर्षिल के निकट : चांगथांग पहुंचकर पर्यटकों ने गंगोत्री हाईवे पर 25 मीटर ऊंचे हिमखंड के दीदार किए।

उत्तर भारत के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इससे ठंड तो बढ़ी ही है साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं, दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार को पूरे दिन रुक रुककर बारिश होती रही। इससे एकबार फिर ठंड बढ़ गई है।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को दिन भर दिल्ली में रुक-रुक कर बारिश होती रही। इससे एक बार फिर ठंडक का एहसास हो आया। बारिश का यह दौर बुधवार सुबह भी जारी रहेगा। इससे तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। हालांकि फरवरी के पहले सप्ताह से तापमान में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह भी है कि अब शीतलहर वाली स्थिति दोबारा लौटकर नहीं आएगी। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 22.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हिमाचल में बर्फबारी से आफत : हिमाचल में सोमवार आधी रात को मौसम ने फिर करवट बदली और बारिश के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मंगलवार को शिमला सहित मनाली, कुफरी और डलहौजी में बर्फ की चादर बिछ गई। ऊपरी हिमाचल में भारी हिमपात होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमपात की वजह से 272 सड़कें यातायात के लिए बद हो गई हैं। ऊपरी शिमला का संपर्क कट गया है।

उत्तराखंड में बर्फ से लकदक हुए पहाड़, मैदानों में बारिश : उत्तराखंड में सोमवार रात से बिगड़ा मौसम का मिजाज मंगलवार को और तल्ख हो गया। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में पहाड़ों पर रुक-रुक कर हिमपात का क्रम बना हुआ। मौसम विभाग ने इस दौरान 2000 मीटर की ऊंचाई तक के स्थानों पर हिमपात और बारिश की चेतावनी दी है।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे फिर बंद, हजारों वाहन फंसे : मौसम के एक बार फिर करवट बदलने से गुलमर्ग, राजौरी, पुंछ, बसंतगढ़, बनी, पत्नीटॉप और माता वैष्णो देवी के ऊपरी त्रिकुटा पर्वत पर भी बर्फ गिरी है। ताजा हिमपात और रामबन में भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। इससे जगह-जगह हजारों वाहन फंसकर रह गए हैं। वहीं, जम्मू संभाग को पुंछ के रास्ते कश्मीर संभाग से जोड़ने वाला मुगल रोड और श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से कई दिनों से बंद पड़ा है। मौसम के बिगड़े मिजाज से कश्मीर और लद्दाख का देश से सड़क संपर्क कटकर रह गया है। निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

देश का एक और विभाजन चाहती है कांग्रेस : वेदांती

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : पूर्व सांसद एवं कथा वाचक डॉ. राम विलास वेदांती ने कहा कि कांग्रेस देश का एक और विभाजन चाहती है। इसलिए कांग्रेस शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को साधने में जुटी हैं। वह यहां रेलवे स्टेडियम में सात दिवसीय महाशिवपुराण कथा कहेंगे।

सिविल लाइन में भाजपा नेता उमेश त्रिवेदी के आवास पर डॉ.वेदांती ने बातचीत में सीएए विरोध के सवाल पर कांग्रेस पर खूब हमले किए। बोले, कांग्रेस से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कांग्रेस को इस बात को भी समझना होगा कि यह देश अब जाग उठा है। अगले चुनाव में कांग्रेस का देश से सफाया हो जाएगा। मुस्लिम तुष्टीकरण का लाभ कांग्रेस न सोचे। देश में मुसलमानों ने ही राजनीति का लाभ उठाया है। अब दिल्ली का मुसलमान केजरीवाल के साथ है तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के साथ। पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौर में सरदार बल्लभ भाई पटेल का रूप माना। कहा, मोदी सरकार ने तीन तलाक और अयोध्या में 550 साल से लंबित रामजन्मभूमि प्रकरण में सरकारी पैरवी के मामले में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

गिर के शेरों को मप्र भेजने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की तरफ से दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में शीर्ष अदालत से गिर (गुजरात) के एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के एक वन्यजीव अभ्यारण्य में भेजने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गिर के शेरों को मध्य प्रदेश भेजने का मुद्दा पहली बार वर्ष 2013 में सामने आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दूसरी जगह भेजने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि महामारी व दावानल आदि आपदाओं में यह प्रजाति विलुप्त न हो जाए, इसलिए उनका दूसरा घर होना जरूरी है। शेरों को लेकर मध्य प्रदेश के आग्रह का गुजरात विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 500 से ज्यादा एशियाई शेरों के दूसरे घर के लिए ग्वालियर के श्योपुर जिले में स्थित पालपुर-कुनो वन्यजीव अभयारण्य को चुना था।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अनीता शेनॉय ने बहस के दौरान पीठ को बताया कि गिर से कुछ शेरों को मध्य प्रदेश में कुनो वन्य जीव अभयारण्य में बसाने की प्रक्रिया वर्ष 1989 में शुरू हुई थी। तब कुनो क्षेत्र को बसावट के लिए तैयार किया गया था। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नंदकर्णी ने पीठ को बताया कि यह मामला वर्ष 2018 में भी उठा था, जब खतरनाक वायरस के कारण गिर में कुछ शेरों की मौत हो गई थी। इसी मामले में शामिल एक अन्य वकील ने कहा कि कुनो राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। यह उद्यान बाघों का आश्रय है। अगर शेरों को कुनो ले जाया गया तो संघर्ष हो सकता है।

एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है हर यात्री को बोर्डिंग गेट तक पहुंचाना : सुप्रीम कोर्ट

▶ यात्रियों से की जाती है खुद बोर्डिंग गेट तक पहुंचने की अपेक्षा

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एयरपोर्ट पर चेक-इन करने के बाद यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे खुद बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ेंगे। हर यात्री को बोर्डिंग गेट तक पहुंचाना एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर यात्री को बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में परेशानी होती है तो वह एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ से मदद मांग सकता है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने कहा कि अगर यात्री ऐसा अनुरोध करता है तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संबंधित एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ यात्री को समय से बोर्डिंग गेट तक पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि बोर्डिंग पास जारी करने वाली एयरलाइन को यात्री के प्रति बरती गई लापरवाही, निष्क्रियता या कहें गलतफहमी के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ से समय पर मदद की मांग की गई हो।

शीर्ष अदालत ने यह फैसला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनाया। एनसीडीआरसी ने त्रिपुरा राज्य आयोग के खिलाफ एयरलाइन की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए इंडिगो को याचिकाकर्ता कल्पना रानी देबबर्मा और उनके परिवार को 20 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। देबबर्मा, उनके पति और उनके दो नाबालिग बच्चे 2017 में इंडिगो की फ्लाइट से कोलकाता से अगरतला जाने वाले थे। एयरलाइन ने उन सभी को बोर्डिंग पास जारी किए थे। देबबर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि एयरलाइन ने बिना सूचना दिए उनके परिवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जबकि वे एयरपोर्ट परिसर में ही थे। जब वह लिखित शिकायत दर्ज करने गईं तो एयरपोर्ट स्टाफ ने उनसे टिकट भी छीन लिए। लिहाजा उनके परिवार को होटल में रहना पड़ा और अगले दिन नए टिकट खरीदने पड़े। जबकि एयरलाइन का कहना था कि नियमित अंतराल पर कई उद्घोषणाएं की गई थीं, लेकिन यात्रियों ने समय पर बोर्डिंग गेट पर रिपोर्ट नहीं किया।

हाई कोर्ट ने गानों में अश्लीलता व हिंसा पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाबी व लोक गीतों में अश्लीलता और हिंसात्मक दृश्यों पर नकेल कसने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुखों से अब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। पंडित राव धरेनवर की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका पर जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकारी वकील सिर्फ संबंधित विभागों से मिले निर्देश अदालत में पेश न करें। धरेनवर ने पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता को प्रतिवादी बनाया है। धरेनवर ने मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में गायक करण औजला ने ऐसे गीत पेश किए, जिनमें हथियारों का महिमा मंडन किया गया। जस्टिस गुप्ता ने इस मामले में अतिरिक्त गृह सचिव को प्रतिवादियों में शामिल करते हुए 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा था कि गानों में शराब, हथियारों या ड्रग्स के महिमा मंडन से बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाई कोर्ट ने 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में न देखने दिए जाने के भी आदेश दिए थे। शिक्षा संस्थानों के पास अश्लील पोस्टरों के लगाए जाने पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा न होने पर पुलिस प्रमुखों को जिम्मेदार माना जाएगा। केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन के वकीलों की अनुपस्थिति पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई।

क्या था याचिका में : याचिकाकर्ता पंडित राव धरेनवर ने कहा था कि यू-ट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे गीत युवाओं को आसानी से उपलब्ध हैं। इनसे युवाओं में हिंसात्मक प्रवृत्ति और अश्लीलता बढ़ती है। उन्होंने ऐसे गीत हटाए जाने की भी मांग की थी।

30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि और मुख्य खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी से जिला खनिज निधि बनाई गई है मध्य प्रदेश में। इसे पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अधोसंरचना पर खर्च करने का प्रावधान है। अब इसे पर्यटन और गोशालाओं पर भी खर्च किया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 जनवरी 2020

न्यूज गैलरी

पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को टायलर पुरस्कार

संयुक्त राष्ट्र : प्रख्यात भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सद्भावना दूत पवन सुखदेव को 'हरित अर्थव्यवस्था' पर उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 2020 का टायलर पुरस्कार दिया जाएगा।

पवन सुखदेव। फाइल

इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 59 वर्षीय सुखदेव जीवविज्ञानी ग्रेशन डेली के साथ यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सुखदेव ने अपने कार्यों से न केवल पर्यावरण को क्षति के आर्थिक परिणामों से अवगत कराया, बल्कि कॉरपोरेट एवं राजनीतिक नीति-निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लगातार प्रयास किया।

सुखदेव और ग्रेशन डेली को एक मई को यहां एक निजी कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के तहत दोनों को एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा और वे दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि साझा करेंगे। सुखदेव यूएनईपी की हरित अर्थव्यवस्था पहल के प्रमुख एवं विशेष सलाहकार रह चुके हैं। वह अभी वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड के प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यह पुरस्कार यूएनईपी और 'पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता की अर्थव्यवस्था यानी टीईईबी' को अंतरराष्ट्रीय मान्यता है।' टीईईबी यूएनईपी की मेजबानी वाला एक वैश्विक अध्ययन है। यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की ओर से दिया जाता है। (प्रेट्र)

बंगाल में तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने उत्तर 24 परगना जिले में अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे तीन बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की ओर से बताया गया कि पेट्रापोल थाना अंतर्गत बीओपी कल्याणी इलाके से 158वीं बटालियन के जवानों ने सोमवार देर रात दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जब वे बांग्लादेश की सीमा में जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बशीरहाट थाना अंतर्गत बीओपी घोजाडांगा इलाके से 153वीं बटालियन के जवानों ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों घुसपैठियों ने बताया है कि वे दलालों की मदद से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। आगे की कार्रवाई के लिए बीएसएफ ने तीनों बांग्लादेशी को स्थानीय थाने को सौंप दिया है। (जासं)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को तराशेंगी कंपनियां

पहल ▶ पहली बार ऑनस्पाट अप्रेंटिसशिप मेला, तुरंत होगा पंजीयन

मार्च-अप्रैल में लगने वाले मेले के साथ बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग की कार्ययोजना तैयार

शशांक शेखर भारद्वाज, कानपुर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को घर में ही तराशने की तैयारी कर रहे बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग (बीओएटी) के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा कर रहे छात्रों का हुनर तराशने के लिए जम्मू-कश्मीर की सौ से अधिक कंपनियां तैयार हो गई हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बोर्ड के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के निदेशक की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल को कंपनियों ने यह सहमति दी है। फरवरी में ही इस संबंध में करार पूरा हो जाएगा। अब बोर्ड मार्च व अप्रैल में एक-एक ऑनस्पाट अप्रेंटिसशिप मेला लगाएगा। कंपनी व भावी इंजीनियर आमने-सामने होंगे। कंपनियां मौके से ही प्रशिक्षु का चयन कर लेंगी। निरंतरता बनी रहे, इसलिए दोनों राज्यों में सहायक निदेशक व अन्य स्टाफ तैनात कर बोर्ड का कार्यालय भी खोला जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर बीओएटी ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं का हुनर तराशने और उद्यमिता विकास की ललक जगाने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की है। पहले चरण में बोर्ड अप्रेंटिसशिप कराएगा। दूसरे चरण में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम विकास संस्थान उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण का कार्य पूरा करने के लिए बोर्ड के उत्तर क्षेत्र के निदेशक एसके मेहता, दिल्ली के सहायक निदेशक संदीप कुमार व अन्य अधिकारी 18 से 25 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर में घूमे। वहां निदेशक वाणिज्य एवं उद्योग और निदेशक तकनीकी शिक्षा के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद बरी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, गंगयाल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सांबा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, डिगियाना इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ बैठक की गई। यहां की सौ से अधिक कंपनियों ने अप्रेंटिसशिप की सहमति दे दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को मिलने वाले मानदेय का आधा-आधा खर्च कंपनी और बोर्ड के जिम्मे होगा।

सहमति देने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम

ल्युपिन, सन फार्मा, हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज लिमिटेड, सिद्धि इंटरप्राइजेज, एथिकेयर लेब्रोरेट्रीज, कैडिला, यूपीएल लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड्स, कांधारी ब्रेवरेजेस यूके पेंट्स, बर्जर पेंट्स आदि।

बोर्ड के कानपुर रीजन में शामिल हैं दस राज्य

कानपुर में बोर्ड का रीजनल कार्यालय है। इस कार्यालय का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक है।

> जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में ऑनस्पाट मेला लगाकर अप्रेंटिसशिप काउंसलिंग होगी। कंपनियां मौके से प्रशिक्षु का चयन करेंगी। फरवरी में कंपनियों से करार होगा।
> – एसके मेहता, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग, नार्थ रीजन

जम्मू-कश्मीर में एलओसी और भीतरी इलाकों में हालात नियंत्रित

नई दिल्ली, प्रेट्र : उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के भीतरी इलाकों और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आस-पास हालात नियंत्रण में हैं। वह उप सेना प्रमुख पाद पदभार करने के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेना सभी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उप सेना प्रमुख ने कहा, 'पिछले साल युद्ध विराम उल्लंघन के मामले ज्यादा हुए। हम सीमा पार से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।' उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा क्षेत्रों में उपकरणों और गोला-बारूद की भारी कमियों को दूर करना और क्षमता विकास उनकी प्राथमिकता होगी। सैनी ने कहा, 'चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे पद का गठन हुआ है। आगे उसके साथ सेना मुख्यालयों को जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।' ले. जनरल सैनी इससे पहले तक दक्षिणी कमान के प्रमुख थे। उनकी शिक्षा कपूरथला स्थित सैनिक स्कूल से हुई है और उसके बाद वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में शामिल हुए थे। जून, 1981 में उन्होंने जाट रेजिमेंट के साथ सेना की नौकरी शुरू की थी। ले. जनरल सैनी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के ट्रेनिंग सेंटर में हथियारों की ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। वह भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट और नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज में वरिष्ठ पद पर भी रह चुके हैं।

अब शेर-ए-कश्मीर नाम से नहीं दिए जाएंगे वीरता पुरस्कार

जागरण संवाददाता, जम्मू

- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पदकों का नाम बदला
- पूर्व सीएम शेख अब्दुल्ला के नाम पर था पुरस्कार, नेकां ने जताया एतराज

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पुलिस वीरता पुरस्कार और उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से शेर-ए-कश्मीर नाम हटा दिया है। शेर-ए-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के संस्थापक शेख अब्दुल्ला को कहा जाता था। कुछ दिन पहले सरकारी कैलेंडर से भी शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी को हटा दिया था। शेर-ए-कश्मीर मेडल उत्कृष्ट सेवाओं और वीरता के लिए दिया जाता था। इस बार दोनों मेडल से शेर-ए-कश्मीर नाम हटा दिया गया है। नेशनल कांफ्रेंस ने राज्य प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है।

गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने गत सप्ताह एक आदेश में कहा था कि शेर-ए-कश्मीर पुलिस वीरता पदक और शेर-ए-कश्मीर पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक को अब जम्मू-कश्मीर पुलिस वीरता पदक और जम्मू-कश्मीर पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक ही पढ़ा, लिखा और पुकारा जाए। पहले वीरता पदक का नाम जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के संस्थापक और एकीक्रत जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के सम्मान में था।

वीरता पदक का नाम बदलने पर नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक पीर आफाक अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन राजनीतिक दुराग्रह से काम कर रहा है। वीरता पुरस्कार से शेर-ए-कश्मीर का नाम हटाना इतिहास से छेड़खानी है। यह जम्मू कश्मीर की राजनीति की प्रत्येक पहचान को मिटाने की साजिश है।

केंद्र सरकार भारतीय संविधान और इसके संघीय ढांचे के प्रति आस्था रखने वालों को ही निशाना बना रही है। वह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के प्रति दुराग्रह रखती है। इसलिए उनसे जुड़ी हर चीज को नष्ट करने पर तुली है। शेख अब्दुल्ला का व्यक्तित्व किसी पदक या पुरस्कार का मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने जिस जम्मू-कश्मीर की परिकल्पना की थी, उसे आज क्षेत्रीय व धार्मिक संकीर्णता के बंधन में बांधकर दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन आज भी 30 साल पहले इस दुनिया से कूच कर गए नेता से डरते हैं।

एजीएच ने खालिद इब्राहिम को बनाया कमांडर

नवीन नवाज, जम्मू

- सुरक्षा एजेंसियों ने किया था आतंकी संगठन के खत्म होने का दावा
- तीन महीने बाद घोषित किया नया कमांडर, एजेंसियों को भी नहीं अधिक जानकारी

अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवात-उल-हिंद (एजीएच) ने एक बार फिर कश्मीर में अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। एजीएच ने लगभग तीन महीने बाद अपने नए कमांडर का एलान कर दिया है। इस बार खालिद इब्राहिम को एजीएच की कमान सौंपी गई है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस आतंकी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सरेंडर नहीं किया तो जल्द ही यह भी मारा जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में एजीएच की नींव हिजबुल मुजाहिदीन से अलग होने वाले आतंकी जाकिर मूसा ने वर्ष 2017 में रखी थी। मूसा 23 मई 2019 को दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मूसा मारा गया था। उसकी मौत के बाद अलकायदा ने एजीएच की कमान कमांडर हमीद ललहारी उर्फ हारुन अब्बास को सौंपी थी।

पुलवामा का रहने वाला ललहारी 22 अक्टूबर को अवंतीपोरा के पास अपने दो साथियों संग सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य में अलकायदा और एजीएच के खत्म होने का एलान किया था। वहीं, ललहारी की मौत के बाद एजीएच ने भी किसी कमांडर का एलान नहीं किया था। ऐसे में ललहारी की मौत के लगभग तीन महीने बाद एजीएच के मीडिया विंग अल हूर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर खालिद इब्राहिम को नया कमांडर बनाने का एलान किया है। अल हूर के मुताबिक खालिद इब्राहिम के साथ उसके दो डिप्टी कमांडर भी तैनात किए गए हैं।

ढूंढे भी नहीं मिल रहे आतंकी कैडर

सूत्रों के अनुसार, एजीएच को इस समय कश्मीर में कैडर तक नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि नया कमांडर बनाने में इतना समय लगा। हालांकि धार्मिक विचारधारा के आधार पर उसका समर्थन करने वाले कई हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एजीएच से जुड़े या उससे सहानुभूति रखने वाले आतंकियों की तादात लगभग एक दर्जन हो सकती है। इसके अलावा यह संगठन आनन-फानन में अपने कमांडरों का एलान करने के बजाय पूरे हालात का जायजा लेने के बाद किसी आतंकी को संगठन की कमान सौंपता है।

अगर कश्मीर में है तो जल्द मारा जाएगा

एजीएच द्वारा खालिद इब्राहिम को नया कमांडर बनाए जाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां खालिद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रही हैं। कोई भी वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अभी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दावा किया कि खालिद अगर कश्मीर में है तो वह जल्द ही मूसा और ललहारी की तरह मारा जाएगा।

कश्मीर के बारामुला जिले में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- हथियार भी बरामद किए गए, अपने संपर्क सूत्र से मिलने पहुंचा था आतंकी
- बांदीपोरा निवासी है आतंकी, साथियों की तलाश जारी

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के अंद्रगाम पट्टन में सुरक्षाबलों ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को हथियारों के साथ दबोच लिया। उसके अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बारामुला, बांदीपोरा और सोपोर में कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया है।

पुलिस को अपने सूचना तंत्र से पता चला था कि लश्कर का आतंकी 19 वर्षीय साजिद फारुक डार उर्फ अदनान अपने किसी संपर्क सूत्र से मिलने के लिए पट्टन के अंद्रगाम इलाके में आया हुआ है। पुलिस ने उसी समय सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर घेराबंदी कर ली और तलाशी अभियान चलाया।

कुछ ही देर में सुरक्षाबलों ने आतंकी के ठिकाने का पता लगा लिया और साजिद फारुक डार को गिरफ्तार कर लिया। साजिद बांडीपोरा जिले के गुंड का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि साजिद के पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी मिला है। उससे मिले सुरागों के आधार पर पट्टन, सोपोर, बांडीपोरा और बारामुला में सक्रिय लश्कर के आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

इस साल दस आतंकी पकड़े : साजिद की गिरफ्तारी के साथ ही इस साल कश्मीर घाटी में पकड़े गए आतंकियों की संख्या 10 हो गई है। इन आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी नवीद बाबू भी शामिल है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकरोधी अभियान में तेजी ला रहे हैं।

पूरी रणनीति के साथ आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए खुफिया तंत्र को अधिक सक्रिय किया गया है। इसी का नतीजा है कि जब भी कोई आतंकी कहीं निकलता है तो उसे दबोच लिया जाता है।

सीआरपीएफ ने देविंदर मामले के बाद कराया मेगा ऑडिट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नवनियुक्त महानिदेशक एपी महेश्वरी ने कहा कि सीआरपीएफ ने किसी भी आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति से निपटने के लिए अपने तीन लाख से अधिक कर्मियों का मेगा ऑडिट कराया है। यह कदम जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह की आतंकवादियों के साथ संलिप्तता सामने आने के बाद उठाया गया है।

महानिदेशक नियुक्त होने के बाद मंगलवार को पहली बार कादरपुर स्थित सीआरपीएफ के समूह केंद्र पहुंचे एपी महेश्वरी ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू कश्मीर में डीएसपी देविंदर सिंह की आतंकवादियों के साथ संलिप्तता एक बेहद शर्मनाक घटना है। जम्मू कश्मीर में 70 हजार सीआरपीएफ जवान आतंकवादी घटनाओं से मुकाबला करने व कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तैनात हैं। सीआरपीएफ में तीन लाख से ज्यादा कर्मियों का मेगा ऑडिट कराया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी एक घटना को ब्रांड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

विधायक की हत्या में एनएससीएन-आइएम आतंकियों पर आरोपपत्र

- पिछले साल 21 मई को आतंकी संगठन ने हमला कर 11 लोगों की कर दी थी हत्या
- अरुणाचल के थे विधायक, एनआइए ने दायर किया आरोपपत्र

ईटानगर, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक की हत्या मामले में आतंकी संगठन एनएससीएन (आइएम) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इस हमले में 10 अन्य लोगों भी मारे गए थे।

एनआइए की तरफ से जारी बयान के अनुसार, लुक्किन मशंग्वा, जय किशन शर्मा, यांग्टे जोसाहम और नापोंग जेनपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। 21 मई 2019 को तिरप जिले में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) के सशस्त्र आतंकियों ने खोंसा पश्चिम विधायक तिरंग अबोह के काफिले पर हमला कर दिया था। इस मामले में एजेंसी ने पिछले साल जून में रिपोर्ट दर्ज की थी। विधायक का काफिला असम के डिब्रूगढ़ से खोंसा जा रहा था।

बयान के अनुसार, 'जांच में यह साबित हुआ है कि आतंकी संगठन एनएससीएन (आइएम) के सदस्यों ने आतंकी हमले का षड्यंत्र रचा था, जिसमें खोंसा विधायक तिरंग अबोह व 10 अन्य मारे गए थे। यह भी पता चला कि विधायक अबोह तिरप जिले में एनएससीएन (आइएम) की विकास विरोधी और उगाही जैसी गतिविधियों का विरोध करते थे, इसलिए आतंकी संगठन ने वारदात को अंजाम दिया था।' जांच में यह भी पता चला कि एनएससीएन (आइएम) के स्वघोषित मेजर जनरल एबसोलम के नेतृत्व में मशंग्वा, जोसाहम और जेनपी ने आतंकी संगठन बनाया था। शर्मा इस संगठन को आर्थिक मदद देता था।

जांच एजेंसी ने बताया कि एनएससीएन (आइएम) अपनी गैरकानूनी गतिविधियों का विरोध करने के लिए विधायक व उनके समर्थकों को पहले भी कई मौकों पर धमका चुका था। इसी दुश्मनी में 21 मई 2019 को आतंकी संगठन के सदस्यों ने विधायक के काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से हमला बोला था, जिसमें कुल 11 लोग मारे गए थे।

अभिजीत बनर्जी ने टेनिस में आजमाया हाथ

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता क्लब में टेनिस में अपना हाथ आजमाया। क्लब के आजीवन सदस्य बनर्जी ने बताया कि वे खेलों, खासकर टेनिस और टेबल टेनिस के शौकीन हैं। वहीं, मंगलवार को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अभिजीत बनर्जी को डी लिट की उपाधि प्रदान की। एएनआइ

बंगाल में जादवपुर के बाद सीयू में हुआ राज्यपाल का विरोध

जागरण संवाददाता, कोलकाता

जादवपुर विश्वविद्यालय में विरोध के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक बार फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) के दीक्षा समारोह में विरोध का सामना करना पड़ा। मंगलवार को शहर के काजी नजरुल मंच ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक दीक्षा समारोह में भाग लेने पहुंचे राज्यपाल को छात्रों के एक समूह ने शामिल नहीं होने दिया। इसके बाद, राज्यपाल परिसर से चले गए। इस घटना के बाद उनके बिना ही सीयू का दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। धनखड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं।

राज्यपाल के दोपहर 12:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचे। इसके बाद छात्रों ने काले झंडे दिखाए और 'गो बैक' के नारे लगाए। वहीं, कुछ छात्रों ने हाथों में 'नो सीएए' और 'नो एनआरसी' के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बीच धनखड़ ने नजरुल मंच के ग्रीन रूम में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी से मुलाकात की, जहां उन्होंने मानद डी लिट पर हस्ताक्षर किए। वहीं, कार्यक्रम शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले छात्रों का एक अन्य समूह मंच पर आ गया और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की, इसके बाद धनखड़ आयोजन स्थल से करीब डेढ़ बजे निकल गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि धनखड़ (भाजपा नीत) केंद्र के प्रतिनिधि हैं, जो कलकत्ता विवि के दीक्षा समारोह के लिए मंच पर उपस्थित होने के हकदार नहीं हैं।

इस दौरान कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी छात्रों को इस बात के लिए मनाती हुई नजर आईं कि वे अपना विरोध बंद कर दें। बाद में उन्होंने घोषणा की कि राज्यपाल आयोजन स्थल से चले गए हैं।

नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी को डी लिट की उपाधि: कलकत्ता विवि ने इस समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी लिट की उपाधि दी। इस मौके पर विवि कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल के इतिहास का अविस्मरणीय क्षण है। हमें अभिजीत की उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है।

बदलेंगे दिन

राज्य के समग्र विकास के लिए पैकेज पर गंभीरता से सोच रही केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रियों और उनके साथ आए अधिकारी तैयार करेंगे विस्तृत रिपोर्ट

'थ्री-ई' के साथ विकास की राह चलेगा जम्मू-कश्मीर

राज्य ब्यूरो, जम्मू

केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को थ्री-ई (एजूकेशन, इम्प्लायमेंट और इम्पावरमेंट) पैकेज देकर विकास की राह पर सरपट दौड़ाना चाहती है। यहां के लोगों को समग्र विकास का यकीन दिलाने के लिए केंद्र ने इस पैकेज पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रस्तावित पैकेज पूरी तरह युवाओं पर केंद्रित रहेगा। यह उन्हें सामाजिक-राजनैतिक व आर्थिक स्तर पर उन्नति की राह पर ले जाएगा। पैकेज में युवाओं की खुशियों के लिए उनके मुद्दे हल करने के सभी विकल्प खुले होंगे।

सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए इस पैकेज का एलान केंद्र सरकार के आम बजट में हो सकता है। इसके लिए वित्त, योजना, मानव संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित अधिकारियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों से केंद्र सरकार की विभिन्न स्तरों पर बातचीत हो चुकी है। हाल ही में राज्य के दौरे पर आए विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्थानीय प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात में भी यह मुद्दा उठा है। इन मंत्रियों के साथ आए केंद्र सरकार के अधिकारियों को इन मुद्दों पर विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आउटरीच कार्यक्रम के तहत कश्मीर पहुंचे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास अहमद नकवी और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी कश्मीर में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में यकीन दिलाया है कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ा पैकेज घोषित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पैकेज का खुद एलान करेंगे।

प्राथमिकता में होगा रोजगार : सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित पैकेज में जम्मू-कश्मीर में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा ढांचे को समग्र रूप से मजबूत और विकसित बनाना, विभिन्न रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम व संस्थान शुरू करना, परंपरागत व गैर परंपरागत क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसरों का सृजन करना और युवाओं का सशक्तिकरण शामिल है।

पैकेज में स्थानीय युवाओं को खेल, कला व समाज कल्याण की विभिन्न गतिविधियों में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें सकारात्मक राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कोई उनका धार्मिक, सामाजिक या मजहबी आधार पर शोषण न कर सके।

हर वर्ग के वादे को पूरा करने का प्रयास

सूत्रों ने बताया कि बेशक प्रस्तावित पैकेज युवाओं पर केंद्रित होगा, लेकिन यह केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य के हर वर्ग के विकास को यकीनी बनाने वाला रहेगा। यह एक समावेशी और व्यावहारिक पैकेज होगा जो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के समय केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करता नजर आएगा।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रेम में नाकाम युवती ने किया युवक पर एसिड अटैक

जागरण संवाददाता, उन्नाव

पांच माह से लगातार प्रेम को ठुकराने से आहत युवती ने सोमवार रात अपनी डेयरी में सफाई कर रहे युवक पर तेजाब फेंक दिया। अचानक हुए एसिड अटैक से युवक झुलस गया। घरवालों ने उसे लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घटनास्थल से तेजाब की केन बरामद की है। आरोपित युवती पर मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। प्राथमिक जांच में एकतरफा प्रेम का मामला सामने आया है।

मौरावां क्षेत्र के गांव गोनामऊ निवासी 25 वर्षीय रोहित यादव मजरा भवानीगंज में दूध डेयरी चलाता है। सोमवार रात करीब दो बजे वह टैंकर में दूध लदवाने के बाद डेयरी में सफाई कर रहा था, तभी डेयरी के सामने रहने वाली 20 वर्षीय युवती वहां पहुंची। उसे देख युवक ने घर जाने को कहा, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। जब युवक ने उसके पिता से शिकायत करने की बात कही तो पहले से तैयारी कर आई युवती ने उस पर पीछे से तेजाब फेंक दिया। इससे रोहित का गला, कान, गर्दन व पीठ झुलस गए। वारदात को अंजाम देने के बाद युवती भाग निकली। झुलसा युवक किसी तरह अपने घर पहुंचा और स्वजनों को पूरी जानकारी दी। घरवाले पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद रोहित को लखनऊ ले गए। सूचना के बाद सीओ एमपी शर्मा के साथ पुलिस की टीम ने पड़ताल शुरू की।

पांच माह से पीछे पड़ी थी: पूछताछ में युवती ने बताया कि पांच माह से वह युवक से प्रेम का इजहार कर रही थी। घर से निकलने और डेयरी तक उसका पीछा करती थी। कई बार डेयरी पर जाकर उससे प्रेम का इजहार भी किया, लेकिन उसने हर बार मना करते हुए भाग जाने को कहा। इससे गुस्से में आकर उसने युवक पर तेजाब फेंकने का मन बना लिया था।

एक दिन पहले लाई थी तेजाब: सीओ पुरवा एमपी शर्मा ने बताया कि एसिड अटैक करने वाली युवती ने पूछताछ में बताया कि उसके प्यार के इजहार को युवक मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में वह बर्तन साफ करने के बहाने एसिड भी युवक के घर से एकदिन पूर्व ही मांगकर लाई थी। पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर आरोपित युवती के खिलाफ एसिड अटैक की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

11 तमिल मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है श्रीलंकाई नौसेना ने। साथ ही दो नौकाएं भी जब्त कर ली हैं। मछुआरों पर श्रीलंकाई जल सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है।

मुकेश की याचिका पर फैसला आज

निर्भया कांड ▸ दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने को दी है चुनौती

निचली अदालत ने फांसी के लिए तय कर रखी है एक फरवरी की तारीख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

निर्भया कांड के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। मुकेश ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने याचिका पर मुकेश और सरकार की दलीलें सुनकर बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने याचिका का जोरदार विरोध करते हुए मंगलवार को कहा कि यह याचिका स्वीकार करने लायक नहीं है। राष्ट्रपति के दोषी को माफी देने के अधिकार की समीक्षा का कोर्ट के पास सीमित अधिकार है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, अशोक भूषण और एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका पर करीब ढाई घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनी। मुकेश की ओर से वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। बिना सोच-विचार के जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को माफी देने का अधिकार एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कुछ आधारों पर उसकी समीक्षा कर सकता है। जैसे कि आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया हो या आदेश मनमाना हो।

अंजना प्रकाश ने कहा कि दया याचिका पेश करते समय राष्ट्रपति के समक्ष मामले से जुड़ा सारा रिकार्ड पेश किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। जेल अथॉरिटी से आरटीआइ में मिली सूचना के मुताबिक राष्ट्रपति के समक्ष मुकेश की डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिससे साबित होता है कि वह दुष्कर्म में शामिल नहीं था। मुकेश के वकील ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के शरीर में उसके डीएनए नहीं पाए गए। मुकेश इस बात से इन्कार नहीं करता कि वह उस दिन बस चला रहा था, लेकिन उसने न तो दुष्कर्म किया और न ही पीड़िता को मारने में उसका कोई हाथ था। यह भी कहा कि उसे एकांत कारावास में रखा गया, जेल में उसका यौन शोषण हुआ। इन चीजों पर विचार होना चाहिए था। यह किसी की जिंदगी का मामला है।

सरकार ने कहा, याचिका स्वीकार किए जाने लायक नहीं है: सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई यह याचिका स्वीकार किए जाने लायक नहीं है। विडंबना देखिए कि आज कौन जीवन के मूल्यों की बात कर रहा है, जिसने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर एक निर्दोष छात्रा से न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आंतरिक अंगों को भी खींचकर बाहर निकाल दिया। फिर उसे उसी हालत में सड़क पर फेक दिया।

मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है। दया याचिका जल्दी निपटाया जाना याचिका का आधार नहीं हो सकती। खुद सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दया याचिका निपटाने में देरी करना अमानवीय होता है, क्योंकि दोषी लगातार मौत के भय मे जीता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जल्दी दया याचिका निपटाए और ऐसा ही किया गया है। 16 जनवरी को गृह मंत्रालय ने सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी और राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कई पूर्व फैसलों में कह चुका है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के माफी देने के अधिकार पर कोई दिशा-निर्देश नहीं तय किए जा सकते। मेहता ने कहा कि मुकेश को कभी भी एकांत कारावास में नहीं रखा गया।

दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उससे इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारों अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और विनय कुमार शर्मा को मृत्युदंड दिया जा चुका है। मुकेश की दया याचिका भी राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं।

31 की दोपहर तक दया याचिका दायर की तो टल जाएगी फांसी

जासं, नई दिल्ली : दोषियों में मुकेश को छोड़कर अब तक किसी ने भी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर नहीं की है। जेल प्रशासन का कहना है कि शुक्रवार दिन में 12 बजे तक यदि दोषी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करते हैं तो उनकी फांसी याचिका के निपटारे तक टल सकती है। फिलहाल जेल प्रशासन फांसी को लेकर तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल प्रशासन की ओर से दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें शवों के पोस्टमार्टम के लिए व्यवस्था का आग्रह किया गया है।

टक्कर के बाद कुएं में गिरे बस और ऑटोरिक्शा, 21 लोगों की जान गई

मुंबई, एजेंसियां : महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को राज्य परिवहन (एसटी) की एक बस ऑटोरिक्शा से भिड़ गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे कुएं में जा गिरे। इसमें 21 की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। परिवहन मंत्री ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों के उपचार का खर्च भी राज्य परिवहन विभाग उठाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तर महाराष्ट्र जिले के मालेगांव-देवला रोड पर स्थित मेशी फाटा जिले में यह हादसा शाम करीब चार बजे हुआ। उन्होंने बताया कि यात्रियों से भरी बस तेज गति से जा रही थी और ऑटोरिक्शा से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस ऑटोरिक्शा को दूर तक घसीटती चली गई और दोनों वाहन सड़क किनारे स्थित कुएं में गिर गए।

नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया, 'कुएं से कम से कम 20 शव निकाले गए हैं। घायलों का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हम लोग पंप की मदद से कुएं का पानी निकाल रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि उसमें कोई और यात्री न फंसा हो।'

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बस धुले जिले से नासिक के कालवां शहर के लिए जा रही थी, जबकि ऑटोरिक्शा विपरीत दिशा से आ रहा था। पुलिस टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। तीस लोगों को बचा लिया गया है।

केंद्र की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जस्टिस भट्ट

भोपाल गैस त्रासदी

▸ पीड़ितों के मुआवजे के लिए सरकार ने की है अतिरिक्त धन दिलाने की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिका में केंद्र सरकार ने त्रासदी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी कंपनी से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दिलाने की मांग की है।

सुनवाई से खुद को अलग करते हुए जस्टिस भट्ट ने कहा, 'केंद्र ने जब इस मामले में पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की थी, तब मैंने सरकार की तरफ से उसकी पैरवी की थी।' जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार तक के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस एसए बोबडे अब इस मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेंगे। पीठ सदस्यों में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण व एमआर शाह भी शामिल हैं। केंद्र चाहता है कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए पूर्व में निर्धारित 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर (समझौते के समय 715 करोड़ रुपये) की राशि के अलावा यूनियन कार्बाइड और दूसरी फर्मों को 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन देने का निर्देश दिया जाए। यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित संयंत्र से एमआइसी गैस के रिसाव के कारण हुई इस त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 1.02 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। केंद्र ने दिसंबर 2010 में मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत में सुधारात्मक याचिका दाखिल की थी। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन का स्वामित्व अब डाउ केमिकल्स के पास है।

उल्लेखनीय है कि भोपाल की एक अदालत ने सात जून 2010 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के सात अधिकारियों को त्रासदी के लिए दोषी मानते हुए दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष वारेन एंडरसन मामले का मुख्य आरोपित था, लेकिन वह कभी सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक फरवरी 1992 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। अदालत ने एंडरसन की गिरफ्तारी के लिए वर्ष 1992 और वर्ष 2009 में गैर जमानती वारंट जारी किए थे। सितंबर 2014 में उसकी मौत हो गई।

न्यूज गैलरी

सलमान खान ने आपा खोया प्रशंसक का मोबाइल छीना

पणजी : गोवा एयरपोर्ट पर मंगलवार को सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे एक प्रशंसक के व्यवहार से अभिनेता सलमान खान इस कदर खफा हुए कि उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भाजपा ने मांग की है कि सलमान खान अपने इस आचरण के लिए माफी मांगें।

सेल्फी लेने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की पहचान एक एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ के रूप में हुई है। एयरपोर्ट पुलिस के इंस्पेक्टर सागर एकोस्कर ने बताया कि इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करके दबोलिम एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा है कि वह अपने स्टाफ से शिष्टाचार बनाए रखने को कहे। वहीं, दक्षिण गोवा से सांसद और भाजपा महासचिव नरेंद्र सवाईकर और दक्षिण गोवा के भाजपा महासचिव नवीन पाई रायकर ने ट्वीट कर सलमान के आचरण की निंदा की और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (प्रेट्र)

सरपंच प्रत्याशी के पति की नक्सलियों ने की हत्या

बीजापुर : दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के मतदान से एक दिन पहले शनिवार को सरपंच प्रत्याशी के पति की हत्या कर दी। घटना गंगालूर थाना क्षेत्र की है। नक्सलियों ने जिस इलाके में यह वारदात की, वहां मंगलवार को ग्रामीण निडरता के साथ घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मृतक बलदेव ताती पूर्व सहायक आरक्षक रह चुका है। उसकी पत्नी सुंदरी ताती कड़ेनार से सरपंच प्रत्याशी है। परिजनों के मुताबिक सोमवार दोपहर ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे 20-25 नक्सलियों ने बलदेव को घर से अगवा कर लिया था। नक्सली सुंदरी के भाई का मोबाइल भी छीनकर अपने साथ ले गए थे। इसी बीच मंगलवार सुबह बलदेव का शव कोटेर गांव के नजदीक पाया गया। पुलिस जांच कर रही है। (नईदुनिया)

भूल सुधार : दैनिक जागरण के मंगलवार (28 जनवरी, 2020) के अंक में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़ी एक खबर में वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी के हवाले से सरकार द्वारा एक चैनल को छोड़ किसी अन्य नए चैनल को लाइसेंस न दिए जाने की बात प्रकाशित हो गई है। दरअसल ये बयान थानवी के बजाय एक अन्य पैनलिस्ट का था। इस चूक के लिए खेद है।

पीएम मोदी के बाद 'मैन वर्सेस वाइल्ड' में नजर आएंगे रजनीकांत

▸ कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूटिंग के दौरान सुपरस्टार को लगी हल्की चोट

चेन्नई, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सुपरस्टार रजनीकांत बेयर ग्रिल्स के मशहूर टीवी शो 'मैन वर्सेस वाइल्ड' में नजर आएंगे। डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो की शूटिंग रजनीकांत और ग्रिल्स ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मंगलवार को शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग के दौरान रजनीकांत का पैर मुड़ गया और वो गिर पड़े, जिससे उनके हाथ में हल्की चोट लग गई।

कर्नाटक के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. श्रीधर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रजनीकांत और ग्रिल्स के शूटिंग करने की पुष्टि की। वहीं, वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कड़ी शर्तों के साथ 28 से 30 जनवरी तक शूटिंग की अनुमति दी गई है। शूटिंग के दौरान विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि रजनीकांत शो की शूटिंग के लिए सोमवार को ही मैसुरु पहुंच गए थे। मंगलवार को शूटिंग खत्म कर वो वापस चेन्नई लौट आए। चेन्नई में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि शूटिंग स्थल पर कांटों के चलते उन्हें हल्की चोट लग गई।

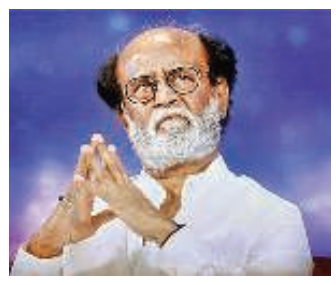
रजनीकांत। फाइल

पिछले साल शो में नजर आए थे पीएम मोदी : बेयर ग्रिल्स के इस शो में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। डिस्कवरी चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी वाला एपिसोड 12 अगस्त को प्रसारित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 'मैन वर्सेस वाइल्ड' एपिसोड के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग हुई थी।

आयकर विभाग ने रजनीकांत के खिलाफ याचिका वापस ली

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ 2002-03 से लेकर तीन साल तक कर आकलन के संदर्भ में दर्ज आयकर विभाग की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया। विभाग ने सीबीडीटी के एक परिपत्र का हवाला देते हुए एक करोड़ रुपये से कम राशि वाले मामले को आगे कानूनी चुनौती नहीं देने का फैसला किया।

न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार की पीठ ने आदेश सुनाया। आयकर विभाग ने दलील दी थी कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 26 जुलाई, 2013 के आदेश के खिलाफ अपील को वापस ले रहा है। न्यायाधिकरण ने रजनीकांत की 66 लाख रुपये से ज्यादा की कुल आय पर जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया था। विभाग के वकील ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 8 अगस्त, 2019 को परिपत्र जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एक करोड़ रुपये से कम कम राशि वाले मामलों में अपील नहीं करें।

सुप्रीम कोर्ट ने सरदारपुरा दंगों के 17 दोषियों को सशर्त जमानत दी

▸ अदालत ने दोषियों को दो भागों में बांटकर इंदौर और जबलपुर भेजा

▸ इन सबको प्रत्येक हफ्ते छह घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद सरदारपुरा में भड़के दंगों में 17 दोषियों को मंगलवार को सशर्त जमानत दी। इस घटना में 33 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया था। न्यायालय ने उन्हें मध्य प्रदेश जाने और सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने दोषियों को दो समूहों में बांटा और कहा कि एक समूह मध्य प्रदेश के इंदौर में रहेगा। दोषियों के दूसरे समूह को मध्य प्रदेश के ही जबलपुर जाना होगा। सरदारपुरा दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तों के तहत सभी दोषियों को प्रत्येक हफ्ते छह घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी। इसके अलावा उन्हें हर हफ्ते स्थानीय थाने में पेश होना पड़ेगा। न्यायालय ने इंदौर और जबलपुर में जिला विधिक सेवा अधिकारियों (डीएलएसए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दोषी जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करें। उसने डीएलएसए को दोषियों की आजीविका के लिए उचित रोगजार ढूंढने में मदद करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को तीन महीने बाद एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उसे बताना होगा कि दोषियों ने शर्तों का अनुपालन किया या नहीं। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुर दंगों में 14 को बरी कर दिया था और 17 को दोषी ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

घोषी से सांसद अतुल राय को पैरोल के खिलाफ पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दुष्कर्म के आरोपित जेल में बंद उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से बसपा सांसद अतुल राय को दो दिन की पैरोल के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अतुल राय को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिली है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 23 जनवरी को अतुल राय को दो दिन की पैरोल दी थी जिसमें उसे पुलिस अभिरक्षा में दिल्ली ले जाया जाना है जहां 31 जनवरी को राय लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। पीड़िता ने वकील किसलय शुक्ला और पीयूष द्विवेद्वी के जरिए याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगाने की मांग की है। पीड़िता की ओर से गत वर्ष मई में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। राय मई से ही जेल में है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में अतुल राय बसपा की टिकट पर घोसी संसदीय सीट पर चुनाव जीते हैं।

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में पूर्व सांसद सहित आठ आरोपित कोर्ट में पेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: करीब छह साल पहले शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने सहित विभिन्न आरोपों में नामजद पूर्व सांसद सईदुज्जमां, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी सहित आठ आरोपित सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने आरोप तय करने के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की है। 27 अगस्त 2013 को हुए कवाल कांड को लेकर 30 अगस्त 2013 को शहर में खालापार के शहीद चौक पर सभा की गई थी। इसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। सात सितंबर 2013 को जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा को लेकर शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां व उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था।

शादी रजिस्टर कराने को हाई कोर्ट पहुंचा समलैंगिक जोड़ा

▸ विशेष विवाह अधिनियम के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की मांग की

▸ अदालत ने केंद्र और केरल सरकार से मांगा जवाब

कोच्चि, प्रेट्र : केरल के एक समलैंगिक जोड़े ने शादी रजिस्टर कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जोड़े ने शादी रजिस्टर कराने के रास्ते में रोड़ा बन रहे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के कुछ प्रावधानों को रद करने की मांग की है।

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को समलैंगिक जोड़े की रिट याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य के साथ ही केंद्र सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा है।

याचिका के मुताबिक इस जोड़े में एक व्यवसायी है तो एक आइटी प्रोफेशनल। पहली बार इन दोनों की मुलाकात 2018 में हुई थी। उसके बाद इनकी मुलाकात बढ़ती गई और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने लगभग दो महीने तक साथ रहने के बाद शादी करने का फैसला किया और पिछले साल सितंबर में इन्होंने निजी समारोह में शादी कर ली। लेकिन इनकी शादी को धार्मिक मान्यता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी को रजिस्टर कराने का निर्णय किया। लेकिन यह कानून भी समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं देता।

इनका दावा है कि इस कानून के प्रावधान सिर्फ विपरीत लिंग वाले जोड़े की शादी को ही मान्यता प्रदान करते हैं, उनके जैसे समलैंगिक जोड़े की नहीं। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए इसके प्रावधान गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं। अदालत से उनकी शादी को रजिस्टर कराने की गुहार लगाते हुए समलैंगिक जोड़े ने कहा है कि उनकी शादी की बात सार्वजनिक होने के बाद से उन्हें लोगों से अपमान सहना पड़ रहा है।

जोड़े ने यह भी कहा है कि लोगों से ज्यादा उन्हें कानून से अपमानित होना पड़ा है, जो उनकी शादी को मान्यता नहीं देता। इसके चलते उन्हें मानसिक पीड़ा और परेशानी से गुजरना पड़ रहा है।

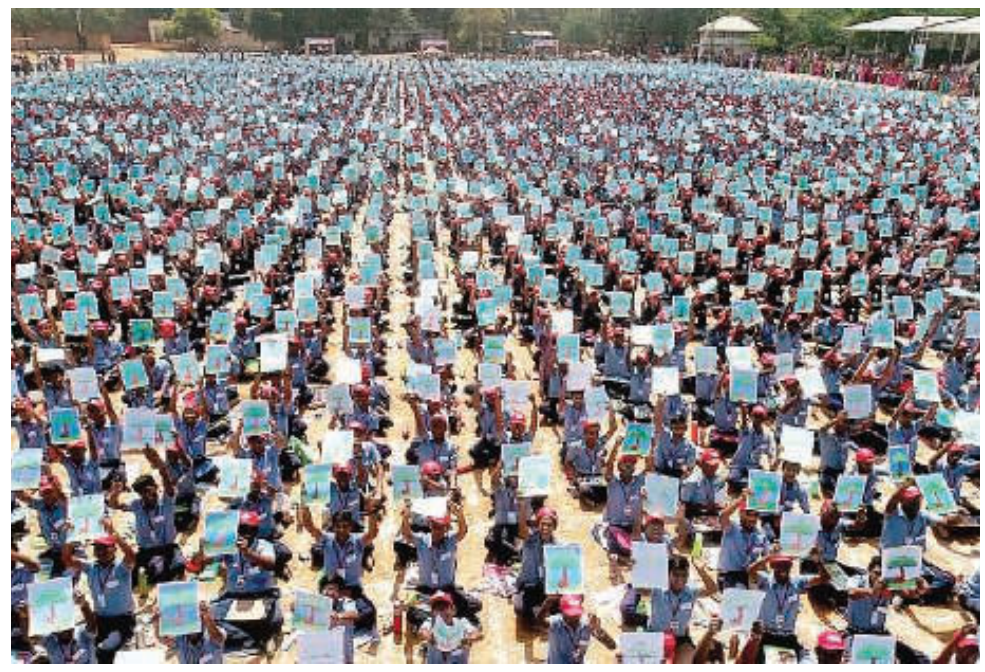

7000 छात्रों ने बनाया पेड़ की पेंटिंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड

तमिलनाडु के मदुरई स्थित सीईओए मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के 7000 छात्रों ने मंगलवार को एक साथ पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। यह आयोजन स्कूल के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। अभी तक यह रिकॉर्ड नीदरलैंड के एक स्कूल के नाम था। यहां के 2000 छात्रों ने एक साथ पेड़ की पेंटिंग बनाई थी। एएनआइ

परंपरा

सौराष्ट्र के प्रतिष्ठित राजपरिवार के समारोह में विंटेज कारों और हाथी-घोड़ों के साथ निकला नगर यात्रा का काफिला देखने उमड़े लोग, 2,126 युवतियों के तलवार रास से बना रिकॉर्ड

राजतिलक समारोह से पूर्व राजसूय यज्ञ शुरू

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

सौराष्ट्र के प्रतिष्ठित राजपरिवार के सदस्य मांधाता सिंह जाडेजा के राजतिलक समारोह से पूर्व राजसूय यज्ञ शुरू हुआ। मांधाता अपने पुत्र जयदीप के साथ नगर यात्रा पर निकले। सजा-धजा हाथी, 15 घोड़े, 25 विंटेज कारें भी इसमें शामिल थीं। दो हजार से अधिक राजपूत युवतियों ने तलवार रास कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया।

सौराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित राजकोट राजपरिवार के 17वें ठाकुर साहब मांधाता सिंह जाडेजा का राजतिलक आगामी 30 जनवरी को होगा। उससे पहले रणजीत विलास पैलेस में जल पूजा के साथ तीन दिवसीय राजसूय यज्ञ शुरू हुआ। मांधाता अपने पुत्र जयदीपसिंह जाडेजा के साथ चांदी के रथ में सवार होकर नगर यात्रा पर निकले।

इस दौरान बैंडबाजों की धुन पर सजे-धजे हाथी, घोड़े व विंटेज कार रैली निकाली गई। राजकोट के शहरवासियों ने रथ व कार में सवार राजपरिवार के सदस्यों व प्रदेश के अन्य रजवाड़ों से आए 50 से अधिक राजपरिवारों के सदस्यों का भव्य स्वागत किया और भारतीय परंपरा से रूबरू हुए। इससे पहले 2,126 राजपूत युवतियों ने तलवार रास कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराया।

मांधाता सिंह जाडेजा अपने पुत्र जयदीप के साथ रणजीत विलास पैलेस से चांदी के रथ पर सवार होकर नगर यात्रा पर निकले। सौ. राजपरिवार

राजतिलक समारोह राजगद्दी व भारतीय परंपरा का सम्मान है। राजप्रणाली से लोगों के काम करने को वचनबद्ध हूं। नगर यात्रा में प्रजा जनों के दर्शन पूजनीय बात हैं। उनके साथ रहकर लोक कल्याण ही राजधर्म है।

ठाकुर साहब मांधाता सिंह, राजकोट राजपरिवार के वरिष्ठ सदस्य

नागपुर में युवती से दरिंदगी आरोपित गिरफ्तार

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के नागपुर में एक 19 वर्षीय युवती से दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने दुष्कर्म के बाद युवती के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड भी डाल दी। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पारदी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील चव्हाण ने बताया कि आरोपित योगीलाल राहंगदले (52) कताई मिल में सुपरवाइजर है जबकि पीड़ित युवती उसी मिल में श्रमिक है। पीड़ित युवती, उसका भाई, उसकी एक दोस्त और योगीलाल परदी में ही किराये के घरों में रहते हैं। 21 जनवरी को पीड़ित युवती का भाई और उसकी दोस्त किसी काम से गांव गए थे। युवती घर पर अकेली थी। रात में योगीलाल ने पीड़ित युवती से दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डाल दी।

भाई के लौटने पर 24 जनवरी को युवती ने भाई को पूरी आपबीती सुनाई जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित योगीलाल को गोंदिया जिले से गिरफ्तार किया है।

रामपुर में पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म

▸ आरोपितों ने दंपती को हथियार के बल पर लूटा भी

▸ पति के शोर मचाने पर ग्रामीण आए तो भाग गए आरोपित

जागरण संवाददाता, रामपुर

उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के लखमन नगला व रामनगर गांव के बीच पुलिया पर सोमवार देर रात ससुराल से घर लौट रहे बाइक सवार दंपती को तीन नकाबपोश बदमाशों ने रोक लिया। हथियार का भय दिखाकर दस हजार की नकदी, पत्नी के जेवर व मोबाइल आदि लूट लिए। विरोध करने पर पीटा और पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने लूट और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया इसके साथ ही पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा।

टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दंपती रविवार रात बाइक से घर आ रहे थे। इसी बीच दो बाइक पर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका और तमंचे दिखाकर लूट लिया। विरोध करने पर मारपीट की और दोनों को सड़क के किनारे ले गए। पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पति के शोर मचाने पर लखमन नगला की ओर से ग्रामीण आते दिखाई दिए तो बदमाश बाइक से भाग निकले। ग्रामीणों ने पति को बंधनमुक्त किया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंपती से बदमाशों के बारे में जानकारी ली और उनकी तलाश में कांबिंग भी की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। मंगलवार को पीड़िता के पति ने तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पहले सिर्फ लूट की जानकारी दी गई थी। डेढ़ घंटे बाद दुष्कर्म की बात भी बताई है।

दैनिक जागरण
शिक्षा की जड़ें कड़वी, लेकिन फल मीठे होते हैं

दुष्प्रचार के दुष्परिणाम

अंध विरोध और दुष्प्रचार कैसे हालात पैदा करता है, इसका ही एक उदाहरण है यूरोपीय संसद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव आना। यह प्रस्ताव उस माहौल का दुष्परिणाम है जो भारतीय मीडिया के एक हिस्से के साथ ही विपक्षी राजनीतिक दलों और वामपंथी रुझान वाले कथित बुद्धिजीवियों की ओर से बनाया गया है। वास्तव में इसी दूषित माहौल के चलते भारत विरोधी तत्वों को यूरोपीय संसद के सदस्यों को उकसाने और उनके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने का अवसर मिला है। हालांकि यूरोपीय संसद में लाए गए किसी प्रस्ताव का कोई मूल्य-महत्व नहीं है और इसे यूरोपीय समुदाय ने भी स्पष्ट कर दिया है, फिर भी देश में कुछ लोग यह रेखांकित करने में लगे हुए हैं जैसे भारत के हितों के खिलाफ कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहल होने जा रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो यूरोपीय समुदाय और यूरोपीय संसद में भेद करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे ही उनके संकीर्ण राजनीतिक हित सध रहे हैं। किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में यूरोपीय संसद की ओर से पारित प्रस्ताव एक ज्ञापन से अधिक महत्व नहीं रखते। वहां से पारित प्रस्ताव जिस यूरोपीय समुदाय को विचार के लिए दिए जाते हैं उसके प्रमुख देश पहले ही यह कह चुके हैं कि नागरिकता कानून भारत का आंतरिक मामला है।

यह देखना दयनीय भी है और शर्मनाक भी कि जिस कांग्रेस पार्टी के शासन वाले राज्य नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक परंपराओं को लांछित करने में लए हुए हैं उसके नेता यह कह कर भ्रम फैलाने में जुटे हैं कि यूरोपीय संसद की पहल मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है। शायद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के ऐसे ही आचरण को देखकर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि वे देश की छवि से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से वे केवल यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के जरूरी कार्यों में बाधा भी डाल रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का विरोध कुल मिलाकर एक जनविरोधी हरकत है। आखिर ऐसे किसी रजिस्टर से ही तो पता चलता है कि निर्धन-वंचित लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं बनाने की जरूरत है। एनपीआर तो एक तरह से जनकल्याण की योजना है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि जिस कांग्रेस ने एनपीआर की शुरुआत की वही उसके खिलाफ न केवल खड़ी हो गई है, बल्कि आम लोगों को गुमराह भी कर रही है। आखिर इसे जनविरोधी राजनीति की संज्ञा न दी जाए तो और क्या कहा जाए?

मिटाना होगा दाग

पिछले दिनों ग्रीन पीस इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की, जो झारखंड, खास तौर पर धनबाद के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। देश के 287 शहरों से पीएम10 आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार झरिया और धनबाद देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं - झरिया नंबर एक और धनबाद नंबर दो। यह तमगा बेहद चिंतनीय है और शर्मसार करनेवाला भी। झरिया देश के सबसे बड़े कोयला स्त्रोतों में एक है। धनबाद को देश की कोयला राजधानी का दर्जा मिला हुआ है। यहां की धरती में बेशुमार कोयला है, जो देश की आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा का आधार है। ऐसे में सबसे प्रदूषित शहर का दाग कैसे गवारा किया जाए? वह भी तब, जब देश को स्वच्छ और साफ-सुथरा रखने की मुहिम चल रही है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गईं, जिनके कारण झरिया और धनबाद सबसे प्रदूषित शहर बन गए। चश्मे को साफ कर पड़ताल जरूरी है। झरिया में 100 साल से अधिक समय से भूमिगत कोयले में आग लगी हुई है। इसका धुआं वातावरण को प्रभावित करते आ रहा है। खदानों से निकला कोयला ट्रकों पर लोड कर बाहर भेजा जाता है। इस दौरान काफी धूल उड़ती है, क्योंकि पानी छिड़काव आदि मानकों का पालन नहीं किया जाता। जगह-जगह खदानों से निकला मलबा रखा हुआ है। यह भी हवा के साथ इधर-उधर पहुंच जाता है। कोयला खनन के दौरान ब्लास्टिंग होती है और छोटे-छोटे बेशुमार कण वातावरण में मिल जाते हैं। वर्ष 2017 में प्रदूषण के मामले में धनबाद देश में 24वें नंबर पर था। बीते तीन सालों में हालात और बिगड़ गए। यह साबित करता है कि लापरवाही बढ़ गई है। ऐसा नहीं चलेगा। इस दाग को अविलंब मिटाना होगा। जरूरी है कि इसके लिए सब संकल्प लें और अपने-अपने स्तर से जुट जाएं। प्रदूषण कम करने की मुहिम चलाएं। इसके अलावा शासन-प्रशासन के स्तर पर स्पष्ट नीति बने, समयसीमा तय हो, उसपर ईमानदारी से काम हो। ऐसा होगा तो परिणाम अवश्य सुखद होगा और हम निर्मल हो जाएंगे, क्योंकि दाग अच्छे नहीं...।

प्रदूषण कम करने की मुहिम चले। शासन-प्रशासन के स्तर पर स्पष्ट नीति बने। समयसीमा तय हो और उसपर ईमानदारी से काम हो। ऐसा होगा तो परिणाम अवश्य सुखद होगा और हम निर्मल हो जाएंगे

संघीय ढांचे पर हमला करते राज्य

ए. सूर्यप्रकाश

राज्य सरकारों द्वारा पारित सीएए विरोधी प्रस्ताव न केवल असंवैधानिक, बल्कि देश के संघीय ढांचे के लिए खतरे की घंटी भी हैं

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर जैसी पहल का कुछ राजनीतिक दलों एवं राज्य सरकारों द्वारा लगातार किया जा रहा विरोध हमारे गणतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। सीएए तो अब कानून भी बन गया है। यह हमारे तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसके लिए भी 31 दिसंबर, 2014 की मियाद रखी गई है। चूंकि ये तीनों ही देश घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं। इस कारण वहां दूसरे धर्मों के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। वहां गैर-मुस्लिमों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। दरअसल विभाजन के समय से ही इन देशों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किस्म-किस्म के जुल्म किए गए। तब मजबूरन उनके समक्ष दो ही विकल्प रह गए। या तो धर्मांतरण या वहां से भागकर कहीं और शरण लेना। इसका परिणाम यह निकला कि 1940 के दशक के आसपास अविभाजित पाकिस्तान में हिंदुओं की जो आबादी 24 प्रतिशत थी वह 1.7 प्रतिशत रह गई। इसी तरह अतीत में पूर्वी पाकिस्तान रहे बांग्लादेश में भी इसी कालावधि में हिंदुओं की आबादी 30 प्रतिशत से घटकर सात फीसद रह गई है। इसी तथ्य में वह जवाब निहित है कि सीएए के तहत प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सूची से मुस्लिमों को क्यों बाहर रखा गया है। अव्वल तो वे 'अल्पसंख्यक' नहीं और दूसरी बात यह कहना हास्यास्पद ही है कि इस्लामिक देश में मुस्लिमों का 'उत्पीड़न' हो रहा है। प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए भी सीएए में एक मियाद तय की गई है। यानी यह भविष्य में इन देशों के विस्थापितों के लिए देश के दरवाजे खोल देने का मामला नहीं है। फिर इसका भारतीय नागरिकों से भी कोई लेनादेना नहीं, भले ही वे हिंदू हों या मुस्लिम।

इस वास्तविकता को देखते हुए कम्युनिस्ट, कांग्रेस और अन्य भाजपा विरोधी दल सीएए को लेकर जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह मुस्लिम विरोधी है, वह पूरी तरह भ्रामक है। इस कानून के जरिये जो प्रयास हो रहा है वह भारतीय धर्म और हमारे संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप ही है कि हम प्रताड़ितों को संरक्षण प्रदान करें। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे असल में पड़ोसी इस्लामिक मुल्कों के गैर-सेक्युलर और गैर-लोकतांत्रिक स्वरूप की अनदेखी कर रहे हैं। इसके साथ ही वे भारत में इन मूल्यों की बात करने का नैतिक आधार भी गंवा देंगे। कम्युनिस्ट और कांग्रेसी एनपीआर को लेकर भी अफवाहें फैलाने में जुटे हैं जिसका संकलन नीति निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। इन दोनों ही दलों को देश की जनता ने पिछले साल मई में हुए संसदीय चुनावों में बुरी तरह खारिज किया था। भले ही टेलीविजन पर होने वाली बहसों में कम्युनिस्टों को 30 से 40 प्रतिशत तक जगह मिलती हो, लेकिन इन दलों के जनाधार में भारी कमी आई है। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में दो शीर्ष कम्युनिस्ट दलों को 7.07 प्रतिशत मत मिले। फिर 2014 के चुनाव में यह हिस्सेदारी और घटकर 4.07 फीसद रह गई और पिछले साल हुए आम चुनाव में यह महज 2.36 प्रतिशत पर सिमट गई। लगता है जेएनयू ही उनका आखिरी गढ़ बचा रह गया है। अब ये दोनों वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर उस कानून को लेकर सरकार को घेरकर अपनी चुनावी खीझ उतारने पर आमादा हैं जिस कानून को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

अवधेश राजपूत

केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि संसद द्वारा पारित सीएए ने समाज के विभिन्न वर्गों को भयाक्रांत करने का काम किया है। इसके बाद पंजाब विधानसभा ने पारित प्रस्ताव में कहा कि सीएए ने देश में व्यापक तनाव और सामाजिक असंतोष पैदा किया है। उसने इसके पीछे की विचारधारा को पक्षपातपूर्ण एवं मानवीय मूल्यों से दूर बताया। ऐसे प्रस्ताव पारित करने वाले राज्यों की फेहरिस्त में ताजा नाम राजस्थान और पश्चिम बंगाल का जुड़ा है। ये प्रस्ताव न केवल असंवैधानिक, बल्कि अप्रत्याशित भी हैं जो देश के संघीय ढांचे के लिए निश्चित रूप से खतरा पैदा करते दिख रहे हैं। इन प्रस्तावों में भी पंजाब विधानसभा का प्रस्ताव बहुत चिंताजनक है। उसमें आशंका जताई गई है कि एनपीआर राष्ट्रव्यापी एनआरसी का पहला पड़ाव है जिसका लक्ष्य 'एक वर्ग को भारतीय नागरिकता से वंचित करना है' और इन आशंकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार को एनपीआर के प्रावधानों को बदलना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव पारित करने वाली केरल, पंजाब, राजस्थान और बंगाल विधानसभाओं ने स्वघोषित मजहबी मुल्कों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर कोई संताप प्रकट नहीं किया। सेक्युलरिज्म पर उनके भाषण भारत के सेक्युलर एवं लोकतांत्रिक नागरिकों और उनके द्वारा चुनी गई सरकार के लिए ही हैं। इस सिलसिले में हाल के तीन और घटनाक्रम बहुत चिंतित करने वाले हैं। पहला यही कि कई मुख्यमंत्रियों ने एलान किया है कि वे अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं करेंगे। दूसरा यह कि सीएए के खिलाफ धरना स्थलों पर बच्चों का सहारा लेकर उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया जा रहा है। तीसरा यह कि मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है कि वे एनपीआर के लिए सहयोग न करें।

अपने-अपने राज्यों में सीएए लागू न करने का एलान करने वाले मुख्यमंत्रियों को तुरंत अपनी यह घोषणा वापस लेनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान की सर्वोच्चता पर सवाल उठता है। नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का एकाधिकार संसद के पास है और किसी व्यक्ति या राज्यों को यह कहने का अधिकार नहीं कि वे संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगे। यदि मुख्यमंत्री ही इस रुख पर अड़े रहेंगे तो इससे संवैधानिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी जिसके गंभीर परिणाम होंगें। प्रदर्शनकारी जिस तरह बच्चों को आगे करके प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा रहे हैं वह भी अस्थिरता पैदा करने की निशानी है जिसका कोई भी तार्किक व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा। एनपीआर के बहिष्कार की अपील के भी बहुत जोखिम हैं, क्योंकि किसी चुनी हुई सरकार के कामकाज को बाधित करने के प्रयास के अपने अंतर्निहित खतरे हैं।

जो भी लोग ऐसी कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, वे एक बेहद खतरनाक राह पर बढ़ रहे हैं। देश की जनता को सतर्क रहना होगा कि संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक जनजीवन किसी तरह अस्थिर न हो पाए।

(लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

खतरनाक इरादों वाला पीएफआइ

विकास सारस्वत

मुस्लिम हितों और मानव अधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले फ्रंट का उग्रवादी चरित्र किसी से छिपा नहीं

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दी गई यह जानकारी जितनी सनसनीखेज है उतनी ही चिंतित करने वाली भी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआइ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम बैंक खातों के जरिये करीब 120 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए, ताकि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ धरना-प्रदर्शनों को हवा दी जा सके। ईडी के अनुसार उक्त रकम का एक बड़ा हिस्सा देश के कुछ नामी वकीलों के पास गया। ये वही वकील हैं जो इस कानून के खिलाफ सक्रिय हैं। ध्यान रहे सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश में भड़की हिंसा के बाद ही प्रदेश सरकार ने चरमपंथी संगठन पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने की संस्तुति की थी। यूपी पुलिस पीएफआइ के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद, कोषाध्यक्ष नदीम और मंडल अध्यक्ष अशफाक समेत अन्य को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। अहमद ने शुरुआत में अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया, लेकिन कॉल डिटेल्स की छानबीन के बाद उसकी असलियत सामने आ गई। इस संगठन के विभिन्न दफ्तरों से तमाम भड़काऊ सामग्री भी बरामद की गई थी। सीएए पर भड़काऊ प्रचार और हिंसा भड़काने में पीएफआइ की भूमिका असम में भी सामने आई है। इसके अलावा दिल्ली और कर्नाटक के मंगलुरु में हुई हिंसा में भी उसका हाथ नजर आया।

पीएफआइ का उग्रवाद-अतिवाद से पुराना नाता है। इस संगठन का उदय 2006 में केरल में हुआ था। पहली बार यह संगठन राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आया था जब उसके कार्यकर्ताओं ने जुलाई 2010 में ईशनिंदा का आरोप लगाकर केरल के न्यूमैन कॉलेज के प्रो. डीजे जोसेफ की हथेली को काट दिया था। इसकी जांच में केरल पुलिस ने सात शहरों में छापेमारी कर पीएफआइ कैडर के घरों से बड़ी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। इनमें तालिबान और अल कायदा का गुणगान करने वाली सामग्री भी थी। 2011 में मैसूर के एक कॉलेज से सुधींद्र और विग्नेश नामक दो युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में भी पीएफआइ से संबद्ध संगठन कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी के छह सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। उनका अपहरण संगठन के लिए धन उगाही के लिए किया गया था। इसके बाद 2013 में कन्नूर के नरथ इलाके में पुलिस ने पीएफआइ के ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारकर हथियारों सहित 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में डर बैठाने के लिए फ्रंट पर उसके कई सदस्यों की हत्या का आरोप है। कन्नूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिन गोपाल और विशाल की हत्या, बेंगलुरु में रुद्रेश और मूदबिदरी में प्रशांत पुजारी की जघन्य हत्या के अलावा कई अन्य हत्याओं में पीएफआइ के सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केरल सरकार द्वारा दिए गए एक हलफनामे में पीएफआइ को अकेले केरल में 27 हत्याओं, 86 हत्या के प्रयास और 106 सांप्रदायिक घटनाओं का दोषी माना गया था। इसमें ज्यादातर पीड़ित संघ कार्यकर्ता ही थे। फरवरी 2015 में शिमोगा में पीएफआइ की रैली के दौरान हिंसा में दो लोगों की जान चली गई थी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन फ्रंट पर मतांतरण द्वारा राज्य के इस्लामीकरण का आरोप लगा चुके हैं इस संगठन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहे हैं। ईडी ने जिन वकीलों पर पीएफआइ से पैसे लेने की बात कही है उन्होंने यह माना है कि यह पैसा लव जिहाद के हादिया केस की पैरवी के लिए लिया था।

शहंशाह और सिराजुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ केरल केस में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस केटी शंकरण ने डीजीपी को लव जिहाद की विवेचना के आदेश दिए थे।

सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि पीएफआइ का संबंध आतंकी संगठनों से होने का संदेह है। पूर्व में प्रतिबंधित सिमी के ही सदस्यों द्वारा शुरू हुए पीएफआइ के इस्लामिक स्टेट से संबंध प्रकाश में आते रहे हैं। कन्नूर के वल्लपत्तनम से फ्रंट के करीब 40-50 लोग आइएस में शामिल भी हो चुके हैं। श्रीलंका में हुए धमाकों के मास्टरमाइंड को कट्टरवादी बनाने में भी फ्रंट का नाम सामने आया था। रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच पीएफआइ के आइएसआइ से साठगांठ का संदेह जता चुके हैं। कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने फ्रंट की गतिविधियों पर चिंता जताई है। मलयालम लेखक मोहिउद्दीन कच्चेरी चेताते हैं कि ऐसे संगठन मुस्लिम युवकों को अल मौदूदी की कट्टरपंथी राह पर ले जाकर केरल के तालिबानीकरण में जुटे हैं।

करीब नौ संगठनों के विलय के बाद पीएफआइ राष्ट्रीय चुनौती बन गया है। इसका जाल मणिपुर तक पहुंच चुका है। दिल्ली के शाहीनबाग में जहां पिछले पांच-छह सप्ताह से सीएए के विरोध में धरना जारी है वहां फ्रंट का मुख्यालय है। संभव है कि यह शक्ति प्रदर्शन पीएफआइ पर प्रतिबंध की स्थिति में मुख्यालय को घेरे रखने और विरोध को उग्र बनाने के तहत हो। कहने को यह संगठन मुस्लिम हितों और मानवीय अधिकारों की रक्षा का दम भरता है, परंतु इसका सांप्रदायिक और उग्रवादी चरित्र किसी से छिपा नहीं है। फ्रंट प्रजातंत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बड़ी चतुराई से उपयोग कर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। एकता मार्च और फ्रीडम मार्च जैसे शब्दों से अलगाववाद और इस्लामीकरण की वकालत होती है। हाथ में तिरंगा लेकर उपद्रव करना और आजादी जैसे नारों का अलगाववाद के लिए इस्तेमाल करना इसकी शैली है। इसका अपना एक दैनिक अखबार भी है।

झारखंड सरकार पीएफआइ पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। दो साल पहले पुलिस महानिदेशकों की बैठक में भी फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा हुई थी। सीएए के विरोध में हुई हिंसा में पीएफआइ की भूमिका के मद्देनजर देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई करती है और उसके हितैषियों को बेनकाब करती है?

(लेखक इंडिक अकादमी से संबद्ध हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मौन का महत्व

मनुष्य प्राचीन काल से ही अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता आ रहा है। यहां तक कि जब वह भाषा या शब्द भी नहीं जानता था तब भी उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करना आता था। उसने अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए तमाम उपक्रम किए। कभी वह दीवारों पर चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहता तो कभी अजीब सी आवाजें निकालता। काल की गति के साथ-साथ उसमें कई बदलाव आए। उसने भाषा सीखी। बोलना सीखा। चीखना-चिल्लाना भी सीख लिया। आधुनिक समय में तो अभिव्यक्ति के दर्जनों माध्यम हैं। सोशल मीडिया के इस युग में विभिन्न बातें रोचक तरीके से कही जा रही हैं। वे कुछ ही क्षणों में प्रसारित होने में सक्षम हैं।

हालांकि बहुधा ऐसा देखने को मिलता है कि आपके मुख से निकले कुछ शब्द आपके लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए ही मौन की महत्ता बताई गई है। कहा भी गया है कि 'वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। हम कितना ही अच्छा और श्रेष्ठ क्यों न बोल लें वह केवल और केवल रजत (चांदी) की श्रेणी में आता है, परंतु व्यक्ति का मौन स्वर्ण यानी सोना है।

मौन दैवीय अभिव्यक्ति है। इसका अपना महत्व है। विज्ञान भी मौन के महत्व को प्रमाणित करता है। जहां शोर उच्च रक्तचाप, सरदर्द और हृदय रोग इत्यादि देता है। वहीं मौन इन सबके के लिए औषधि का कार्य करता है। मौन ही है जो हमारे चिंतन को विराट स्वरूप प्रदान करता है। आधुनिक जीवन शैली में मौन का महत्व चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम है। जब व्यक्ति दिनभर कार्यों में व्यस्त रहता है। ध्वनि प्रदूषण के बीच जूझता है। तनाव के मकड़जाल में फंस जाता है। उसी समय मौन का सामीप्य उस पर मातृवत् प्रेम बरसाता है। अगर हम प्रतिदिन कुछ घंटे मौन के शरणागत होते हैं तो वह हमें रचनात्मकता प्रदान करता है। मौन की साधना साधक को अनेकों वरदान प्रदान करती है।

ललित शौर्य

मत का महत्व जानें मतदाता

अनीश कुमार

किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का मतदाता कितना जागरूक है

वैश्विक लोकतंत्र की स्थिति के ताजे सूचकांक में भारत 10 पायदान फिसल कर 51वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं। इसमें संविधान ने बड़ी भूमिका निभाई है। विविधता से भरे भारतीय संविधान की अनेक विशिष्टताओं में से एक है, अनुच्छेद 326 के तहत सभी वयस्कों को मत डालने और चुनाव में सक्रिय भागीदारी का दिया गया अधिकार। यह एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों की सबसे बड़ी ताकत बन कर उभरा है। मताधिकार का प्रयोग कर हर नागरिक गर्व महसूस करता है। मतदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराने का सर्वोत्तम तरीका है। यह न सिर्फ राजनीतिक अधिकार है, अपितु एक नैतिक कर्तव्य भी है। इस अधिकार का जितना अधिक और वाजिब प्रयोग होगा, लोकतंत्र उतना ही परिपक्व होगा।

दरअसल एक लोकतांत्रिक गणराज्य की असली ताकत उसके मतदाताओं में ही निहित होती है। मतदाता ही यह चयन करते हैं कि वह अपने ऊपर किसका शासन चाहते हैं। वहीं जो जनप्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, उन्हें सही समय आने पर सबक भी सीखा देते हैं। चुनाव में भाग लेकर मतदाता अपना और देश का भविष्य तय करते हैं। मतदाताओं का एक-एक वोट कीमती होता है। वोट की ताकत के बल पर न सिर्फ सरकारें बदलती रहती हैं, अपितु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन से जुड़े मुद्दे विधानमंडल और संसद तक का सफर तय करते हैं। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का मतदाता कितना जागरूक है और चुनाव प्रणाली में वह अपनी सहभागिता देता है नहीं? वोट प्रतिशत इस बात का भी संकेतक होता है कि मतदाता लोकतंत्र पर कितना भरोसा करता है? मतदाता जितने जागरूक, निडर और सतर्क होकर मताधिकार का उपयोग करेंगे, लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में उतना ही कामयाब होगा। हालांकि देश में सौ फीसद मतदान और अनिवार्य मतदान का स्वप्न अधूरा ही है, लेकिन मतदान को लेकर जागरूकता के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियानों का ही सकारात्मक परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इससे एक तरफ जहां लोकतंत्र की स्थिति मजबूत हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज भी मतदाताओं का एक हिस्सा चुनाव में निष्क्रिय नजर आता है, जिससे प्रतीत होता है कि या तो उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या उन्हें अपने वोट की कीमत मालूम ही नहीं है!

एक नागरिक के तौर पर हमें सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार के रूप में मिला है, लिहाजा विवेक से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। वोट किसे देना है, यह निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार मतदाता के ही पास होता है। वोट डालना न सिर्फ एक अधिकार है, अपितु एक कर्तव्य भी है। यह बात हरेक मतदाता को समझनी होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

देशहित में हों समझौते

नए सिरे से विचार हो मुक्त व्यापार का शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. भरत झुनझुनवाला ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि वह इस वर्ष के आम बजट में विदेशी व्यापार के लिए ऐसा कोई प्रावधान करे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो। मेरा मानना है कि इस बार ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी से देश के उद्योग जगत की कमर टूटी थी, उस पर अभी मरहम नहीं लग पाया है। मोदी सरकार को इस बार के आम बजट में उद्योग जगत को सस्ते कर्जे उपलब्ध करवाने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि ये बिना किसी तनाव के लोन लेकर अपने उद्योग को सुधार सकें। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के उद्योग धंधों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ाया था। भारत को ट्रंप की इन नीतियों से सबक लेना चाहिए। भारत दूसरे देशों, खासतौर चीन के साथ व्यापार के मामले में गंभीर नहीं है, इस कारण भारत को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इससे भारत उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ही रहा, साथ ही अपने देश के उद्योग धंधों की बर्बादी का कारण भी बन रहा है। भारत को व्यापार के मामले में दूसरे देशों से इस तरह समझौते करने चाहिए जिससे देश में रोजगार बढ़े, आर्थिक फायदा हो।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

शाकाहार को बढ़ावा देने की जरूरत

चीन में जन्मा कोरोना वायरस अब खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। खासतौर पर दक्षिण एशियाई देशों के लिए यह खतरा बना हुआ है। भारतीय स्वास्थ्य तंत्र भी इसके खिलाफ कमर कसते हुए हवाई अड्डों, दूतावासों, अस्पतालों, बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों पर पूरी नजर बनाए हुए है ताकि ये देश की सरहदों को ना लांघ पाए। सी फूड यानी समुद्री जीवों अथवा जानवरों के मास का सेवन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हम चीनी खानपान शैली को देखें तो उनकी खानपान शैली में मांसाहार मुख्य घटक है। मांसाहार की यही शैली अफ्रीकन देशों में भी मुख्य रूप से पाई जाती है, फलस्वरूप बंदरों व सूअरों जैसे जानवरों के मांस के सेवन से फैले इबोला वायरस के भयंकर परिणाम पूरी दुनिया के समक्ष है। भारतीय खानपान शैली को देखें तो यहां भरपूर वनस्पति होते हुए भी लोगों में मांसाहार की प्रवृत्ति पहले की अपेक्षा बढ़ती जा रही है, जो इस तरह के खतरे को आमंत्रित करने का कार्य कर रही है। खतरनाक वायरसों से उत्पन्न भयंकर परिणामों को हमारा स्वास्थ्य तंत्र कितना संभाल पाएगा ये आप और हम सब जानते हैं। अतः अभी से हम पूरी मानव सभ्यता के बचाव और विकास के लिए शाकाहार शैली को अपनाकर इस प्रकार के खतरों की संभावनाओं को शून्य कर सकने में अपना योगदान दे सकते हैं।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

सरकार का सही फैसला

यह पत्र 'एयर इंडिया की बिक्री' के संदर्भ में है। जब करदाताओं के पैसे से एयर इंडिया चल रही हो तो इसको बेचने में ही भलाई है। एयर इंडिया हो सकता है कि विश्व की सबसे लाभदायक एयरलाइंस में से एक न हो, मगर 100 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय अधिकार और काफी देशों के साथ प्राइम स्लॉट होना अपने आप में बहुत फायदे का सौदा है। हम उम्मीद करेंगे की कई एयरलाइंस इसमें अपनी रुचि दिखाएंगी और जल्द ही सरकार एअर इंडिया को बेचने में कामयाब होगी।

balgovindly@gmail.com

विपक्ष मजबूत बने

वर्तमान राजीनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त विपक्ष की अनुपस्थिति शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। वे क्षेत्रीय हितों को ज्यादा महत्व देती हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी राजनितिक पार्टी है जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज भी वजूद बनाए हुए है। जिसकी जमीन आज बंजर हो चुकी है ऊपर से एक ही परिवार का लेबल लगा हुआ है जिससे पार्टी को अब छुटकारा पाना ही होगा। पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ताओं और नेताओं का घोर अभाव है और जो हैं उनमें जोश खत्म हो चुका है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1921 में ब्रिटिश भारत में मद्रास पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को सबसे पहले मत डालने का अधिकार दिया था। हालांकि यह अधिकार महिलाओं के एक सीमित वर्ग को मिला था।

आजकल

अब कोरोना की चुनौती से दो-चार होती दुनिया

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि दुनिया दूसरी प्रजातियों से इंसानों तक पहुंचने वाले विषाणुओं की चपेट में आती है और वह संक्रमण इंसानों से ही दूसरे इंसानों में फैलकर एक महामारी में बदल जाता है। ऐसा ही एक तूफान नोवेल कोरोना वायरस की शक्ल में चीन से उठ खड़ा हुआ है। इससे फिलहाल चीन में ही 106 मौतें होने और दुनिया भर में करीब डेढ़ हजार लोगों के संक्रमित होने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा संक्रमित लोग चीन के ही नागरिक हैं, लेकिन विभिन्न देशों में उनके आवागमन के कारण दूसरे मुल्कों में भी इसका जोखिम बढ़ रहा है

अगर मर्ज पकड़ में आ जाए और उसका आसानी से इलाज मुमकिन हो तो कोई बीमारी बड़ी नहीं हो सकती। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से लेकर कई अन्य रोग ऐसे हैं जिनसे मानव समुदाय निजात तो नहीं पा सका है, लेकिन उन्हें ज्यादा बड़ा खतरा इसलिए नहीं माना जाता है कि क्योंकि उनका निदान संभव है। वे ऐसे संक्रामक भी नहीं होते कि किसी महामारी में बदल जाएं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि दुनिया दूसरी प्रजातियों से इंसानों तक पहुंचने वाले विषाणुओं की चपेट में आती है और वह संक्रमण इंसानों से ही दूसरे इंसानों में फैलकर एक महामारी में बदल जाता है। ऐसा ही एक तूफान नोवेल कोरोना वायरस की शक्ल में चीन से उठ खड़ा हुआ है। इससे फिलहाल चीन में ही 106 मौतें होने और दुनिया भर में करीब डेढ़ हजार लोगों के संक्रमित होने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा संक्रमित लोग चीन के ही नागरिक हैं, लेकिन विभिन्न देशों में उनके आवागमन के कारण दूसरे मुल्कों में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा फैल गया है।

इंसान से इंसान में फैलने का खतरा : समस्या यह है कि इस वायरस के मानव से मानव में संचार की पुष्टि हो गई है और भारत में भी इसके मरीजों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। यूपी, बिहार और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और उनके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। खतरा यह है कि यह संक्रमण चीन के विभिन्न शहरों से होते हुए थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आदि 11 देशों तक जा पहुंचा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस वायरस के जा पहुंचने की आशंकाएं निराधार नहीं हैं। असल में 25 जनवरी से शुरू हुए चीनी नए वर्ष के त्योहारी सीजन में चीनी नागरिक पूरी दुनिया की सैर पर निकल पड़े हैं। एक दावा है कि वुहान शहर के ही करीब 50 लाख बाशिंदे चीन समेत दुनिया के अलग हिस्सों में जा पहुंचे हैं। ऐसे में यदि किसी देश का स्वास्थ्य तंत्र कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सावधान न हुआ तो उस देश के बड़े हिस्से इसकी चपेट में आ सकते हैं। यही कारण है कि एशिया के आधा दर्जन देशों समेत अमेरिका तक में चीन से आने वाले यात्रियों की गहन जांच की जा रही है।

कहां से आया कोरोना वायरस : हालांकि इस संक्रामक विषाणु के स्रोत की पक्की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है, लेकिन दावा है कि आमतौर पर जानवारों में पाए जाने वाले कोरोना या करॉन वायरस की शुरुआत दिसंबर, 2019 में चीन के वुहान प्रांत के फ्रेश फूड मार्केट से हुई थी। हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है कि इस वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ों और सांप के मांस से तैयार की गई डिश (भोजन) से हुई है या फिर इसमें कुछ योगदान वुहान स्थित उस प्रयोगशाला का है, जिसमें खतरनाक वायरसों पर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ विश्लेषकों का अंदाजा है कि वुहान का वायरस लैब असल में जैविक हथियार तैयार करने का अड्डा है, जहां से एकदम नई किस्म का वायरस कोरोना की शक्ल में छिटक कर बाहर आ गया और सबसे पहले चीन को ही इसने अपना निशाना बना लिया। हालांकि ज्यादा ठोस अनुमान यही है कि चमगादड़ों को संक्रमित करने वाला यह वायरस उत्परिवर्तित होकर इंसानों तक जा पहुंचा है। चूंकि मेडिकल साइंस इस वायरस से लड़ने को अभी तैयार नहीं है, इसलिए यह समस्या बड़ी हो गई है। चिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि एक जीव से दूसरे जीव में छलांग लगाने की प्रवृत्ति के कारण इस वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति में आम जुकाम से लेकर गंभीर किस्म की श्वास संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकता हैं।

कितना तैयार है भारत : उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में दक्षिणी चीन के कुछ लोग सार्स (एसएआरएस) से पीड़ित हुए थे और इसके बाद करीब 25 देशों में यह संक्रमण फैल गया था जिससे 800 लोगों की मौत हो गई थी। दावा किया गया कि चीन सरकार ने तब शुरुआत में इसे हल्के में लिया और इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिससे बात हाथ से निकल गई और पूरी दुनिया एक मामूली बीमारी के सामने घुटनों पर आ गई। इसमें भी ज्यादा समस्या भारत जैसे विकासशील देशों के लिए पैदा होती रही है जहां का स्वास्थ्य तंत्र ऐसे मामलों की रोकथाम करने में कई बार नाकाम साबित हुआ है। जैसे करीब दो साल पहले वर्ष 2018 में मलेशिया के बाद पड़ोसी बांग्लादेश में निपाह वायरस की मौजूदगी के बाद भारत में इसके पहुंचने का खतरा था, लेकिन इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय नहीं किए गए, जिसका साफ असर दिखा। केरल जैसे राज्य में तो इसके कारण महामारी का ही संकट पैदा हो गया था। इससे पहले 2017 में जीका वायरस के मामले में भी ऐसी ही लापरवाही दिखी थी। मच्छरों से फैलने वाले जानलेवा जीका वायरस से भारत महफूज नहीं है-इसे लेकर एक आशंका 2016 में ही जता दी गई थी। सितंबर, 2016 में सिंगापुर में 13 भारतीयों में इस वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी और तब कहा गया था कि यहां से इस वायरस के भारत पहुंचने में ज्यादा देर नहीं है।

यह आशंका 2017 में सच साबित हो गई। जनवरी और फरवरी 2017 के बीच अहमदाबाद के तीन लोगों के जीका वायरस से प्रभावित होने की बात सामने आ गई थी, पर गुजरात सरकार इसके बारे में समय रहते सूचना जारी नहीं कर पाई। पहले भी इसी तरह देश में बर्ड फ्लू की सूचनाओं को लंबे समय तक दबाया गया था। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि विकसित देशों के मुकाबले हमारे देश का जो स्वास्थ्य ढांचा व सेहत का सूचना तंत्र इतना लचर है, उसमें कैसे अचानक फूट पड़ने वाले ऐसे वायरसों से लोगों का बचाव हो सकेगा।

समय के साथ चालाक हो रहे वायरस : समस्या का एक पहलू विषाणुओं के ज्यादा चालाक होते चले जाने का भी है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका-साइंस में एक वैज्ञानिक ने लिखा था- जिस तरह इंसानों ने पृथ्वी पर हर परिस्थिति और वातावरण में ढलना सीख लिया, उसी प्रकार वायरसों ने जीवाणुरोधी दवाओं यानी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। कुछ मामलों में तो बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले एंजाइम तक बनाने सीख लिए हैं। इसका एक और सच यह है कि ऐसी भीषण बीमारियों का सामना करने वाले कारगर टीके भी अभी मुकम्मल तौर पर विकसित नहीं हो पाए हैं। जैसे इबोला के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन जेडमैप अभी प्रायोगिक चरण में ही है। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा पर जारी अपनी एक रिपोर्ट में कुछ बरस पहले डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि दुनिया में अब जितनी तेजी के साथ संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, वैसा मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया के खुलते बाजार और देशों के परस्पर सहयोग में इजाफे का एक नतीजा यह निकला है कि कोरोना, सार्स, निपाह, स्वाइन फ्लू और पोलियो के अलावा एचआइवी, मैड काऊ, इबोला और श्वास तंत्र को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों के फैलने की गति बढ़ गई है और यह स्थिति बेहद खतरनाक है। वायरसों को लेकर दुनिया की बड़ी चिंता बात की है कि हाल में ऐसे संक्रामक वायरसों की तादाद में कुछ ज्यादा ही इजाफा हो गया है, जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में छलांग लगाने की काबिलियत रखते हैं।

संक्रमण रोकने में मददगार हो सकते हैं वैक्सीन

वैसे तो हमारे देश में बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण के अहम कार्यक्रम- इंद्रधनुष से गरीब तबके को काफी लाभ हो रहा है, लेकिन कोरोना (वायरल न्यूमोनिया), फ्लू, सार्स, मलेरिया, निपाह आदि कई संक्रामक बीमारियों से बचाव में कारगर टीकों (वैक्सीन) की कम उपलब्धता या उनका नहीं होना एक बड़ा सवाल है। गंभीर बात यह है कि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन वैक्सीन के मोर्चे पर दुनिया में कम ही तरक्की हुई है। असल में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां और उनके कई हितैषी संगठन किसी संक्रामक बीमारी से बचाव में कारगर वैक्सीन के निर्माण में तब तक कोई रुचि नहीं दिखाते, जब तक कि उसमें उन्हें अरबों डॉलर का बिजनेस न दिखे। ऐसा एक उदाहरण चार साल पहले भारत में भी दिखा था।

देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जिस पेंटावेलेंट वैक्सीन को शामिल किया था, उसके इस्तेमाल से 2014 के आरंभ में केरल में कुछ बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद अदालतों ने यह सवाल उठाया कि जिन टीकों का उपयोग विकसित देश खुद नहीं करते, उन्हें भारत जैसे विकासशील देशों में क्यों बेचते हैं और इसके लिए षड्यंत्र क्यों करते हैं। इससे यह भी जाहिर हुआ कि हमारे देश में न तो टीकों के मामले में कोई पारदर्शिता थी और न ही कोई वैक्सीन पॉलिसी थी। इस पूरे विवाद ने वैक्सीन क्षेत्र में जरूरी सुधार की ओर भी ध्यान दिलाया। यह आरोप लगा कि जिन टीकों का निर्माण देश में ही हो सकता था, उन्हें लंबे समय तक विदेशों से कई गुना ज्यादा दामों पर मंगाया जाता रहा। यह बात रोटा वायरस के स्वदेश में विकसित टीके से साबित हुई।

देश में एक कंपनी (भारत बायोटेक) ने सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एड्स की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाले इस वैक्सीन का वर्ष 2013 में विकास कर लिया था। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसकी एक खुराक करीब एक डॉलर में पड़ने लगी, जबकि विदेशी फार्मा कंपनियां इस तरह के टीके की कीमत 300 डॉलर प्रति डोज के हिसाब से वसूल रही थीं। रोटा वायरस के वैक्सीन का देश में ही विकास कर लिए जाने से भारत के वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं का मनोबल भी बढ़ा और उनमें यह विश्वास पैदा हुआ कि दूसरे देशों से दवा या तकनीक मांगने और उनके फार्मूलों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बदले हम खुद भी ऐसे वैक्सीन और दवाएं विकसित कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ संक्रामक बीमारियों के वायरस ऐसे होते हैं जो स्थान विशेष से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उनसे निपटने में विदेशों में विकसित किए गए वैक्सीन हमारे लिए बहुत कारगर नहीं भी हो सकते हैं।

अच्छा होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मार्केटिंग के तौर-तरीकों में मीनमेख निकालने या पेटेंट नियमों की आड़ में होने वाली बेईमानी का रोना रोने के बजाय हमारा देश रिसर्च में ताकत लगाए और हमारे संगठन एवं प्रयोगशालाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ऐसी स्थिति में कोई वजह नहीं है कि हम उन बीमारियों के लिए भी दवाएं और वैक्सीन वगैरह तैयार न कर सकें, जिनकी वजह से यहां ज्यादा मौतें होती हैं।

खरी-खरी

नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल

चेतना भाटी

सोशल वर्कर जी की व्यस्तता देखते ही बनती थी। पहले एक आइडिया उगाओ, फिर विज्ञापन करो उसका। तिथि-समय-स्थान सुनिश्चित होने पर अपनी तैयारियां शुरू। इतनी भारीभरकम तैयारी के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचो। फिर फोटो खिंचवाने की प्रतिस्पर्द्धा में खुद को बनाए रखते हुए प्रथम स्थान पर ही आना। यानी हर फ्रेम में स्वयं का होना आवश्यक है। और एक बार न आ पाएं तो कई बार वही पोज देना होता है। अलग-अलग प्रेस (के) फोटोग्राफर भी तो अलग-अलग समय पर आते हैं ना, तो कई रीटेक देने होते हैं। वर्ना क्या फायदा सामाजिक कार्य का?

खैर! अगले दिन के सभी अखबारों को खंगालने की बारी आती है। इसके बाद कार्यक्रम के कवरेज की फोटो खींचना और उन्हें फोटोशॉप करने की बारी आती है। किसी में नाम तो किसी में अपना फोटो न पाने पर कुढ़ना-गरियाना भी चलता रहेगा साथ ही साथ। और फिर एक अच्छी सी लुभावनी-गर्वीली तथा अपनी महानता दर्शाती पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना होता है फोटोज सहित। फोटो क्रम वही रहेगा रेटिंग अनुसार-सबसे अच्छा और सबसे पहले।

अब शिखर पर पहुंचकर भी चैन कहां, आराम कहां? लाइक्स और कमेंट्स की भिनभिनाहट के कारण। बार-बार चेक करिए फोन और उतने ही मीठे-मीठे, रस में पगे जैम-जैली-मुरब्बे-आइसिंग ऑन केक टाइप रिप्लाय भी दीजिए। उल्लेख कीजिए। यह ध्यान रखते हुए कि किसने नहीं किया है। ओह! उफ्फ!! अब तक तो सांस ही फूलने लगती है। अंगुलियां ही जवाब देने लगती हैं, आंखें सूखती-सी लगती हैं या कभी सीली दीवारों-सी रिसने लगती हैं। लीकेज होने लगता है। सिर तो हैंग हो ही चुका होता है फोन से पहले ही। तो कुल मिलाकर यह कि ये सोशल वर्क नहीं आसां, बस इतना समझ लीजे...वगैरह-वगैरह। अब आप ही समझ लो ना भई। कह तो दिया है-समझ लीजे।

उफ! ये टेक्नोलॉजी, ये सदी भी ना!! जो न कराए, कम है!!! पहले के लोग कितने खुशनसीब हुआ करते थे कि नेकी कर दरिया में डालते और सो जाते लंबी तानकर। उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था। कोई मेहनत नहीं।

ट्वीट-ट्वीट

राहुल गांधी फिर जयपुर से लांच हो रहे हैं। वह आखिर कितनी बार लांच होंगे? उनके लांच-रीलांच की गिनती करना अब मुश्किल है। उनके लिए ऐसा करने वालों के संयम की भी सराहना की जानी चाहिए।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

यह बहस हो सकती है कि अदनान सामी को पद्मश्री मिलना चाहिए था या नहीं, उनके योगदान को लेकर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पिता को इस विवाद में घसीटना ठीक नहीं है। माता-पिता के क्रियाकलापों की सजा अगर बच्चों को मिलने लगे तो पता नहीं यह सिलसिला कहां शुरू होगा और कहां जाकर रुकेगा।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

राजनीति के दो कोरोना वायरस को हमने निष्प्रभावी कर दिया है। शायद उन्होंने सदस्यता का नवीनीकरण भी नहीं कराया। ऐसे राजनीतिक कॉरपोरेट दलाल जो दल और नेता के चेहरे पर अपनी दिल्ली की दलाली और जेब चमकाते हैं वे किसी भी दल के लिए बीमारी से कम नहीं हैं। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल इस बात को समझें।
डॉ. अजय आलोक@alok_ajay

यह देखना बहुत निराशाजनक है कि अनुराग ठाकुर जैसे युवा नेता अपनी चुनावी रैलियों में जहरीले नारे लगवा रहे हैं। इसे देखकर यही लगता है समूची भारतीय जनता पार्टी की यही रीति-नीति बन गई है।
अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अदनान सामी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर सवाल उठाना उचित है?

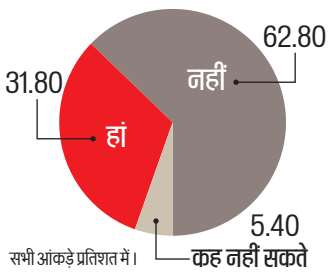

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या दशकों पुराने बोडोलैंड विवाद के अंत होने से पूर्वोत्तर में शांति स्थापना में मदद मिलेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सिब्बल का 'शाहीन' से आखिर क्या है झोल,
पीएफआई दे रहा जिसका इतना मोल!
जिसका इतना मोल लाख पूरे सतहत्तर,
चेहरा उजला और पेट में पाप बहत्तर!!
जिन्हें न प्यारा देश दे रहे हैं उनको बल,
अपना बेच जमीर खा गए अय्यर-सिब्बल।
- ओमप्रकाश तिवारी

कोंकण को रेल की सौगात देने वाले जॉर्ज फर्नांडिस

अभिषेक रंजन सिंह
राजनीतिक विश्लेषक

आज प्रख्यात समाजवादी एवं श्रमिक नेता जॉर्ज फर्नांडिस की पहली पुण्यतिथि है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। उन्हें चाहने वाले कई लोगों का मानना है कि अगर जीवित रहते जॉर्ज साहब को यह सम्मान मिला होता तो बेहतर होता। खैर, इस देश में अकेले जॉर्ज ही ऐसे नहीं हैं जिनकी महत्ता उनकी मृत्यु के बाद लोगों की समझ में आई हो। समाजवादियों का एक बड़ा खेमा जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण दिए जाने को उनका अपमान भी मान रहा है।

वैसे तो जॉर्ज फर्नांडिस की जिंदगी से जुड़े कई रोचक प्रसंग हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रसंग कोंकण रेलवे के निर्माण से जुड़ा है। कोंकण का पूरा इलाका मूलतः पहाड़ी है। प्रायः सभी मौसम में यह क्षेत्र खूबसूरत दिखता है, लेकिन मानसून के समय में अगर आप रेलगाड़ी से गुजरें तो यहां की प्राकृतिक सुंदरता बरबस आपको आकर्षित करेगी। पहले कोंकण इलाके में कोई रेल लाइन नहीं थी। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रेलमंत्री हुए। पदभार संभालते ही उन्होंने रेल अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि कोंकण में रेल लाइन कैसे बिछेगी?

सभी अधिकारियों की अलग-अलग राय थी। किसी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काफी खर्चा आएगा तो किसी ने कहा कि काफी सुरंगें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि यह क्षेत्र काफी उबड़-खाबड़ है। कुल मिलाकर रेल अधिकारियों की राय में कोंकण क्षेत्र में रेल की पटरियां बिछाना घाटे का सौदा था। इसके बावजूद भी जॉर्ज फर्नांडिस ने हार नहीं मानी, क्योंकि कोंकण अंचल में रेलगाड़ी दौड़ाने की उनकी इच्छा उस समय से थी, जब वे मुंबई में ट्रेड यूनियन के नेता थे। उन दिनों मुंबई में कोंकण के काफी मजदूर कल-कारखानों में काम करते थे।

जॉर्ज फर्नांडिस।

जॉर्ज खुद मंगलोर के थे और वहां भी कोई रेल लाइन नहीं थी। मुंबई में जब भी जॉर्ज फर्नांडिस कोंकणवासियों के बीच होते थे तो वे लोग अपने यहां रेलमार्ग न होने का दर्द साझा करते थे।

जॉर्ज साहब के करीबी रहे वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण के मुताबिक वीपी सिंह सरकार में बतौर रेलमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आज के मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध श्रीधरन को बुलाया जो उन दिनों रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजीनियर थे। जॉर्ज ने उन्हें प्रस्तावित कोंकण रेल परियोजना का नक्शा वगैरह दिखाया और कहा कि सभी अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन आप निराश नहीं कीजिएगा! कोंकण रेल परियोजना से संबंधित नक्शे का अवलोकन करने के बाद श्रीधरन ने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा कि कोंकण में रेलगाड़ी दौड़ाने का आपका सपना हम पूरा करेंगे। यह सुनते ही जॉर्ज फर्नांडिस अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और फौरन उन्होंने रेल मंत्रालय के कुछ आला अधिकारियों को बुलाया। घंटे भर के भीतर कोंकण रेल परियोजना का जिम्मा श्रीधरन को सौंप दिया गया।

अगले दिन कोंकण रेल परियोजना और उसके मद में खर्च होने वाली धनराशि को लेकर जॉर्ज फर्नांडिस ने तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते से मुलाकात की। मधु दंडवते ने जॉर्ज से कहा कि हम भी चाहते हैं कि कोंकण रेल का सपना साकार हो, क्योंकि यह प्रोजेक्ट कोंकणवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार में खजाने की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस ने मधु दंडवते से कहा, फिर मैं ही पैसे जुटाने का कोई इंतजाम खुद करूंगा। सप्ताह भर के भीतर 'कोंकण रेल कॉरपोरेशन' नामक एक नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडियन रेलवे ने करवा लिया। उसका इश्यू शेयर मार्केट में जारी हो गया। चौबीस घंटे के भीतर 'कोंकण रेल कॉरपोरेशन' के सारे शेयर बिक गए। इस तरह काफी पैसे इस मद में आ गए। उसके बाद श्रीधरन को जॉर्ज फर्नांडिस ने 'कोंकण रेल कॉरपोरेशन' का अध्यक्ष बना दिया। और इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थापित कर दिया। 1998 तक कोंकण रेल लाइन बनकर तैयार हो गई। 736 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग है कोंकण रेलवे। इस पूरे रास्ते में सौ से ज्यादा सुरंगें हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं।

कोंकण रेलवे के निर्माण ने सही मायनों में श्रीधरन को श्रीधरन बना दिया। देश को उनकी एक बड़ी देन है कोंकण रेलवे और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे जॉर्ज फर्नांडिस ही हैं। खैर, कोंकण रेलवे का सपना तो साकार हो गया। अब न तो जॉर्ज फर्नांडिस हैं और न ही मधु दंडवते, लेकिन यह समझ से परे है कि उस वक्त मधु दंडवते ने कोंकण रेलवे के लिए धनराशि आवंटित क्यों नहीं की, जबकि वे खुद कोंकण स्थित रत्नागिरि जिले के राजापुर लोकसभा से कई बार सांसद रहे चुके थे।

जॉर्ज फर्नांडिस को गुजरे एक वर्ष हो गए। मुमकिन है कि आने वाले कुछ वर्षों में जॉर्ज जैसे जीवट वाले नेताओं को उनके अनुयायी ही भुला दें, लेकिन कोंकणवासियों के लिए जो काम जॉर्ज फर्नांडिस ने कर दिया, शायद वहां के लोग इसे कभी नहीं भुला पाएंगे।

भागीदारी का सवाल

आधी आबादी का प्रतिनिधित्व

कपिल शर्मा
चुनाव संबंधी मामलों के जानकार

2019 के आम चुनावों में रिकार्ड 78 महिला सांसद लोकसभा पहुंची हैं, लेकिन इसके बावजूद आधी आबादी का प्रतिनिधित्व लक्ष्य से बहुत दूर है

ब्रिटिश भारत में मद्रास पहला ऐसा राज्य था जिसने 1921 में महिलाओं को सबसे पहले मत डालने का अधिकार दिया था। भले ही यह अधिकार महिलाओं के एक सीमित वर्ग को मिला था, लेकिन इस कदम ने इतिहास के लिए वह राह खोल दी थी जो आजाद भारत में महिलाओं के मताधिकार के लिए मील का पत्थर बनने वाली थी। देश की आजादी के बाद पहली लोकसभा के गठन से लेकर आज तक महिलाओं का एक छोटा सा समूह संसद तक पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर महिला सांसदों का यह समूह संसद में देश की आधी आबादी के अनुपात में छोटा है और देश की कुल महिला जनसंख्या का बहुत ही सीमित प्रतिनिधित्व है। राज्य विधानमंडलों की भी कमोबेश यही स्थिति है जहां महिला विधायकों और विधान पार्षदों का प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित है।

1990 के बाद से एक नया प्रयोग हुआ और कुछ महिला राजनीतिक दल भी भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हुए। इन दलों में नारी शक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2004 में मुंबई उत्तर से अपने उम्मीदवार को उतारा, लखनऊ लोकसभा सीट से जगनमयी नारी संगठन ने 2009 के आम चुनावों में भागीदारी की।

इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी से महिला अधिकार पार्टी ने अपने उम्मीदवार को टिकट दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में महिला स्वाभिमान पार्टी ने लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार को टिकट दिया। इन महिलावादी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की पत्नी सुमन कृष्णकांत ने संसद में महिला जनप्रतिनिधियों के 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु बहुप्रतीक्षित बिल के न आने पर महिलाओं के मुद्दों पर आधारित एक राजनीतिक दल यूनाइटेड वूमेन फ्रंट को नई दिल्ली में पंजीकृत कराया था। इस राजनीतिक दल के अध्यक्ष का पद केवल महिला सदस्य के लिए आरक्षित था और कोई भी पुरुष राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य नहीं हो सकता था। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रयास था। यूनाइटेड वूमेन फ्रंट ने 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में सभी 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह केवल एक ही उम्मीदवार को उतार पाया था। यूनाइटेड वूमेन फ्रंट ने 2009 के लोकसभा चुनावों में भी भागीदारी की थी। इसी तरह श्वेता शेट्टी की अध्यक्षता में बनाई गई नेशनल वूमेन पार्टी ने साल 2019 में आयोजित 17वें लोकसभा चुनावों में प्रतिभागिता की।

महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के आंकड़े भी देखने लायक हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन लोकसभा आम चुनाव को देखें तो 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 2014 में 13 महिला उम्मीदवार उतारे और 2019 में इसे बढ़ाकर 23 कर दिया। समाजवादी पार्टी ने साल 2009 में आठ, 2014 में 11 और 2019 में छह महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं 2004 के लोकसभा आम चुनावों में कांग्रेस ने 45, 2009 के चुनावों में 43, 2014 के आम चुनावों में 60 और 2019 में 54 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को टिकट देने में अग्रणी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। 2004 में भाजपा ने 30 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। यह संख्या 2009 में 44, 2014 में 38 और 2019 में 55 हो गई। वहीं 2004 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने 20, 2009 के चुनावों में 28, 2014 के आम चुनावों में 27 और 2019 में 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। वामदल सीपीआइ और सीपीएम राष्ट्रीय दल होने के बावजूद महिलाओं को टिकट देने में पीछे रहे हैं। सीपीआइ ने 2004 में दो, 2009 में चार, 2014 में छह और 2019 में चार महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया और इन चारों चुनावों में एक भी महिला उम्मीदवार सीपीआइ की तरफ से जीतकर लोकसभा नहीं पहुंची। सीपीएम ने 2004 में आठ, 2009 में छह, 2014 में 11 और 2019 में 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। राज्य स्तरीय दलों में ओडिशा के बीजू जनता दल ने रचनात्मक कदम उठाते हुए महिला प्रतिनिधियों को 33 फीसद टिकट देने का प्रावधान किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। आजादी के बाद से संसद और राज्य विधानमंडलों में पहुंचने तक महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अभी भी मुल्क की आधी आबादी के लिए मंजिल बहुत दूर है। महिला सुधारों पर कार्य करने वाले संगठन यह बताते रहे हैं कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों में सक्रिय महिला जनप्रतिनिधियों ने कभी महिलाओं के नेतृत्व के प्रसार के लिए संगठित-सक्रिय प्रयास नहीं किए। ज्यादातर राजनीतिक दलों में पुरुषों का बहुमत होने के कारण भी वे महिलाओं के नेतृत्व विस्तार की मांग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आजादी के बाद से यह भी ट्रेंड देखा गया है कि राजनीतिक दलों में लैंगिक असमानता को एक मौन सहमति मिली हुई है।

बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनावों में रिकार्ड 78 महिला सांसद लोकसभा पहुंची हैं जो अभी तक की सर्वाधिक संख्या है, लेकिन इसके बावजूद आधी आबादी का प्रतिनिधित्व लक्ष्य से बहुत दूर है। इसे हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है।

64 मामले सामने आए हैं 2019 में शार्क के अकारण हमले के दुनियाभर में। 2018 में इनकी संख्या 62 थी। हालांकि, इन मामलों में औसतन गिरावट आई है। इससे पहले हर वर्ष औसतन 82 मामले सामने आते थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 जनवरी 2020

बंगाल

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का सवाल

कोलकाता और हावड़ा की गली-गली में उग आए शिक्षण संस्थानों ने पढ़ाई की दिशा चाहे जितनी बदली हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। टिकियापड़ा के ईस्ट-वेस्ट बाइपास से सटे बेलिलियस पार्क इलाके के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सोमवार को चौथी मंजिल पर आग लग गई। इस आग पर भले काबू पा लिया गया, लेकिन घंटों छात्रों और शिक्षकों की सांस अटकी रही। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कई अभिभावक स्कूल पर भी पहुंच गए। शुक्र है कि इस आग को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन अगर हादसे का दायरा बढ़ जाता तो बहुमंजिली इमारत वाले इस स्कूल के बच्चों की हालत का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस हादसे ने सरकार और प्रशासन को चेताने के लिए एक बार फिर दस्तक दी है। कल्पना करने मात्र से मन भयभीत हो जाता है। जब आग लगी तो सभी कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे थे। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार और प्रशासन ऐसे स्कूलों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रही है। क्या स्कूल खोले जाते समय मानक पूरे किए जाते हैं। क्या बच्चों से वसूली जाने वाली मोटी फीस का उपयोग सुरक्षा और सुविधा पर खर्च किया जाता है। या फिर स्कूलों के संचालक इन पैसों से अपनी जेब भर रहे हैं।

गगनचुंबी इमारतों में स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां बच्चों की सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही है। यह उचित नहीं है।

बात सिर्फ स्कूलों की ही नहीं है। महानगरों में आग पर काबू पाने के इंतजाम माकूल नहीं है। दमकल विभाग के सामने लगातार चुनौतियां बनी रहती हैं। यद्यपि अनेक स्थानों पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने समय पर पहुंच कर आग की विनाशलीला पर अंकुश भी लगाया है, लेकिन आम शिकायत यही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से पहुंच नहीं पाती हैं। अगर पहुंच भी गईं तो उनके पास आग बुझाने के आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं। संकरी गलियों में जाने वाले सक्षम वाहनों, बहुउद्देश्यीय अग्निशमन वाहनों, अधिक ऊंचाई पर आग बुझाने वाले यंत्रों, हाई पावर क्रेन, रिकवरी वैन आदि की कमी से पूरा देश जूझ रहा है। ज्यादातर अग्निशमन वाहन पुराने मॉडल के हो गए हैं। जिस तेजी से महानगरों में क्रंकीट के जंगल उगे हैं और गगनचुंबी इमारतों का दायरा बढ़ा है उसके अनुपात में आग बुझाने के संसाधन विकसित नहीं हो सके हैं। ऊपर से संबंधित विभाग के कर्मियों को नई चुनौतियों के अनुपात में प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका है। सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा को लेकर सजग होने की है। जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुमंजिली इमारतों में स्कूल खोले जाएं वहां पर विशेष सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाना चाहिए।

यह एक विडंबना ही है कि आग के मामले में प्राकृतिक जंगल और कंक्रीट के जंगलों यानी शहरों में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, बल्कि शहरों में लगने वाली आग कई मामलों में प्राकृतिक जंगलों से भी भयावह हो गई है। यहां यह बेहद मामूली कारणों से जब-तब भड़क उठती है और हर बार लाखों-करोड़ों की संपत्ति के नुकसान के साथ दर्जनों जिंदगियों को स्वाहा कर डालती है।

पंजाब

टिड्डी दल के हमले से निपटने की तैयारी

अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए पड़ोसी राज्य राजस्थान में सैकड़ों एकड़ जमीन पर फसल को तबाह कर देने वाले टिड्डी दल की पंजाब में दस्तक से पहले ही किसानों के साथ-साथ सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंचनी शुरू हो गई हैं। झटके में खेतों के खेत खाली कर देने वाला टिड्डी दल वैसे राजस्थान और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगते कुछ सीमावर्ती इलाकों बठिंडा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और मानसा इत्यादि में पहुंच भी गया है। यहां पर छोटे-छोटे टिड्डी दल देखे गए हैं। 1993 में भी ऐसे ही छोटे-छोटे टिड्डी दलों ने हमला कर मालवा क्षेत्र में कपास की पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी थी।

रेतीले क्षेत्रों में पैदा होने वाली इन टिड्डियों को भगाने के लिए किसान वैसे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनके हमले को नाकाम करने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके पास इनके हमलों को निष्क्रिय करने के लिए पूरे इंतजामात हैं। विडंबना यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां से यह टिड्डी दल भारत में घुसपैठ कर रहा है, वहां पर इसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। इस पर सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चिंता जताई है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी

प्रतीकात्मक फोटो

लिखकर टिड्डी दल को पाकिस्तान में ही रोकने के लिए दवाब बनाने को कहा है।

यह जमीनी हकीकत है कि पाकिस्तान इन्हें रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है और उल्टा तर्क दे रहा है कि यह हवा के वेग से भारत में घुस रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टिड्डी दल हवा के वेग से चलता है, परंतु कीटनाशकों के उपयोग से इन्हें रोका तो जा ही सकता है। वैसे तो सरकार ने अपने स्तर पर इनके हमलों को निष्क्रिय करने के लिए पूरे प्रबंध किए हुए हैं, परंतु जिन क्षेत्रों में इनके हमले की आशंका है वहां के किसानों को भी किसी अफवाह का शिकार होने की बजाए जागरूक होना पड़ेगा। अपनी खेती को बचाने के लिए किसी पर निर्भर होने के बजाय खुद आगे आना होगा।

वैसे तो सर्दियों में टिड्डियां अपने आप ही खत्म हो जाती थीं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जिस तरह से मौसम का पैटर्न बदला है, उससे टिड्डियों को पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात में ठहरने का अधिक मौका मिल गया है। एलडब्ल्यूओ द्वारा टिड्डी नियंत्रण एवं शोध विषय पर जारी एक डॉक्यूमेंट बताता है कि दुनिया में टिड्डियों की 10 प्रजातियां सक्रिय हैं, इनमें से चार प्रजातियां भारत में समय-समय पर देखी गई हैं। इनमें से सबसे खतरनाक रेगिस्तानी टिड्डी होती है। इसके अलावा प्रवासी टिड्डियां, बांबे टिड्डी और ट्री (वृक्ष) टिड्डी भी भारत में देखी गई हैं।

इस बार जो प्रजाति सक्रिय है, वह रेगिस्तानी टिड्डी है। एक वयस्क टिड्डी की रफ्तार 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। वह प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक हवा के साथ उड़ सकती है। ये टिड्डियां किस कदर नुकसानदायक हो सकती हैं, इसका अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है कि इन टिड्डियों का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट या 3000 आदमियों के बराबर खाना खा सकता है। यह लगभग 20 से 30 मिनट में सारा खेत चटकर जाती है उसके बाद केवल फसल के अवशेष डंठल के रूप में रह जाते हैं।

जम्मू- कश्मीर

असमंजस दूर करे सरकार

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में नई फार्मेसी काउंसिल को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा होना स्वभाविक है। अभी तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस कारण सैकड़ों युवाओं को भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। विगत दिवस मेडिकल असिस्टेंट का प्रशिक्षण हासिल करने वाले कई युवाओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। सर्वविदित है कि पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य की अपनी फार्मेसी काउंसिल थी। इसमें मेडिकल असिस्टेंट का प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं को भी दवाइयों की दुकानें खोलने के लाइसेंस जारी कर दिए जाते थे। जो केंद्र सरकार के फार्मेसी काउंसिल के नियमों के विपरीत था।

इस समय राज्य में दवाइयों की जितनी दुकानें हैं, उनमें से 80 प्रतिशत वही युवा चला रहे हैं जो कि मेडिकल असिस्टेंट हैं या उन्हें अनुभव के आधार पर लाइसेंस मिला है। इस समय सैकड़ों युवा इसी उम्मीद में कोर्स कर रहे हैं कि अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तब भी वे दवाइयों की दुकान खोल

प्रतीकात्मक फोटो

सकते हैं। और अपनी रोजी-रोटी चला सकते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नए नियमों को लेकर असमंजस बना हुआ है।

होना तो यह चाहिए था कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ही नए नियमों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जाती या फिर संबंधित कार्यालयों में सूचनात्मक नोटिस बोर्ड लगाए जाते। विडंबना है कि किसी ने भी इस दिशा में कुछ नहीं किया और युवाओं के आक्रोश को पनपने का अवसर दे दिया। ड्रग कंट्रोल विभाग को चाहिए कि वह एक बारे में युवाओं के समक्ष नए फार्मेसी काउंसिल के नियमों पर स्थिति स्पष्ट करे ताकि उन्हें दरबदर नहीं होना पड़े।

जो युवा अभी भी इसी उम्मीद में मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें भी अपने भविष्य पर फैसला लेने के लिए समय मिल सके। यही नहीं जो दुकानदार यहां पर पहले से दवाइयों की दुकानें कर रहे हैं, उन पर इसका क्या असर होगा, इस पर भी विस्तार से जानकारी देने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो इससे युवाओं के मन में उलझन खत्म होगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। वहां रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले न कि नियमों की अस्पष्टता की स्थिति में रोजगार से हाथ धोना पड़े।

उत्तराखंड

कब पूरी होगी पर्यटन प्रदेश की उम्मीद

उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बात चाहे टिहरी झील को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करने की हो अथवा होम स्टे योजना या फिर औली को विंटर डेस्टिनेशन बनाना। सरकार ने पौड़ी जिले के खिर्सू में 'बासा' नाम से होम स्टे योजना को मूर्त रूप देना भी शुरू कर दिया है। इसी की अगली कड़ी में उन स्कूल भवनों को भी होम स्टे योजना के तहत लाने का है जो कम छात्र संख्या के कारण बंद हो गए हैं। इन भवनों में विभिन्न सुविधाएं मुहैया करा कर यात्रा व ट्रैकिंग रूट पर इस्तेमाल किया जाएगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्यटन विकास की ये योजनाएं अच्छी हैं। यदि इन पर काम किया गया तो निश्चित ही परिणाम सकारात्मक होंगे। लेकिन तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी गौर करने की आवश्यकता है। पर्यटन के विकास को लेकर बन रही तमाम नीतियां के बीच कुछ सवाल तैर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीस साल से बन रही योजनाओं की स्थिति क्या है। मसलन लंबे समय से खिर्सू पर्यटन सर्किट की बात की जा रही थी, लेकिन यह अब भी सपना बना हुआ है। महाभारत पर्यटन सर्किट का कार्य कहां तक पहुंचा। इस बारे में भी जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं पर्यटन के नाम पर जो आयोजन कराए भी गए वहां भी अव्यवस्थाओं के आरोप लगते रहे। पिछले साल टिहरी में हुए झील महोत्सव के आयोजन हो या औली में हुई अल्पाइन स्कीइंग, इन आयोजनों में यही स्थिति रही। झील महोत्सव में महज सात प्रदेशों की टीम सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए पहुंची थी। बावजूद इसके टिहरी पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बेहद कम रही।

पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार के स्तर पर की जा रही कवायद तभी परवान चढ़ेगी, जब योजनाएं जमीन पर आकार लेने लगेंगी।

औली में अल्पाइन स्कीइंग का है। वर्ष 2011 के बाद यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई भी आयोजन नहीं हो पाया। बीच में इक्का-दुक्का प्रतियोगिताएं अवश्य हुईं, लेकिन वे बड़े स्तर की नहीं थीं। इस बार यहां राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जा रहा है। कुदरत भी मेहरबान है, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर औली में जनवरी में अच्छा हिमपात होता है। ऐसे में आयोजन की तिथियां फरवरी और मार्च में तय करने का क्या औचित्य है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यटन क्षेत्र को लेकर जिस गंभीरता की जरूरत है, वह अभी नजर नहीं आ रही है। पर्यटन इस प्रदेश की आर्थिकी का बड़ा आधार है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, आयोजन हों या योजनाएं वे खानापूरी न बनें।

भारत के पर्यटन क्षेत्र में जीडीपी के लगभग पांच प्रतिशत के बराबर योगदान की संभावनाएं हैं। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तो लाखों-करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकता है। अफसोस की बात यही है कि इन अवसरों को भुनाने की दिशा में हमारी कोशिशें उतनी दमदार नहीं हैं।

टिड्डी दल के मामले में कैप्टन ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- कहा, पाकिस्तान सरकार के समक्ष भारत उठाए मामला
- पंजाब के कुछ इलाकों में फसलों पर हमले पर जताई चिंता

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि टिड्डी दल के हमले के मामले में वह दखल दें। प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय को निर्देश दें कि वह पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग को यह मामला पाक सरकार के पास उठाने को कहे। कैप्टन ने राजस्थान की सरहद के साथ लगते दक्षिणी पंजाब के कुछ इलाकों में टिड्डी दल द्वारा फसलों पर किए हमले को लेकर चिंता जताई है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि टिड्डी दल पड़ोसी मुल्क से उत्पन्न हो रहा है। राजस्थान में फसलों पर इस दल का लगातार हमला हुआ है। दक्षिणी पंजाब के कुछ इलाकों में भी ये दल दाखिल हो गए हैं। हालांकि राजस्थान इस पर काबू पाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके कंट्रोल का सबसे कारगर उपाय इसके प्रजनन क्षेत्र का उपयुक्त बंदोबस्त करना है, जो संयोग से पाकिस्तान के साथ लगते मरुस्थल क्षेत्र में पड़ता है।

कैप्टन ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार के पास उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

आर्गेनाइजेशन (एफएओ) को भी टिड्डी दल के प्रजनन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में प्रभावशाली कदम उठाने को कहा जा सकता है। जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि फसलों की तबाही करने वाला यह खतरनाक दल पैदा ही न हो। एफएओ वैश्विक स्तर पर टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए काम करता है।

रामनगर डिवीजन में हाथियों और हल्द्वानी में बाघों की सेहत बेहतर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी

- हल्द्वानी डिवीजन में तीन साल में एक भी बाघ की मौत नहीं
- रामनगर डिवीजन में केवल दो हाथियों की मौत

जंगल में बाघ, हाथी और गुलदार की मौत वन विभाग से लेकर वन्यजीव प्रेमियों तक को चिंता में डाल देती है, लेकिन यहां सुकून देने वाली बात यह है कि बाघों के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग और हाथियों के लिए रामनगर डिवीजन बेहतर साबित हो रहे हैं। पिछले तीन साल में हल्द्वानी डिवीजन में बाघ की मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि रामनगर डिवीजन में सबसे कम दो हाथियों ने जान गंवाई है।

राज्य में वेस्टर्न सर्किल के तहत तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी, तराई केंद्रीय, रामनगर व हल्द्वानी वन प्रभाग आते हैं। इन वन प्रभागों में पिछले तीन साल में बाघ, गुलदार व हाथियों की मौत से संबंधित विभागीय आंकड़े काफी हद तक राहत देने वाले हैं। तीन साल में तराई पश्चिमी डिवीजन में सबसे ज्यादा चार बाघों ने अपनी जान गंवाई, जबकि हाथियों के लिहाज से तराई केंद्रीय का जंगल ज्यादा चिंताजनक रहा। यहां दस हाथियों की मौत हुई। वहीं, तराई पूर्वी में सबसे ज्यादा 12 गुलदार जिंदगी की जंग हार गए। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी में पांचों वन

प्रतीकात्मक

प्रभागों ने माना है कि तस्करी से ज्यादा आपसी संघर्ष वन्य जीवों की मौत का सबब बना।

इस वन प्रभाग का हिस्सा गौलापार से शुरू होकर चंपावत तक फैला है। वेस्टर्न सर्किल का यह सबसे दुर्गम डिवीजन है। 1872 में अस्तित्व में आने की वजह से सबसे पुराना डिवीजन भी इसे कहा जाता है।

तराई केंद्रीय में हाथी के लिए घातक ट्रेन : पिछले तीन साल में हाथियों की मौत के सबसे ज्यादा दस मामले तराई केंद्रीय डिवीजन में सामने आए। चार हाथियों की मौत ट्रेन से कटकर हुई थी, जिसके बाद वन और रेलवे महकमे ने हाथियों की सुरक्षा के लिए काफी मंथन भी किया था।

तस्करी नहीं आपसी संघर्ष ज्यादा : पिछले तीन साल में वन्यजीवों की मौतों की अधिकांश वजह आपसी संघर्ष के साथ बीमारी भी मानी गई है। बीते सप्ताह नैनीताल व रामनगर डिवीजन के एक-एक गुलदार आपसी संघर्ष में मारे गए थे।

मौतों का आंकड़ा

डिवीजन	हाथी	बाघ	गुलदार
हल्द्वानी	3	0	5
तराई पूर्वी	3	1	12
तराई केंद्रीय	10	3	5
रामनगर	2	2	3
तराई पश्चिमी	6	4	9

उत्तराखंड कांग्रेस में अपनों से दो-दो हाथ की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- प्रदेश में कांग्रेस के भीतर गुटीय खींचतान की नई पटकथा तैयार
- क्षत्रपों के बीच वार-पलटवार ने बनाए पार्टी के भीतर जंग के हालात

उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में कांग्रेस क्षत्रप एकदूसरे से दो-दो हाथ करने को आतुर हैं। प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी के गठन के साथ ही गुटीय खींचतान की नई पटकथा को अंजाम देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन कोशिशों के निशाने पर प्रदेश संगठन और विधानमंडल दल का नेतृत्व है। दबाव की इस रणनीति और इस पर किए जा रहे पलटवार ने पार्टी के भीतर जंग के नए हालात तैयार कर दिए हैं। ऐसे में पार्टी के सामने क्षत्रपों को साधने और उन्हें एकजुट रखने की चुनौती बढ़ गई है।

वर्ष 2016 में बड़ी टूट झेलने के साथ प्रदेश की सियासत में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस दोबारा मजबूत होगी या फिर एक ओर टूट की ओर बढ़ेगी, सियासी हलकों में यह सवाल तेजी से तैरने लगा है। प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी को लेकर असंतोष के बहाने बन रहे हालात पार्टी के माथे पर बल डाल रहे हैं। वजह ये है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद राज्य की सियासत में मजबूत स्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस तरस गई है। निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजों ने कुछ उम्मीद भले ही जगाई, लेकिन इनके बूते पार्टी मजबूती से ताल ठोकने की स्थिति में कहीं नहीं ठहरती। प्रदेश संगठन और विधानमंडल दल के नेतृत्व की ओर से सभी को साथ रखने के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन मनमुटाव तल्ख नाराजगी के रूप में गाहे-बगाहे फूट रहा है। पार्टी के मजबूत समझे जाने वाले क्षत्रपों की ओर से बार-बार संगठन को समानांतर ताकत का अहसास कराया जा रहा है। असंतोष के सुरों के जब चाहे तेज होने से प्रदेश में संगठन और विधानमंडल दल नेतृत्व की मुश्किलें और दुविधा दोनों बढ़ गई हैं। प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को भी असंतुष्ट निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे हैं। इसे अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दबाव की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानमंडल दल नेता इंदिरा हृदयेश ने जिस तरीके से असंतुष्टों पर पलटवार किया है, उससे आने वाले समय में पार्टी की सियासत और गर्माना तय है।

पटना हाई कोर्ट ने दिए यूजीसी सचिव को हाजिर होने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों द्वारा यूजीसी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देने पर पटना हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिए जाने को लेकर अदालत में कई बार सुनवाई हो चुकी है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि जब उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया ही नहीं जाता है तो अनुदान और सहयोग देने का क्या मतलब? वेटरन फोरम की लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि यूजीसी द्वारा कॉलेजों को दिए गए अनुदान के खर्च करने से संबंधित प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया। इससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की आशंका बलवती होती है।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि यूजीसी ने अनेक कॉलेजों को अनुदान दिया, लेकिन कॉलेजों ने खर्च की जानकारी नहीं दी। जबकि नियमानुसार राशि के खर्च होने पर

प्रतीकात्मक

कॉलेजों को खर्च का पूरा ब्योरा यूजीसी को देना पड़ता है। याचिका में यह भी बताया गया कि लगभग 287 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हो चुकी है। यह गड़बड़ी वर्ष 2007 से 2017 के बीच की है।

हालांकि, इसके पहले यूजीसी की ओर से यह सफाई दी गई कि अभी तक 270 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेना जरुरी नहीं है। अदालत में इस मामले पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

घातक दवा निर्माण के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार तलब

पटना : हाई कोर्ट ने मंगलवार को मानव स्वास्थ्य के लिए घातक दवाएं बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने पर केंद्र एवं राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। इन दवाओं को कुछ कंपनियां धड़ल्ले से बाजार में बेचती भी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने ऐसे मामले पर हैरानी जाहिर की। प्रज्ञा भारती संस्था द्वारा इस विषय पर एक लोकहित याचिका दायर की गई थी।

अदालत को याचिका के माध्यम से बताया गया कि अनेक प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक हैं। खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों को लाइसेंस कैसे दे दिया जाता है। कोर्ट ने वैसे जिम्मेदार अधिकारियों का नाम भी पूछा है। अदालत ने पूछा है कि ये कौन अधिकारी हैं जो लाइसेंस देने में सावधानी नहीं बरतते हैं।

पीसीओएस से ग्रस्त मरीजों का एक ही स्थान पर बेहतर उपचार

पुनीत शर्मा, रोहतक

- पीजीआइएमएस में प्रति माह के प्रथम गुरुवार को लगाया जाएगा क्लीनिक
- देश में अभी तक मुंबई में संचालित किया जा रहा है पीसीओएस क्लीनिक
- रोहतक की हेल्थ विवि के कुलपति क्लीनिक का औपचारिक शुभारंभ करेंगे

देश में मुंबई के बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) क्लीनिक शुरू करने के लिए हरियाणा के रोहतक स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पीजीआइएमएस) के अधिकारियों ने कदम बढ़ाए हैं। क्लीनिक शुरू करने का उद्देश्य विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को एक ही क्लीनिक में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। उक्त क्लीनिक में विभिन्न विभागों के आठ विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहकर मरीजों का उपचार करेंगे। अभी तक पीसीओएस क्लीनिक केवल मुंबई में है। बताया जा रहा है कि फरवरी माह में हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. ओपी कालरा क्लीनिक का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बायो केमिस्ट्री विभाग द्वारा गायनी विभाग की ओपीडी में पीसीओएस क्लीनिक का शुभारंभ करने की तैयारी है। क्लीनिक का संचालन प्रत्येक माह के प्रथम बृहस्पतिवार को किया जाएगा। क्लीनिक में गायनोकोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूट्रीशियन, साइकोलॉजी और जेनेटिक्स एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ एमआयू के लैब टेक्नीशियन विपुल शर्मा और

हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआइएमएस। फाइल

नीतू मौजूद रहकर मरीजों का उपचार करेंगे। क्लीनिक शुरू करने का उद्देश्य मरीजों की परेशानी कम करने के साथ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। इसके अलावा क्लीनिक के माध्यम से जीवन में व्यायाम को एकीकृत करने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम सीरीज तैयार की जाएगी। अभी तक देश में केवल मुंबई में पीसीओएस क्लीनिक संचालित किया जा रहा है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. ओपी कालरा के निर्देश पर बायो केमिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष और एमआरयू यूनिट की नोडल अधिकारी डा. शिम्मी खरब, गायनी विभागाध्यक्ष डा. स्मिति नंदा और डा. वंदना के निर्देशन में क्लीनिक शुरू किया गया है। क्लीनिक में आने वाले मरीजों की पूरी जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी।

क्या होती है पीसीओएस बीमारी : पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोनल असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसमें महिला के शरीर के मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और अंडाशय पर एक से अधिक सिस्ट होने लगते हैं। जिसके चलते कई बार महिलाओं को गर्भधारण में भी परेशानी आती है। ऐसे महिलाओं के उपचार के लिए क्लीनिक का ओपीडी कार्ड पीजीआइ के ओपीडी कार्ड से अलग होगा।

पीसीओएस के लक्षण

पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रस्त महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म, वजन का लगातार बढ़ना, अनचाहे अंगों पर बालों का उगना, त्वचा संबंधी समस्या, व्यवहार या स्वभाव में बदलाव होना, बार-बार गर्भपात होना या डिप्रेशन या एंग्जायटी प्रमुख है। ऐसी महिलाओं को एक स्थान पर उचित उपचार के साथ पोषित आहार खाने और खाने की दिनचर्या के बारे में अवगत कराने के लिए न्यूट्रीशियन की भी तैनाती की जाएगी।

पीसीओएस क्लीनिक शुरू करना संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। गायनी विभाग की अध्यक्ष डा. स्मिति नंदा और बायो केमिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष डा. शिम्मी खरब के निर्देशन में क्लीनिक का संचालन शुरू करने की तैयारी है। देश में अभी तक केवल मुंबई में उक्त क्लीनिक का संचालन किया जाता है। इसके लिए दोनों विभागों की विभागाध्यक्ष और उनकी टीम बधाई की पात्र हैं।

- डॉ. ओपी कालरा, कुलपति, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय।

1 प्रतिशत भारत के सबसे अमीर लोगों के पास 95.3 करोड़ लोगों से चार गुना ज्यादा धन है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

15 हजार साल पहले के वायरस हो सकते हैं सक्रिय

चीन में कोरोना वायरस के चलते दुनिया चिंतित है, लेकिन वैज्ञानिकों का नया शोध दुनिया के संभावित और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने तिब्बत में 15 हजार साल पुराने वायरस के समूह का पता लगाया है। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी द्वारा संचालित बॉयो आर्काइव डाटाबेस से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है और ये वायरस बाहर आ रहे हैं। आशंका है कि इससे बरसों पुरानी बीमारियां फिर से दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं।

यहां छिपे हैं वायरस

उत्तर पश्चिम तिब्बत के पठारों में स्थित एक बड़े ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है। शोधकर्ता बताते हैं कि यहां पर कभी न देखे गए 15 हजार साल पुराने वायरस मौजूद हैं। ग्लेशियर के मूल तक जाने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के पठारों को करीब 50 मीटर तक ड्रिल किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जब ग्लेशियरों की बर्फ पिघलेगी और यह वायरस बाहर आएंगे तो यह दुनिया के लिए बड़ा संकट होगा। यह कई तरह की बीमारियों के कारण बन सकते हैं।

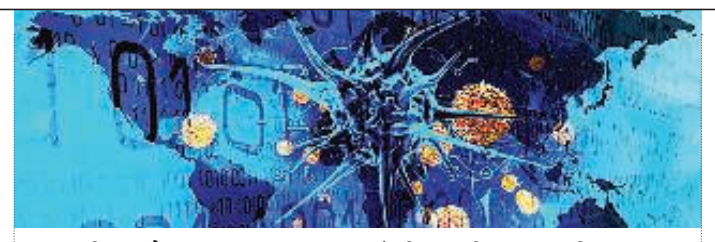

वायरसों का है समूह

यह 33 वायरसों का समूह है। यह 520 से 15 हजार साल पुराने हैं। जिन्होंने इस बर्फीले इलाके को अपना घर बना लिया है। चिंता की बात है कि इन 33 में से आधुनिक विज्ञान महज 5 के बारे में जानता है। जबकि 28 ऐसे हैं, जो विज्ञान के लिए नए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि बर्फ में दबे होने के कारण यह वायरस अलग-अलग जलवायु में खुद को जिंदा रख सके हैं।

दो नमूने, एक नतीजा

अमेरिका से तिब्बत पहुंची वैज्ञानिकों की टीम ने 1992 और 2015 में ग्लेशियर से नमूने लिए थे। इनमें ग्लेशियर के टुकड़ों को ठंडे कमरों में रखा गया था। जहां एक को इथेलॉन से साफ किया गया और दूसरे को साफ पानी से धोया गया। ग्लेशियर की बाहरी परत हटते ही 15 हजार साल पुराने वायरस सामने आ गए।

जलवायु परिवर्तन बढ़ाएगा मुश्किल

जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न मंचों से आवाज उठती रही है, लेकिन ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने में हम कामयाब नहीं हो सके हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंटार्कटिका में ग्लेशियरों का पिघलना बहुत तेज है। 1980 की तुलना में यह 2019 में छह गुना तेज हो चुका है। जिसका प्रभाव कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। जलवायु परिवर्तन को तिब्बती पठार को प्रभावित करने वाला माना जाता है और यह 1970 के बाद से अपनी एक चौथाई बर्फ खो चुका है। यदि इसे नहीं रोका गया तो शेष दो तिहाई ग्लेशियर सदी के अंत तक खो सकते हैं।

ऐसे समझिए खतरे की विभीषिका

2016 में रूस के ध्रुवीय इलाके में एंथ्रेक्स फैला। जैविक युद्ध लड़ने में सक्षम फौज उतारनी पड़ी। 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराने पड़े। कुछ की मौत हुई। 1000 से अधिक रेंडियर भी मरे। दरअसल 70 साल पहले एक संक्रमित रेंडियर के दफनाए शव से ये वायरस फैला था। इतने साल बाद जब उ. साइबेरिया में लू चली तो ये वाइरस फिर से सक्रिय हुआ। रेंडियर की लाश से एंथ्रेक्स फैलने की वजह रूसी वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग बताई।

यहां वसंत पंचमी पर रहती है दशहरे सी धूम

जागरण विशेष ▸ लाखों की लागत से बनते हैं पंडाल, चार दिनों तक रहती है रौनक

बारसोई में है ऐतिहासिक नील सरस्वती मंदिर

नंदन कुमार झा, कटिहार

अंग-बंग व मिथिलांचल की मिश्रित संस्कृति वाले बिहार के कटिहार जिले में वसंत पंचमी पर दशहरे के जैसी धूम रहती है। दशहरे की तर्ज पर ही यहां सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। चार दिनों तक मेले जैसा नजारा रहता है। सरस्वती पूजा पर यहां पांच से लेकर 25 लाख रुपये तक की लागत से विशाल और भव्य पंडालों का निर्माण कराया जाता है। जिले में औसतन 350 से अधिक पंडालों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है।

कालीदास पहुंचे थे नील सरस्वती मंदिर : बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण यहां पूरे आयोजन पर मिश्रित संस्कृति की झलक दिखती है। पूजा का आयोजन वैदिक पद्धति से होता है। बंगाल के ढाक की थाप और परिधानों से त्योहार का रंग और गहराता है। लोगों की आस्था का कारण बारसोई का नील सरस्वती मंदिर भी है। मान्यता है कि यहां पहुंचकर कालीदास ने मां की पूजा-अर्चना की थी। कई अन्य स्थानों पर भी यहां मां सरस्वती के मंदिर हैं।

कई जगहों पर लगता है मेला : वसंत पंचमी को लेकर यहां वृहत तैयारी की जाती है। आयोजन में अंग-बंग और मिथिलांचल की अलग-अलग संस्कृतियों का अनूठा रंग इसकी विशेषता को बढ़ाता है। इसके साथ ही ढाक की थाप पर महाआरती और विविध आयोजनों के कारण लोगों की भीड़ जुटती है। यहां स्थानीय ही नहीं, दूर-दराज से भी लोग आयोजनों में शामिल होने के लिए आते हैं। इस दौरान कई स्थानों पर मेला का भी आयोजन किया जाता है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

बारसोई प्रखंड के बेलवा गांव में नील सरस्वती मंदिर में स्थापित प्रतिमा। जागरण

एक माह पूर्व से बनते हैं पंडाल

सरस्वती पूजा को लेकर यहां एक माह पूर्व से तैयारी शुरू हो जाती है। बंगाल के कारीगरों द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाता है। जबकि कई स्थानों पर प्रतिमा निर्माण के लिए यहां बंगाल से कारीगर पहुंचते हैं। रायगंज, मालदा, कालियागंज आदि स्थानों से भी प्रतिमा मंगाई जाती है। दो हजार से लेकर एक लाख तक की प्रतिमा पंडालों में स्थापित होती है। वृहत आयोजन के कारण सरस्वती पूजा भी यहां दशहरे की तर्ज पर मनाया जाता है। बिनोदपुर, दुर्गास्थान, ओटीपाड़ा, ड्राइवर टोला समेत अन्य स्थानों पर भव्य पंडाल का निर्माण होता है।

कटिहार में डीएस कॉलेज में तैयार भव्य पंडाल। जागरण

ब्रज में कल से बहेगी वसंती बयार

जागरण संवाददाता, मथुरा : ब्रज में वसंत पंचमी का अलग ही महत्व है। इस दिन प्रकृति तो अंगड़ाई लेगी ही, ब्रज में 40 दिवसीय फाग महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। मंदिरों में अबीर गुलाल उड़ाया जाएगा। ब्रज में राधारानी और ठाकुर जी के होली खेलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रसिया गायन शुरू होंगे। श्रीकृष्ण जन्मस्थान, बरसाना, नंदगांव, द्वारिकाधीश मंदिर और गोवर्धन में 30 जनवरी को होली का डांढ़ा (जिस स्थान पर होली जलाई जाती है, उस जगह लगाई जाने वाली लकड़ी) गाड़े जाने के साथ ही उत्सव शुरू हो जाएगा।

होली में बरसाना के लाडिलीजी मंदिर और नंदगांव स्थित नंदभवन में होली की छटा देखते ही बनेगी। इन दोनों जगहों पर भी वसंत पंचमी (30 जनवरी) को होली का डांढ़ा गाड़ दिया जाएगा। सेवायत ठाकुर जी को गुलाल लगाकर रंग महोत्सव की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ पारंपरिक 40 दिवसीय समाज गायन शुरू हो जाएगा। हालांकि, बलदेव के दाऊ जी मंदिर में 29 जनवरी को डांढ़ा गाड़ा जाएगा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान स्थित केशवदेव मंदिर में 30 जनवरी को शाम चार बजे से वसंती कमरा सजाया जाएगा। ठाकुरजी को पीले वस्त्र धारण कराए जाएंगे। बलदेव का हुरंगा प्रसिद्ध है। दाऊजी मंदिर में 29 जनवरी से फाग महोत्सव आरंभ होगा। ठाकुरजी के समक्ष गुलाल धरने के साथ रसिया गायन आरंभ हो जाएगा।

गोवर्धन में ठाकुर जी को 29 जनवरी को गुलाल लगाकर होली महोत्सव शुरू होगा, लेकिन डांढ़ा 30 जनवरी को गाड़ा जाएगा। वृंदावन में सुबह 8.45 बजे सेवायत ठाकुर बांके बिहारी के गुलाल लगाएंगे। उसी दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालु होली खेलेंगे।

बनाया उम्मीदों का सोलर प्लांट

पौड़ी गढ़वाल के धीरेंद्र ने गांव की बंजर जमीन पर लगाया सोलर प्लांट

गुरुवेंद्र नेगी, पौड़ी

कुछ अपना करेंगे...। आज हर युवा में इसकी चाहत क्यों बढ़ रही है, यह कोई धीरेंद्र सिंह रावत से समझे। 31 साल तक राष्ट्रीय राजधानी के नोएडा-दिल्ली में अंतहीन संघर्ष के बाद गांव लौटे तो गांव में सोलर प्लांट लगाया। आज यह प्लांट न केवल उनके, बल्कि के गांव और आसपास के लोगों के लिए भी नई उम्मीदें बना है।

53 वर्षीय धीरेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ग्राम ओड्डा के रहने वाले हैं। वह बताते हैं कि बचपन बेहद गरीबी में बीता। 11 वर्ष की उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, सो 16 वर्ष की उम्र में रोजगार के लिए नोएडा की राह पकड़ ली। वहां कभी पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी की तो कभी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हाथ आजमाया। 31 साल नोएडा-दिल्ली की खाक छानते रहे और जब वर्ष 2011 में गांव वापस लौटे तो सारी जमा पूंजी गांव के विकास में लगा दी। वर्ष 2015 में गांव के समीप बंजर भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित किया। आज 500 किलोवाट के इस सोलर प्लांट में प्रतिवर्ष सात लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह बिजली यूपीसीएल (उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड) को बेची जाती है, जिससे धीरेंद्र को प्रतिमाह चार लाख रुपये की आमदनी हो रही है। सोलर प्लांट को स्थापित करने में सात करोड़ से अधिक की लागत आई। इसके लिए बैंक से भी 2.80 करोड़ का ऋण लिया। अब इसका बड़ा हिस्सा चुकाया जा चुका है।

सोलर प्लांट में गांव के संजय, सोबन, शाकंबरी व जगदीश समेत कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। धीरेंद्र बताते हैं कि महिलाओं को फिलहाल चार हजार रुपये और पुरुषों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। अब उनकी कोशिश इस प्रोजेक्ट में तीन दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार देने की है।

पत्नी ने नहीं डिगने दिया हौसला : धीरेंद्र बताते हैं कि सोलर प्लांट लगाने में उनके सामने कई समस्याएं आईं, लेकिन, पत्नी शकुंतला रावत ने उन्हें हमेशा हौसला दिया। यही वजह है कि वह पहाड़ की खुशहाली के लिए दोगुने जोश के साथ कार्य कर रहे हैं। बताते हैं कि अब वह फल व पुष्पोत्पादन के जरिये भी लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं।

जनसंख्या नियोजन

कोट ब्लॉक के ओड्डा गांव के समीप लगाया गया 500 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट। जागरण

जल संचय को बनाया एक लाख लीटर क्षमता का टैंक

कोट निवासी सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी बताते हैं कि धीरेंद्र के कदम यहीं नहीं थमे। उन्होंने गांव के समीप ही बरबाद हो रहे प्राकृतिक स्रोत के पानी को एकत्रित करने के लिए एक बड़ा टैंक बनाया। इस टैंक में हर समय एक लाख लीटर से अधिक पानी जमा रहता है। इसका उपयोग वह फलोद्यान और फुलवारी की सिंचाई के लिए करते हैं। इसके अलावा उनकी अब एक रिसॉर्ट खोलने की योजना भी है। ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।

धीरेंद्र सिंह रावत। जागरण

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

ट्रकों को गैस से चलाने को देश में बनेंगे 340 एलसीएनजी स्टेशन

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी

▸ **तीन हजार करोड़ की योजना, पहले चरण में वाराणसी, पटना, कोलकाता व भुवनेश्वर में होंगे कार्य**

तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वर्णिम चतुर्भुज, साउथ व वेस्ट कॉरिडोर पर गैस से बस व ट्रक संचालित करने के लिए देश में 340 एलसीएनजी (लिक्विफाइड कांफ्रेंसिव नेचुरल गैस) स्टेशन बनाएगा। वाराणसी स्थित गेल इंडिया लिमिटेड को मंत्रालय ने पत्र भेजकर 2500 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। योजना के तहत पहले चरण में वाराणसी, पटना, कोलकाता व भुवनेश्वर में एलसीएनजी स्टेशन बनने हैं। स्टेशनों के निर्माण पर 3000 करोड़ खर्च होने की बात है। एक स्टेशन की क्षमता करीब 80 हजार लीटर की होगी।

चीन व अन्य यूरोपीय देशों में एलसीएनजी से वाहनों का संचालन सफल है। डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में 2035 तक वाहनों में 14 मिलियन मीट्रिक टन नेचुरल गैस खपत करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हाईवे पर हर 100 किलोमीटर पर एक एलसीएनजी स्टेशन बनेंगे। एलसीएनजी से लंबी दूरी के ट्रक या बस के संचालन से करीब 20 प्रतिशत खर्च की बचत होगी। साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। गेल के उप महाप्रबंधक गौरीशंकर मिश्र ने बताया कि गेल ने जिला प्रशासन को जमीन के लिए पत्र लिखा है। साथ ही गेल भी अपने स्तर पर भूमि तलाश रही है।

यह है एलसीएनजी : एलसीएनजी द्रव की अवस्था में वाहनों के टैंक में भरा जाएगा। जब वाहन के इंजन चलने शुरू होंगे तो इंजन में लगी किट उसे गैस में परिवर्तित कर देगी। इस प्रक्रिया में खर्च कम आएगा।

केंद्र सरकार की यह बहुत ही स्वर्णिम योजना है। इसके तहत देश के विभिन्न हाईवे पर 340 एलसीएनजी स्टेशन बनेंगे। पहले चरण में स्टेशन खोलने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। स्टेशन के खुलने के बाद डीजल से निर्भरता कम होगी साथ ही पर्यावरण का भी संरक्षण होगा।

– एसएन यादव, मुख्य महाप्रबंधक गेल इंडिया लिमिटेड, वाराणसी

अल्मोड़ा से रहा है पद्मश्री थुरमन का नाता

दीप बोरा, अल्मोड़ा

▸ **दो साल तक कसारदेवी बौद्ध मठ में रहकर ली थी दीक्षा**

▸ **हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री हैं बेटी उमा, भारत को बताती हैं दूसरा घर**

साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए अमेरिकी मूल के रॉबर्ट थुरमन का उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से भी गहरा नाता रहा है। इंडो-तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर रह चुके थुरमन ने कसारदेवी स्थित बौद्ध मठ में करीब दो वर्ष तक बौद्ध धर्म की दीक्षा हासिल की है। यहां थुरमन के साथ उनकी पत्नी नीना वॉन भी आईं और बेटी उमा करुणा थुरमन का बचपन भी गुजरा है। उमा हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री हैं। रॉबर्ट ने बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए अपना गुरु लामा गोविंदाजी को बनाया था। अल्मोड़ा मठ के महामहिम टुल्कू मिंग्युर दोरजे रिंपोचे ने बताया कि थुरमन 1965-66 में अल्मोड़ा आए थे। उन्होंने यहां लामा गोविंदाजी से बौद्ध धर्म की महायान परंपरा का ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने न सिर्फ ज्ञान अर्जित किया, बल्कि बौद्ध जीवन-दर्शन का पश्चिमी देशों में प्रचार-प्रसार भी किया।

आध्यात्म के लिए परिवार के साथ भारत आए थे थुरमन : पहली पत्नी मेनिल से तलाक और कुछ अन्य घटनाओं की वजह से थुरमन ने जीवन को नए तरह से समझने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने कई देशों की यात्राएं शुरू कीं। तुर्की, ईरान की यात्रा करते हुए वह अपनी दूसरी पत्नी नीना वॉन और बेटी उमा करुणा थुरमन के साथ भारत पहुंचे। इस दौरान वह कसार देवी स्थित बौद्ध आश्रम में रहे। थुरमन को गुरु लामा गोविंदाजी ने महायान में समाहित करुणा, परोपकार, मानव सेवा की गहन शिक्षा दी।

अल्मोड़ा के मठ में विश्वभर से दीक्षा लेने आते हैं लोग : अल्मोड़ा का अंतरराष्ट्रीय बौद्ध आश्रम ध्यान एवं साधना करने वाले विदेशी साधकों के लिए सबसे शांत व प्रिय स्थान रहा है। यहां विश्वभर से बौद्ध धर्म के अनुयायी दीक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। यह साधना केंद्र बौद्ध धर्म अनुयायियों की कग्युग शाखा का उत्तराखंड में स्थापित सबसे पुराना मठ है, जिसे विधिवत 1968 में स्थापित किया गया था। हालांकि, आश्रम के रूप में यह पहले से ही अस्तित्व में था। बौद्ध मठ को ड्रिकुं काच्यू व छ्योखोर लिंग के रूप में जाना जाता है।

रॉबर्ट थुरमन फाइल

बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जता चुकी हैं बेटी

हॉलीवुड एक्ट्रेस उमा थुरमन रॉबर्ट थुरमन की बेटी हैं। मां और पिता के साथ उनके बचपन का कुछ समय सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ही गुजरा। उमा भारत को अपना दूसरा घर बताती हैं। इतना ही नहीं वो बेहतर स्क्रिप्ट मिलने पर बॉलीवुड में भी काम करने की इच्छा जता चुकी हैं। उमा किल-बिल वॉल्यूम -1, किल-बिल वॉल्यूम -2, द हाउस दैट जैक बिल्ट, माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड, डाउन ए डार्क हॉल, निम्फोमैनिएक जैसी चर्चित हॉलीवुड फिल्मों में मुख्य किरदार निभा चुकी हैं।

दूनघाटी में आसान नहीं बड़े होटलों व अस्पतालों का निर्माण

राज्य ब्यूरो, देहरादून

▸ **दूनवैली नोटिफिकेशन में सौ किलोलीटर गंदा पानी छोड़ने वाले होटल व इन्सुलेटर वाले अस्पताल रेड श्रेणी में**

पर्यावरणीय लिहाज से संवेदनशील दूनघाटी में भले ही 30 साल पुराने दूनवैली नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया गया हो, लेकिन इसमें नए बड़े होटलों और अस्पतालों की राह आसान नहीं है। 100 किलोलीटर से ज्यादा गंदा पानी छोड़ने वाले होटलों और इन्सुलेटर लगे अस्पतालों को नोटिफिकेशन में रेड श्रेणी में शामिल किया गया है। ये भी साफ किया गया है कि रेड श्रेणी (प्रदूषणकारी उद्योग) किसी भी दशा में यहां स्थापित करने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसे में दूनघाटी में ऐसे नए होटल व अस्पताल नहीं खुल पाएंगे।

खुशनुमा आबोहवा की पहचान रखने वाले देहरादून में एक फरवरी 1989 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दूनघाटी नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद यहां लाइम स्टोन के खनन पर प्रतिबंध के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक लगा दी गई थी। अलबत्ता, कम प्रदूषणकारी उद्योगों को प्रदूषण सूचकांक के आधार पर ग्रीन व ऑरेंज श्रेणी में सशर्त अनुमति दी गई। बदली परिस्थितियों में नोटिफिकेशन में बदलाव की मांग लगातार उठती रही। सरकार ने भी इसके लिए पहल की। नतीजतन बीती छह जनवरी को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया।

ये साफ किया गया कि अब दूनघाटी में ह्वाइट, ग्रीन व ऑरेंज श्रेणी के ही उद्योग लगेंगे। रेड श्रेणी के उद्योगों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया।

अब जबकि संशोधित नोटिफिकेशन का अध्ययन हो रहा है तो ये बात सामने आई है कि नए बड़े होटल व अस्पताल यहां अस्तित्व में नहीं आ पाएंगे। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी के अनुसार नोटिफिकेशन में व्यवस्था दी गई है कि 100 किलोलीटर प्रतिदिन गंदा पानी छोड़ने वाले होटल और जिन अस्पतालों में कचरा निस्तारण को इन्सुलेटर मशीनें लगेंगी, उन्हें रेड श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे में रेड श्रेणी में आने के कारण ऐसे बड़े होटल व अस्पताल यहां नहीं बन सकेंगे।

बदलेगी तस्वीर

फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद मिल गई केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से अनुमति

मारकंडा की जलधारा से प्रवाहित होगी सरस्वती नदी

पोपीन पंवार, यमुनानगर

सरस्वती नदी में जल धारा बहे, इसके लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को एक और सफलता मिल गई है। आदिबद्री में डैम व झील के निर्माण को अनुमति के साथ ही मारकंडा को सरस्वती नदी से जोड़ने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय व अन्य विभागों ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब मारकंडा का जल सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रशांत भारद्वाज का कहना है कि योजना को अनुमति मिल चुकी है। अब इस पर काम शुरू होगा। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है।

बनाई जाएगी आउट फॉल ड्रेन : सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के एसई अरविंद्र कौशिक के मुताबिक, मारकंडा नदी पर बने जलबेड़ा हेड से कुरुक्षेत्र के बीबीपुर से कंटला सप्लाई चैनल निकाली जाएगी, जो बीबीपुर लेक तक आएगी। यहां से आउट फॉल ड्रेन तैयार होगी। लेक से कुछ ही दूरी पर ड्रेन के माध्यम से मारकंडा का जल सरस्वती नदी में छोड़ा जाएगा। इसकी सभी तरह की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। काम पूरा होते ही सरस्वती में जल की कमी नहीं रहेगी।

छिलौर में 350 एकड़ में बनेगा रिजरवाए : सरस्वती नदी के लिए बिलासपुर उपमंडल के गांव रामपुर कांबोज, रामपुरा हेडियान व छिलौर में 350 एकड़ जमीन पर रिजरवाए (जहां वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाएगा) भी बनाया जाएगा। इसमें बरसात व पहाड़ों से आने वाला पानी स्टोर होगा। जरूरत पड़ने पर नदी में छोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस स्थान को अधिकारी पर्यटन की दृष्टि से तैयार करेंगे, ताकि इसकी सुंदरता को देखने के लिए यहां पर पर्यटक आते रहे, जिससे इस एरिया में रोजगार बढ़ेगा।

मारकंडा को जोड़ने से ये होगा लाभ : मारकंडा में बाढ़ आने पर आसपास के एरिया में भारी नुकसान होता है। मारकंडा को सरस्वती से जोड़ने पर बाढ़ की तबाही से राहत मिलेगी। अतिरिक्त पानी सरस्वती नदी में चला जाएगा। अधिकारी दो हजार क्यूसेक पानी सरस्वती में छोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसकी क्षमता घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। जिस एरिया से मारकंडा का जल सरस्वती के लिए आएगा, वहां पर धार्मिक मान्यता के साथ वाटर लेवल में भी सुधार होगा। अच्छी फसल होने से खुशहाली आएगी।

मारकंडा में बाढ़ आने पर आसपास के क्षेत्रों को पहुंचता है नुकसान। फाइल

द्वादश माधव के विद्यमान होने से प्रयागराज है वैष्णव क्षेत्र

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▸ **संत सम्मेलन में पहुंचे अयोध्या, दिल्ली, उप्र व मप्र के वैष्णव धर्माचार्य**

▸ **गाय, गंगा की रक्षा और श्रीराम मंदिर निर्माण पर भी हुई चर्चा**

माघ मेला क्षेत्र स्थित श्रीकृष्णकुंज सेवा समिति के शिविर में मंगलवार को जुटे संतों ने प्रयागराज को वैष्णव क्षेत्र घोषित किया। कहा कि प्रयाग में द्वादश माधव बसते हैं। इन्हीं के नाम से पूजा होती है, इसलिए प्रयाग अपने आप में वैष्णव क्षेत्र है। संत सम्मेलन में गाय, गंगा और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा हुई।

सम्मेलन में अयोध्या, प्रयागराज, मध्य प्रदेश और दिल्ली के भी वैष्णव धर्माचार्यों का जमावड़ा हुआ। महंत नृत्य गोपाल दास (अयोध्या) देर शाम तक इसमें शामिल नहीं हो सके। रसिक पीठाधीश्वर स्वामी जनमेजय शरण ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण शीघ्र होना चाहिए। शिविर के अध्यक्ष स्वामी कृष्णाचार्य ने कहा कि प्रयाग वैष्णव क्षेत्र है। इसे ऐसे सिद्ध किया जा सकता है कि यहां द्वादश माधव विद्यमान हैं। श्रद्धालु इनकी परिक्रमा करते हैं। द्वादश माधव सनातन धर्म के आधार हैं। इन्हीं के विभिन्न नाम पर देवालय हैं और पूजा होती है, इसलिए प्रयागराज को वैष्णव क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। सम्मेलन में जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य, जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रघुनाथ देशिक महाराज, जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य (दिल्ली), जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य (रीवा, मप्र), स्वामी गोपालाचार्य (ऋषिकेश), मानस केसरी महामंडलेश्वर रामलखन दास (अयोध्या), हरि प्रपन्नाचार्य और राघवेंद्राचार्य ने विचार व्यक्त किए।

किसानों की मेहनत ने भारत को टॉप तीन में पहुंचाया : मोदी

गांधीनगर, प्रेट्र : किसानों की मेहनत और सरकारी नीतियों के संयुक्त प्रयास ने ही कुछ अनाजों और खाद्य उत्पादों के मामले में भारत को टॉप तीन देशों में शामिल कराया है। मंगलवार को गुजरात में ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। किसानों के खाते में साल में छह हजार रुपये की सहायता को उन्होंने सरकार का बड़ा कदम बताया।

युवा उद्यमियों को मौजूदा मुश्किलों से परेशान नहीं होना चाहिए। यह हालात बदलेगा। इसे बदलना ही होगा।
— दीपक पारेख
चेयरमैन, एचडीएफसी

सेंसेक्स	40,966.86	188.26	निफ्टी	12,055.80	63.20	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 41,294	₹162	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 47,870	₹657
डॉलर	₹ 71.31	₹0.12	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 59.17							

चीन की अर्थव्यवस्था को बीमार बना रहा जानलेवा कोरोना वायरस

आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां झेल रहे चीन की आर्थिक सेहत को अब कोरोना वायरस बीमार करने में जुटा है। ऐसी समस्याओं से जूझने का चीन का पिछला अनुभव ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। माना जा रहा है कि चीन की चिंताओं को बढ़ाने वाला कोरोना वायरस उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होगा। उधर, चीन के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। इस वायरस के प्रकोप के बाद चीन ने अपने मुख्य प्रांत हुबेई में तालाबंदी कर दी है। हुबेई की राजधानी वुहान ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जानी जाती है। अगले आदेशों तक परिवहन के साधनों को यहां पर रोक कर रखा गया है।

दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संकट

चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी विकास दर में मामूली उतार-चढ़ाव भी वैश्विक मंदी को प्रभावित करने में सक्षम है। भारत की लुढ़कती अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए पहले से ही चिंता का विषय है। उस पर कोरोना वायरस का प्रकोप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वालों और संचालकों के सिर का दर्द ही बढ़ा रहा है।

सार्स में डूबा था चीन

चीन में कोरोना वायरस के प्रभाव के सामने आने के बाद विशेषज्ञ पिछली महामारियों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर के बारे में बात करने लगे हैं। 2002-03 में चीन सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) के वक्त डूब ही गया था। उस वक्त मरने वालों की दर कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों से ज्यादा थीं।

बीजिंग में लूनर नववर्ष के उपलक्ष्य में हुई लाइटिंग के सामने मॉस्क पहनकर सेल्फी लेता युवक। एएफपी

अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव

अनुमान है कि सार्स का प्रकोप चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक था। यहां तक की उसकी विकास दर को 1.1 से 2.6 फीसद तक प्रभावित किया था। इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रकोप सार्स की तरह ही विनाशकारी प्रभाव वाला हो सकता है। 2002-03 में चीन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर कम आश्रित और परस्पर संबंधित थीं।

दिख रहा है असर

कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया के शेयर बाजारों में दिखने लगा है। चीन के शेनजेन और शंघाई कंपोजिट स्टॉक मार्केट में लूनर नववर्ष के लिए बंद होने से पहले क्रमश: 3.52 फीसद और 2.72 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। बाजारों में नकारात्मक भावनाओं को देखते हुए अगले सोमवार तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है।

लूनर नववर्ष की खुशी फीकी

लूनर नववर्ष चीन में छुट्टी और यात्रा का समय होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें लाखों लोग दुनिया के दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। इस साल करीब 70 लाख लोगों ने विदेश यात्रा की योजना बनाई थी। हालांकि 2019 की तुलना में इस साल विदेश जाने वालों में करीब 40 फीसद की गिरावट देखी गई है। परिवहन बंद होने से उद्योगों के साथ आयात-निर्यात भी प्रभावित हुआ है। चीन इस वक्त दुनिया का विनिर्माण केंद्र है। परिवहन का लंबे समय तक बंद रहना दुनिया के दूसरे देशों पर भी असर डालेगा।

करोड़ों के नुकसान का अंदेशा

कोरोना वायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है, यह पूरी तरह तो बाद में ही पता चल सकेगा लेकिन शुरुआती अनुमान बताते हैं कि चीन की आर्थिक वृद्धि को 0.5 फीसद से एक फीसद तक प्रभावित कर सकता है। एक फीसद चीनी अर्थव्यवस्था का अर्थ 136 अरब डॉलर है और यह बहुत ज्यादा है। एशियन डवलपमेंट बैंक के अनुसार, सार्स के प्रकोप से चीन को 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। कोरोना वायरस का वैश्विक प्रभाव इससे बहुत ही ज्यादा होगा।

तीन वर्षों में 56,000 करोड़ की होगी फूड टेक इंडस्ट्री

अनुमान ▸ 25-30 फीसद रह सकती है इस उद्योग की विकास दर

गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की सर्वे रिपोर्ट से सामने आई इस इंडस्ट्री की स्थिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : तेज रफ्तार डिजिटाइजेशन और बढ़ती ऑनलाइन शॉपिंग की बदौलत साल 2022 तक देश की ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का कारोबार आठ अरब डॉलर (करीब 56,000 करोड़ रुपये) के स्तर पर पहुंच जाएगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यह बिजनेस 25-30 प्रतिशत सीएजीआर (सालाना विकास दर के हिसाब से बढ़ रहा है। मंगलवार को जारी गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यंजनों में विविधता ऑनलाइन फूड ऑर्डर वाले एप्स के बार-बार इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजहों (35 प्रतिशत) में से एक है। यह कारोबार बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण आकर्षक छूट और खाने-पीने की चीजें घर बैठे मंगवाने में सहूलियत है।

फूड डिलिवरी की चुनौतियां

- **20** प्रतिशत लोगों को विभिन्न तरह के भरोसे की कमी
- **18** प्रतिशत लोग डिलिवरी चार्ज पसंद नहीं करते
- **13** प्रतिशत को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर आशंका
- **10** प्रतिशत ग्राहकों को खलती है मनमाफिक ऑर्डर की कमी

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब जोमैटो ने हाल ही में उबर का भारतीय फूड डिलिवरी बिजनेस खरीद लिया है।

गूगल की डायरेक्टर (ट्रेवल, बीएफएसआइ, क्लासीफाइड, गेमिंग, पेमेंट्स) रोमा दत्ता चौबे ने कहा, 'फूड टेक्नोलॉजी ने भारत के 500 से ज्यादा शहरों में अपनी पहुंच बना ली है। इस क्षेत्र की कंपनियों पर ग्राहकों का भरोसा हाल में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस उभरते बाजार में ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कंपनियों के पास नए अवसर उपलब्ध हैं। नेटवर्क एडवोकेसी ने पहली बार भारत में लोगों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की दिशा में प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका (52 प्रतिशत) निभाई है। इसके बाद इस मामले में विज्ञापनों की भूमिका 19 प्रतिशत रही है। खासतौर पर बड़े शहरों और देशभर के मध्यमवर्गीय तबके के बीच ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है।'

बढ़ रहा ऑनलाइन खर्च : बीसीजी के सीनियर पार्टनर और एमडी अभीक सिंघी ने कहा, 'फूड टेक स्टार्ट-अप्स ने भारतीयों के खाने का अंदाज बदल दिया है। अब ग्राहक होम-कुक्ड और हेल्थी खाने की मांग करने लगे हैं, जिससे बिजनेस के नए मॉडल सामने आ रहे हैं।'

निवेशकों को डुबोकर गुम हुई स्टार्ट-अप्स को मौका नहीं : टाटा

मुंबई, प्रेट्र : देश के शीर्ष उद्योगपतियों में एक रतन टाटा ने मंगलवार को कहा कि जो स्टार्ट-अप कंपनियां निवेशकों की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर गायब हो जाती हैं, उन्हें दूसरा या तीसरा मौका नहीं मिलने वाला है। टाटा संस के मानद चेयरमैन का यह भी कहना था कि भविष्य में पुराने जमाने के कारोबार खत्म होते जाएंगे और इनोवेटिव कंपनियों के युवा संस्थापक ही भारतीय उद्योग जगत के लीडर होंगे।

कई स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश कर चुके रतन टाटा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसी कंपनियों पर निवेशकों को भारी घाटे में डुबोने के आरोप लग रहे हैं। निवेशक भविष्य में कमाई की उम्मीद में स्टार्ट-अप कंपनियों में पूंजी लगाते रहते हैं और कंपनियां घाटे में चलती रहती हैं। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट को अपने परिचालन के लिए एक समय हर महीने 15 करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ रही थी। टाटा ने कहा कि हमारे सामने ऐसी स्टार्ट-अप कंपनियां आएंगी जो हमारा ध्यान खीचेंगी, रकम जुटाएंगी और गायब हो जाएंगी। इन्हें दूसरा या तीसरा मौका नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट-अप कंपनियों को नैतिकता से कारोबार करना चाहिए और रातोंरात भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

एमएसएमई को बड़ी राहत मिलने की आस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नोटबंदी की मार से अभी तक जूझ रहे छोटे व मझोले उद्यमों को राहत देने की होगी बड़ी कोशिश
- नकदी भुगतान पर लगी रोक में ढिलाई देने पर भी हो रहा विचार
- पूंजी की दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष फंड बनाने पर भी गंभीर विमर्श

प्रतीकात्मक फोटो

वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद से देश की छोटी व मझोली औद्योगिक इकाइयों की स्थिति जो खराब होनी शुरू हुई थी वह अभी तक नहीं सुधर पाई है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत के लिए बहुत हद तक इन इकाइयों की स्थिति को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में शनिवार को पेश होने जा रहा आम बजट करोड़ों उद्योगों के लिए कई राहत भरी खबर ला सकता है। सूक्ष्म, लघु व मझोली इकाइयों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकातों में इस सेक्टर की स्थिति की सही तस्वीर रखी गई है। एमएसएमई को राहत देने को लेकर पिछले हफ्ते तक उच्चस्तरीय विमर्श हुआ है। नोटबंदी की वजह से इस सेक्टर को हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य तरीके से किए जाने की उम्मीद है।

मोदी के साथ इस सेक्टर की हुई बैठक में प्रमुखता से बताया गया है कि भारत जैसे बड़े व विकासशील देश में छोटे कारोबारियों के लिए नकदी का प्रचलन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है। नोटबंदी के बाद से जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग पर दबाव बनाया गया है वह उलटा असर दिखा रहा है। छोटे छोटे उद्योगों में नकदी निवेश बंद हो चुका है। यह समूचे तंत्र में एक बड़ी बाधा के तौर पर चिन्हित हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार नकदी के इस्तेमाल को लेकर मौजूदा नियमों में राहत दे जो समूचे सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए जरुरी है। सरकार की तरफ से इस सेक्टर के लिए दूसरी अहम घोषणा इन्हें आसानी से वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए अलग से फंड बनाने का हो सकता है। पिछले छह महीने के दौरान सरकार व आरबीआइ से आश्वासन मिलने के बावजूद बैंक व एनबीएफसी अभी भी इन उद्योगों को कर्ज नहीं दे रहे हैं। अलग से फंड की घोषणा सेक्टर में नया उत्साह भर सकता है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के महासचिव अनिल भारद्वाज का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या अभी वर्किंग कैपिटल की कमी है। इसकी एक वजह है कि हजारों करोड़ सरकार व निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास फंसे हुए हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी रकम उन कंपनियों में फंसी हुई है जिनके खिलाफ दिवालिया कानून के तहत मामला दर्ज है। हमें सरकार से उच्च स्तर पर यह आश्वासन मिला है कि फंसे बकाये की रकम वापसी के लिए कुछ बजट में किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर ऐसा हो जाए तो रोजाना इस्तेमाल के लिए पूंजी की जरूरत पूरी हो जाएगी। इकोनॉमी में छोटे व मझोले उद्योगों की हिस्सेदारी 30 फीसद है और अभी जैसी इनकी हालत है उससे पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूरा नहीं हो सकेगा।

झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होने का शक

जेएनएन, नई दिल्ली

- शिक्षा क्षेत्र की कंपनी एपटेक का है मामला, कंपनी में है झुनझुनवाला का बड़ा निवेश

घरेलू शेयर बाजार के सबसे सधे निवेशकों में एक राकेश झुनझुनवाला पर शिक्षा क्षेत्र की कंपनी एपटेक में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। खबरों के मुताबिक पूंजी बाजार नियामक सेबी इन आरोपों की जांच कर रहा है। एपटेक में झुनझुनवाला और उनके परिवार की निर्णायक हिस्सेदारी है। जांच के दायरे में झुनझुनवाला परिवार के वे सभी सदस्य शामिल हैं जो एपटेक में शेयरधारक हैं। निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों पर भी सेबी की नजर है, जिनमें जानेमाने निवेशक रमेश एस. दमानी और डायरेक्टर मधु जयकुमार शामिल हैं। किसी सूचीबद्ध कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति जब कंपनी की अंदरूनी जानकारी शेयर बाजार को दिए जाने से पहले उसके आधार पर शेयर की खरीद-फरोख्त करके गलत ढंग से कमाई करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है।

अभी यह पता नहीं चला है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कब और किस सूचना के आधार पर हुई है। सेबी ने राकेश झुनझुनवाला के साथ उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, भाई राजेश कुमार और सास सुशीला देवी गुप्ता को सेबी ने 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। झुनझुनवाला भी सेबी के जांच आधिकारी के सामने आए। झुनझुनवाला की बहन सुधा गुप्ता को 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सेबी ने एपटेक के डायरेक्टर उत्पल सेठ की बहन और रेयर एंटरप्राइज की सीईओ ऊष्मा सेठ सुले को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। रेयर एंटरप्राइज झुनझुनवाला की असेट मैनेजमेंट कंपनी है। एपटेक इकलौती कंपनी है, जिसमें झुनझुनवाला का निवेश और इसके प्रबंधन पर नियंत्रण दोनों है।

शेयरों में सफल निवेश के हुनर की वजह से राकेश झुनझनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। वह देश के सबसे अमीर व्यक्तिगत निवेशक हैं। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक झुनझुनवाला के पास करीब 11,140 करोड़ रुपये की शेयर संपत्ति है। यह पहला मौका नहीं है जब झुनझुनवाला सेबी की निगाह में आए हैं। वर्ष 2018 में भी बाजार नियामक ने जियोमेट्रिक में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर उनसे पूछताछ की थी। झुनझुनवाला ने बाद में कन्सेंट के साथ यह मामला 2.48 लाख रुपये चुकाकर सेटल कर लिया था।

फ्रॉड की जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए जवाबदेह नहीं होंगे बैंक प्रमुख

- वित्तीय सेवा विभाग ने सरकारी बैंकों के बोर्ड को उचित व्यवस्था बनाने को कहा
- बैंकरों को अपने हर कारोबारी फैसले की विफलता पर नहीं होना होगा परेशान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए बड़े फ्रॉड के मामलों की जांच के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही बैंक के एमडी और सीईओ की नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के सर्कुलर्स द्वारा तय की गई विभिन्न समयसीमाओं के अनुपालन के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था करें।

सरकार ने इस दिशा में कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया, 'इसी तरह 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले सभी फंसे कर्ज यानी एनपीए संबंधी खातों में धोखाधड़ी की अनिवार्य जांच संबंधी वित्तीय सेवा विभाग के 2015 के दिशानिर्देशों को केंद्रीय सतर्कता आयोग के 15 जनवरी, 2020 के सर्कुलर के साथ जोड़ दिया गया है। इसके तहत इस तरह के सभी संदिग्ध मामलों को शुरुआत में पूर्व सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी परामर्श बोर्ड (एबीबीएफएफ)

प्रतीकात्मक फोटो

के पास भेजने के लिए कहा गया है।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मौकों पर कहा है कि बैंकों के ईमानदारी से लिए गए वाणिज्यिक फैसलों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे मामलों में बैंकरों के बचाव के उपाय किए जाएंगे। वास्तविक कारोबारी विफलता और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच फर्क को रखांकित किया जाएगा। बैंकरों के बीच बड़े स्तर पर ऐसी धारणा है कि यदि उनके द्वारा लिया गया कोई भी व्यावसायिक निर्णय गलत हो जाता है तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वित्त मंत्री ने बैंकरों की इस चिंता को दूर करने के लिए पिछले महीने एक बैठक बुलाई थी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशक भी उपस्थित थे। सीतारमण ने बैंकरों से यह भी कहा था कि इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर सीबीआइ के साथ विचार विमर्श, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि सब की आशंकाएं दूर की जा सकें। इस दौरान वित्त मंत्री ने बैंक प्रमुखों को भी काफी समय से लंबित सतर्कता मामलों को निपटाने के लिए कहा। उनका कहना था कि बैंकों को महाप्रबंधक की अध्यक्षता में पैनल बनाना चाहिए और तय समयसीमा में केस तैयार करने या फाइल बंद करने को लेकर फैसला लेना चाहिए।

वित्त मंत्री से बैठक के आधार पर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया। यह कमेटी लंबित मामलों की प्रगति पर निगाह रखेगी। मंत्रालय का कहना है कि जांच में देरी से एक ओर कर्मचारियों का मनोबल टूटता है तो दूसरी ओर व्यवस्था की अक्षमता का कारण भी बनती है।

रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दे सकती है सरकार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- वर्ष 2022 तक सबके लिए घर का सपना साकार करने में मददगार होगा यह कदम
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाने से उद्योग को मिलेगी बड़ी मदद

लंबे समय से सुस्ती के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को आम बजट से इंडस्ट्री का दर्जा मिलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह शनिवार को पेश होने के लिए प्रस्तावित बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिशा में कोई न कोई घोषणा कर सकती हैं। वर्ष 2022 तक सबके लिए घर का सपना तेजी से साकार करने के लिए भी इस तरह के कदम की जरूरत है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के कारोबारी सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं।

बिल्डरों को उम्मीद है कि बजट में होने वाली घोषणाएं और उपाय लंबे समय के लिए इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले होंगे। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले वर्ष के आखिरी महीनों में सरकार ने इस क्षेत्र को गति देने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के एक फंड की घोषणा की है। अब बजट में रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से इसका समग्र विकास संभव हो सकेगा। रियल एस्टेट विशेषज्ञ विजय कुमार का कहना है कि इस क्षेत्र में लंबी सुस्ती का दौर है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं उसका सकारात्मक नतीजा आने वाले कुछ माह में दिखाई देने लगेगा। ऐसे में यदि बजट भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला होगा तो बात कुछ और होगी। एलान ग्रुप के एमडी रवीश कपूर का मानना है कि आगामी बजट से रियल एस्टेट क्षेत्र को भारी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली कई घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। उम्मीद है कि इस बार यह इंतजार खत्म हो जाएगा।

बिल्डरों ने सरकार से कई तरह के अनुदानों की मांग भी की है। बजट में इस संबंध में भी घोषणा की उम्मीद है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस को लेकर सभी काफी आशान्वित हैं। इससे सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी होगा और किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय कम लगेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट विशेष में कदम उठाए जाने की जरूरत है।

मुश्किल हालात

अर्थव्यवस्था पर असर की चिंता में दुनियाभर के बाजार नरम, घरेलू शेयर बाजार भी लगातार दूसरे दिन गिरावट में रहे, सेंसेक्स में 188 अंक और निफ्टी में 63 अंक की गिरावट दर्ज

कोरोना के डर से नहीं उबर पाए शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : जानलेवा कोरोना वायरस का डर दुनियाभर के बाजारों पर हावी है। इसका असर घरेलू बाजारों पर भी दिख रहा है। इस वायरस ने चीन में बड़ी तादाद में लोगों को चपेट में ले लिया है। दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी इसके संदिग्ध मामले मिले हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर की आशंका में घरेलू और वैश्विक शेयर बाजारों में नरमी रही। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में गिरावट आई। सेंसेक्स 188.26 अंक गिरकर 40,966.86 पर बंद हुआ। यह छह हफ्ते का निचला स्तर है। निफ्टी 63.20 अंक गिरकर 12,055.80 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा 4.55 फीसद का नुकसान हुआ। टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, आइटीसी, नेस्ले इंडिया और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा और एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.53 फीसद तक बढ़कर बंद हुए। सेक्टर के हिसाब से टेलीकॉम में सबसे ज्यादा 4.11 फीसद की गिरावट आई। मेटल, एनर्जी, पावर, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। तेल एवं गैस, आइटी एवं फाइनेंस सेक्टर हरे निशान पर रहे। बीएसई के मिडकैप और स्मालकैप इंडेक्स में 0.52 फीसद तक की गिरावट आई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'मांग में कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते ऑटो सेक्टर ने बाजार को सेटबैक दिया है। बीती तिमाही के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे हैं, इसलिए निवेशक सतर्कता से कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में यह चिंता है कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है।' मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 71.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोना-चांदी में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती से मंगलवार को सोने में गिरावट आई। स्थानीय सराफा बाजार में यह कीमती धातु 162 रुपये गिरकर 41,294 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली गई। चांदी ने 657 रुपये का गोता लगाया। चांदी का भाव 47,870 रुपये प्रति किलो पर बोली गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में गिरावट दर्ज की गई।

इनमें रही गहमागहमी

एचडीएफसी : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में जबर्दस्त मुनाफे के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों में उछाल आया। बीएसई में कंपनी के शेयर 1.53 फीसद की तेजी के साथ 2,432.40 रुपये पर बंद हुए। एनएसई में शेयर भाव 1.56 फीसद बढ़कर 2,433.40 रुपये रहा। कंपनी को बीती तिमाही में 8,372.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। सालभर पहले यह 2,113.8 करोड़ रुपये था।

यूनाइटेड स्पिरिट्स : बीएसई में कंपनी के शेयर 14 फीसद उछलकर 656.04 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई में 13.58 फीसद की बढ़त के साथ शेयर भाव 653.90 रुपये रहा। कंपनी के शेयरों में यह तेजी बेहतर तिमाही नतीजों के चलते देखी गई। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 15.19 फीसद बढ़कर 232 करोड़ रुपये रहा। सालभर पहले कंपनी का मुनाफा 201.4 करोड़ रुपये था।

इंटरग्लोब एविएशन : मुनाफावसूली के कारण इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में गिरावट आई। शुरुआती ट्रेडिंग में 3.23 फीसद की बढ़त लेने वाले शेयरों में आखिर में मुनाफावसूली हुई। बीएसई में कंपनी के शेयर 2.65 फीसद गिरकर 1,453.25 रुपये पर बंद हुए। एनएसई में कंपनी के शेयर 3.17 फीसद गिरकर 1,448.30 रुपये पर बंद हुए।

'एयर इंडिया को बेच जिम्मेदारी से बच नहीं सकती सरकार'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बीएमएस ने कहा - निजी उद्योगों को लाभ पहुंचाने का परोक्ष तरीका
- सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के नाम पर निजीकरण दुर्भाग्यपूर्ण

आरएसएस से संबद्ध यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने एयर इंडिया को बेचने के फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए सरकार से पुनर्विचार करने को कहा है। मंगलवार को जारी बयान में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्ष 1956 में निर्धारित औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को पूर्ण रूपेण पूरा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के नाम पर उन्हें बेचा जा रहा है। निजी कंपनियों को पीएसयू की बिक्री से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि निजीकरण सरकार को उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करता।

संगठन का कहना है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करतीं। ऐसे अनेक मामले हैं जहां निजी कंपनियां अपने लिए संसाधन पैदा करने में विफल रही हैं। वे कर्ज के रूप में बैंकों (जिनमें ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं) से पैसा लेती हैं और फिर उसे चुकाने में असमर्थ रहती हैं। एनपीए संकट का ये एक बड़ा कारण है। पहले भी ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सरकार ने करदाताओं के पैसों से निजी कंपनियों या बैंकों को उबारा है। यह निजी व्यवसायों को धन आपूर्ति का परोक्ष तरीका है। जबकि मुनाफा कमाने पर ये कंपनियां सरकार को टैक्स चुकाने के अलावा कुछ नहीं देतीं। विरजेश ने कहा कि पब्लिक सेक्टर पर विचार करते समय हमें निष्पादन का पैमाना अपनाना चाहिए।

11 लोगों की मौत हो गई पाकिस्तान के कराची में मंगलवार को एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से। शहादरा इलाके की इस फैक्ट्री में आग गैस सिलेंडर के विस्फोट से लगी। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

न्यूज गैलरी

कतर के शासक ने करीबी खालिद को बनाया प्रधानमंत्री

दुबई : कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अपने करीबी सहयोगी शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देलअजीज अल थानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। शेख खालिद प्रधानमंत्री पद के साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इससे पहले तक वह कतर के शासक के दफ्तर अमीरी दीवान के प्रमुख थे। शेख खालिद की नियुक्ति शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी के स्थान पर हुई है। पदमुक्त होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मार्गदर्शन के लिए अमीर का शुक्रिया अदा किया। अमीरी दीवान के मुताबिक, विदेश, ऊर्जा, वित्त, रक्षा और व्यापार जैसे अन्य अहम मंत्रालयों के प्रमुखों की जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। (रायटर)

मातृत्व, पितृत्व अवकाश पर पाक सीनेट की मुहर

इस्लामाबाद : पाकिस्तान संसद के उच्च सदन सीनेट ने मातृत्व व पितृत्व अवकाश प्रदान करने वाले बिल को सोमवार को पारित कर दिया। विधेयक के अनुसार, पहले बच्चे के वक्त देश के राजधानी क्षेत्र में सरकारी व गैरसरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को 180 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 30 दिनों की सवैतनिक छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है। चर्चा के लिए बिल को निचले सदन नेशनल असेंबली भेज दिया गया है। (आइएएनएस)

नेपाल में दो भारतीय ठगी के आरोप में गिरफ्तार

काठमांडू : नेपाल में मोबाइल एप के जरिये लोगों को चूना लगाने के आरोप में दो भारतीय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाली साथियों के साथ मिलकर कोलकाता के रहने वाले दोनों आरोपित अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। ऑनलाइन शॉपिंग एप क्लब फैक्ट्री चलाने वाले आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। (प्रेट्र)

लंदन में तीन हमवतन सिखों की हत्या में भारतीय गिरफ्तार

लंदन : पूर्वी लंदन में रहने वाले पंजाब के तीन लोगों की हत्या के मामले में यहां की पुलिस ने एक अन्य भारतीय को गिरफ्तार किया है। जांच के सिलसिले में पुलिस स्टेशन पहुंचे संदीप सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह तीसरा व्यक्ति है जिसे इस केस में गिरफ्तार किया गया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वह शवों को परिवार तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहा है। (प्रेट्र)

चीन के सभी प्रांतों में फैला कोरोना वायरस का प्रकोप

महामारी ▸ अब तक 106 लोगों की मौत, 4500 से ज्यादा संक्रमित, नियंत्रण की कवायद

राष्ट्रपति चिनफिंग बोले– दानव कोरोना से मुकाबला कर रहा चीन

बीजिंग, एजेंसियां : घातक कोरोना वायरस तिब्बत को छोड़ चीन के सभी प्रांतों में फैल गया है। राजधानी बीजिंग और शंघाई में इससे पहली मौत की खबर है। चीन में इस वायरस से अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है और 4500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंगलवार को कहा कि देश इस समय दानव कोरोना वायरस से गंभीरता से मुकाबला कर रहा है।

कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत के स्वास्थ्य आयोग के अनुसार, जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से 563 की हालत गंभीर है। राजधानी बीजिंग में भी पीड़ितों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। शंघाई में 66 मामले सामने आ चुके हैं। बीजिंग और तिआनजिन शहरों के बीच बस और ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास में छह करोड़ की आबादी वाले हुबेई में आवाजाही पहले ही बंद की जा चुकी है। नए साल (लूनर ईयर) की छुट्टियां भी दो फरवरी तक बढ़ा दी गई हैं। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि क्या चीन इस महामारी पर नियंत्रण पा सकता है?

कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे मध्य चीन के प्रांत हुबेई से सटे दूसरे शहरों में भी सड़कें सूनी हो गई हैं। लोग घरों से बेहद जरूरी होने पर ही निकल रहे हैं। यह तस्वीर हुनान प्रांत के सीमांत शहर युयांग की है। बता दें कि वुहान हुबेई प्रांत का एक शहर है। संक्रमण के चलते पूरे प्रांत का संपर्क आंशिक तौर पर देश के दूसरे हिस्सों से काट दिया गया है। रायटर

वुहान भेजे गए छह हजार अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी : चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि वुहान शहर में छह हजार अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी भेजे गए हैं। शहर में पीड़ितों के उपचार के लिए दो अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक अस्पताल एक फरवरी तक खुल जाने की उम्मीद है। जबकि दूसरा अगले दो हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा।

डब्ल्यूएचओ ने आकलन में मानी गलती : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने घातक वायरस का आकलन करने में गलती स्वीकार करते हुए सोमवार को कहा कि इस वायरस से ना सिर्फ चीन बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उच्च स्तर का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने पिछले हफ्ते वायरस के प्रकोप के मद्देनजर सिर्फ चीन के लिए हेल्थ इमरजेंसी का एलान किया था।

हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने सोमवार को मास्क पहनकर प्रेस कांफ्रेंस कर हालात की जानकारी दी। एपी

हांगकांग और चीन के बीच रुकेगी ट्रेन सेवा

चीन के नियंत्रण वाला हांगकांग ट्रेन सेवा बंद करने की तैयारी में जुट गया है। हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने कहा है कि चीन तक जाने वाली सभी रेल सेवाओं में शुक्रवार से कटौती की जाएगी। हाई स्पीड और सामान्य रेल स्टेशनों को बंद किया जाएगा। मंगोलिया ने चीन से लगती सीमाओं को बंद कर दिया है।

इन देशों में भी पहुंचा वायरस

थाइलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम, नेपाल और श्रीलंका।

वुहान में फंसे पाकिस्तानी छात्रों ने इमरान से लगाई गुहार

▸ एक छात्रा का आरोप, पाकिस्तान को छोड़ कई देश अपने नागरिकों को बचाने में जुटे

इस्लामाबाद, प्रेट्र : कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र बताए जा रहे चीन के वुहान शहर में सैकड़ों पाकिस्तानी छात्र भी फंसे हैं। शहर से निकालने के लिए इन छात्रों ने इमरान सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वायरस के प्रकोप के चलते वुहान में आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है।

हफ्सा तैयब नामक छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा, 'कई देशों के दूतावास (पाकिस्तान को छोड़) अपने नागरिकों को बचा रहे हैं। वुहान में 500 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्र हैं।' इसी वीडियो में एक अन्य छात्र ने कहा, 'हम गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी मानवीय आधार पर हमारी हालत पर संज्ञान लें और कुछ करें।' वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक छात्र के अनुसार, इस संस्थान में करीब 200 पाकिस्तानी छात्र हैं। वुहान के विश्वविद्यालयों में करीब दो हजार पाकिस्तानी छात्र पढ़ते हैं। इस बीच, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता आइसा फारुकी ने कहा, 'हम प्रभावित इलाकों में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में हैं।'

रोकथाम में जुटी पाक सरकार : पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसकी रोकथाम के उपाय करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान के आदेश पर मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है।

इमरान खान। फाइल

श्रीलंका ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा पर लगाई रोक

कोलंबो, प्रेट्र : कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद श्रीलंका ने चीनी नागरिकों को मिलने वाली वीजा ऑन अराइवल सुविधा पर मंगलवार से रोक लगा दी। चीन से कोलंबो पहुंची 40 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है।

हालात पर सरकार की नजर

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्र सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मंगलवार को कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और उससे निबटने की तैयारियों की समीक्षा की। यह लगातार दूसरा दिन है जब उन्होंने उच्चस्तरीय समीक्षा की है। मंगलवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे।

राजीव गौबा। फाइल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। बैठक में चीन से नागरिकों को निकाल कर भारत तक लाने और यहां उनकी उचित निगरानी के मुद्दे पर विमर्श किया गया। जिन राज्यों में अभी तक कोरोना वायरस के संदेह में लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उनकी भी समीक्षा की गई।

20 हवाईअड्डों पर कोरोना वायरस की जांच की व्यवस्था : स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देश के 13 और हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस की जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। अभी तक देश के 20 हवाई अड्डों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। वायरस की जांच के लिए चार लैब तैयार किए गए हैं। 27 जनवरी, 2020 तक 155 उड़ानों से आने वाले कुल 33,552 यात्रियों की जांच की है और 20 यात्रियों के सैंपल आगे की जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं। मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के साथ संपर्क में है और हर राज्य में विशेष रूप से चीन की यात्रा से आने वाले नागरिकों की जांच की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

वायरस को लेकर देश में अलर्ट, चीन से लौटे लोगों पर नजर

नई दिल्ली, एजेंसियां : चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर देश में भी अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। हाल-फिलहाल चीन से लौटने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। अभी तक देश में कोरोना वायरस से प्रभावित किसी मामले की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न राज्यों में उससे मिलते-जुलते लक्षण से प्रभावित लोगों को अस्पतालों में बनाए गए विशेष वार्ड में रखा गया है और उनकी सघन जांच पड़ताल की जा रही है।

दक्षिणी राज्य केरल में हाल के दिनों में चीन से 633 लोग लौटे हैं। सबसे ज्यादा यहीं के सात लोगों में कोरोना वायरस से मिलते-जुलते लक्षण पाए जाने के बाद अस्पतालों मे भर्ती कराया गया है। हालांकि, किसी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र की तरफ से गई तीन सदस्यीय टीम ने भी कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं मिला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कहा कि अभी सबकुछ नियंत्रण में है, लेकिन जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन हालात को सुरक्षित नहीं घोषित कर देता है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने चीन या प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों से स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने चीन से भारतीयों को निकालने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

वायरस से सतर्क चीनी पर्यटक : उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रसिद्ध ताज महल देखने पहुंचे चीन के पर्यटक मंगलवार को कोरोना वायरस से सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतते हुए मास्क पहने थे। एएफपी

केरल के 34 बच्चे वुहान में फंसे : केरल के लगभग 34 बच्चे चीन के वुहान शहर में फंसे हुए हैं। इनके माता-पिता उनको लेकर चिंतित हैं। हालांकि, कोई छात्र इस वायरस से पीड़ित नहीं है। इससे अभिभावकों में संतोष तो है, लेकिन डर भी बना हुआ है।तमिलनाडु में भी हाल में चीन से लौटे आठ लोगों को निगरानी में रखा गया है।

'डोलमा मंत्र का करें जाप'

जासं, धर्मशाला : तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाईलामा ने चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को डोलमा मंत्र के जाप की सलाह दी है। दलाईलामा से फेसबुक पर चीनी भक्तों के एक समूह ने वायरस से बचने की सलाह देने का आग्रह किया था, जिससे चीन सहित अन्य देशों के लोग वायरस से बचें रहे।

वायरस से कोलकाता में थाई युवती की मौत का शक

जागरण न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली : एहतियाती कदम उठाए जाने के बावजूद कोरोना के संदिग्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोलकाता में भर्ती थाई की युवती की मौत हो गई। आशंका है कि वह 'कोरोना' से संक्रमित थी।

अमेरिका में धोखाधड़ी में तीन भारतवंशियों को सजा

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी नागरिकों को कॉल सेंटर के जरिये 37 लाख डॉलर (करीब 26 करोड़ रुपये) से ज्यादा का चूना लगाने के गिरोह में शामिल तीन भारतवंशियों को यहां सजा सुनाई गई है। जॉर्जिया प्रांत में रहने वाले मुहम्मद काजिम मोमीन (33), मुहम्मद सोजाब मोमीन (23) और पलक कुमार पटेल (30) उन आठ लोगों में शामिल हैं जिन्हें छह माह से पांच साल तक की सजा सुनाई गई है। 2018 में सात अन्य भारतीयों के साथ इन लोगों पर जालसाजी और मनी लांड्रिंग के आरोप तय किए गए थे। उन्होंने अहमदाबाद से कॉल सेंटरों के जरिये अमेरिकियों को ठगी का शिकार बनाया था।

अटॉर्नी बयुंग जे पक ने बताया कि मामले में अमेरिकी प्रशासन आरोपी कॉल सेंटर फर्मों और उनके संचालकों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर की आड़ में गिरोह के सदस्यों ने सरकारी अधिकारी बनकर हजारों अमेरिकी नागरिकों से बकाया टैक्स राशि और लोन चुकता करने के नाम पर लाखों डालर ऐंठ लिए।

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ

▸ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में औपचारिक तौर किए गए आरोपित

▸ मुकदमे का सामना करने वाले बनेंगे इजरायल के पहले प्रधानमंत्री

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने इन मामलों में राहत पाने की संसद से अपनी याचिका वापस ले ली है। इस कदम के बाद भ्रष्टाचार के तीन मामलों में उन्हें औपचारिक तौर पर आरोपित कर दिया गया है। इजरायल के इतिहास में नेतन्याहू ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, जिन्हें मुकदमे का सामना करना होगा। हालांकि इस कानूनी प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं।

अटॉर्नी जनरल अवीचाई मांडेल्बिट ने मंगलवार को यरुशलम जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में 70 वर्षीय नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के आरोप लगाए हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल अखबार ने अटॉर्नी जनरल कार्यालय के हवाले से बताया, 'अभी कुछ समय पहले ही अभियोग दाखिल किया गया है' जबकि न्याय मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि संसद से राहत पाने का आग्रह खारिज होने के बाद किसी सांसद के साथ सामान्य नागरिकों जैसा बर्ताव किया जाता है। सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार मामलों में संसद से राहत पाने की अपनी याचिका वापस ले ली। इसी के बाद उन पर मुकदमे का रास्ता प्रशस्त हो गया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिये अपने फैसले को सार्वजनिक किया।

बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल

अभी नहीं जाएगी कुर्सी : इजरायली कानून के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित किए जाने के बावजूद नेतन्याहू को पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दोषी पाए जाने पर ही इस्तीफा देना पड़ेगा।

बेंजामिन को इन मामलों में बनाया गया है आरोपित

नेतन्याहू पर इजरायल में जन्मे हॉलीवुड के निर्माता अर्नोन मिलचन समेत कई अरबपतियों से महंगे उपहार लेने का आरोप है। उन पर अपने हित में खबर छापने के बदले एक अखबार के प्रतिद्वंद्वी अखबार को कमजोर करने का भी आरोप लगाया गया है जबकि एक टेलीकॉम कंपनी के हित में फैसला लेने का भी आरोप है। हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया है।

पाकिस्तान ने मंदिर में तोड़फोड़ मामले में पकड़े चार नाबालिग

▸ हिंदू मंत्री ने की ईशनिंदा के तहत मामला दर्ज करने की मांग

▸ सिंध प्रांत के माता देवल भिटानी मंदिर में शनिवार रात हुई थी घटना

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान की पुलिस ने सिंध प्रांत के एक मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में चार नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। थार जिले के छाचरो कस्बे के एक गांव में स्थित माता देवल भिटानी मंदिर में शनिवार रात तोड़फोड़ की घटना हुई थी। मंदिर और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद हमलावर फरार हो गए थे। प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के हिंदू मंत्री हरिराम किशोरी लाल ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में पकड़े गए लड़कों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। उन्होंने अपना जुर्म कुबूल लिया है। चारों ने बताया कि उन्होंने मंदिर से पैसे चुराने के लिए यह सब किया था। पकड़े गए चारों नाबालिग छाचरो कस्बे के रहने वाले हैं।

घटना पर नाराजगी जताते हुए मंत्री किशोरी लाल ने कहा, 'छाचरो को शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इस घटना के पीछे कुछ ऐसे तत्वों का हाथ है, जो इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं।' मानवाधिकार मामले पर सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के विशेष सहायक और वकील वीरजी कोहली ने भी मंदिर में तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कहा कि सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू

पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 75 लाख है। हिंदुओं की बड़ी आबादी सिंध प्रांत में रहती है। मुल्क में हाल के समय में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। हिंदू लड़कियों को अगवा करने और जबरन धर्मांतरण के बाद उनकी मुस्लिमों से शादी कराने की घटनाएं बढ़ गई हैं।

अमेरिका के अलबामा में आग की भेंट चढ़ीं 35 नौकाएं, आठ मरे

▸ रात में लगी आग, कई ने नदी में कूदकर बचाई जान

बोट डॉक में लगी आग। रायटर

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका के अलबामा प्रांत में सोमवार देर रात एक बोट डॉक में भीषण आग लगने से 35 नौकाएं जलकर राख हो गईं। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। इस हादसे के दौरान डॉक पर सो रहे कई लोगों ने नदी के ठंडे पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। यह घटना प्रांत के जैक्सन काउंटी पार्क में टेनेसी नदी के तट पर हुई। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

स्कॉट्सबरो शहर के अग्निशमन प्रमुख जीन नेकलेस ने कहा, 'मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि नौकाओं पर कितने लोग मौजूद थे।' पानी में कूदकर अपनी जान बचाने वाले टोमी जोंस ने कहा, 'तेज हवाओं के चलते आग इतनी तेजी से फैल गई कि हम कुछ नहीं कर पाए। हम असहाय बनकर देखते रहे और एक छोटी नाव पर सवार एक महिला और उसके बच्चे आग की भेंट चढ़ गए।' जबकि दूसरी नौका पर सवार जोंस के भाई की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटनास्थल से थोड़ी दूर एक नौका पर अपने ब्वायफ्रेंड के साथ मौजूद मैंडी डरहम ने कहा, 'लोगों की चीख-पुकार सुनकर हमारी नींद खुली। 15 से 20 मिनट के अंदर ही पूरे डॉक से आग की लपटें उठने लगी थीं।'

लोगों ने नौकाओं पर बनाया था स्थायी आशियाना

अग्निकांड में जो नौकाएं तबाह हुई हैं, उन पर कई लोगों ने स्थायी तौर पर अपना आशियाना बना रखा था। जबकि कुछ पर लोग सप्ताहांत के दौरान रहने के लिए आते थे।

न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी मुशर्रफ की गैरहाजिरी में सुनवाई

▸ पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को राहत देने वाला लाहौर हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला आया सामने

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह से जुड़े मामले में लाहौर हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपित की अनुपस्थिति में मुकदमे की सुनवाई पूरी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने इस मामले की छह साल तक सुनवाई करने के बाद गत 17 दिसंबर को मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को दिए अपने संक्षिप्त फैसले में इस सजा को असंवैधानिक करार दिया था।

डॉन न्यूज के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज सैय्यद मजार अली अकबर नकवी ने अपने विस्तृत फैसले में कहा, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और पांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से स्थापित की गई विशेष अदालत संविधान सम्मत नहीं थी। विशेष अदालत का गठन ना केवल गैरकानूनी और अनुचित था बल्कि वह अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था। आरोपित की अनुपस्थिति में मुकदमे की सुनवाई ना केवल पवित्र कुरान और सुन्नत में बताए गए इस्लामी न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सुनहरे सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

संवैधानिक बाध्यताओं का नहीं रखा ध्यान

हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा, केवल गृह सचिव संघीय सरकार की सिफारिश पर उच्चस्तरीय देशद्रोह के मामलों में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मामले में शिकायत दर्ज कराते समय संवैधानिक बाध्यताओं का ध्यान नहीं रखा गया। विशेष अदालत का गठन असंवैधानिक था। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करते समय नियमों का पालन नहीं किया गया। बता दें कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सेना प्रमुख को संविधान के अनुच्छेद-6 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी।

एपस्टीन मामले की जांच में मदद नहीं कर रहे प्रिंस एंड्रयू

लंदन, आइएएनएस : अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ के बार-बार अनुरोध के बावजूद ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जेफरी एपस्टीन मामले में किसी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। अमेरिकी अटॉर्नी ज्योफ्री बर्मन ने सोमवार को यह बात कही। अमेरिका के मशहूर फाइनेंसर एपस्टीन पर जिस्मफरोशी के लिए नाबालिगों की तस्करी का आरोप था। एपस्टीन ने पिछले साल न्यूयॉर्क की एक जेल में खुदकशी कर ली थी।

बकिंघम पैलेस ने अभी तक अमेरिकी अटॉर्नी के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। महारानी एलिजाबेथ के छोटे बेटे प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन के गलत कामों में लिप्त होने से इन्कार किया था। पिछले साल उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग का भी संकेत दिया था। प्रिंस एंड्रयू पिछले साल दिसंबर में एपस्टीन के साथ अपनी मित्रता को लेकर दिए गए साक्षात्कार के बाद शाही परिवार से अलग हो गए थे। एपस्टीन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया की राबर्ट्स गुइफ्रे ने दावा किया था कि एपस्टीन और उसके एक साथी गिसलेन मैक्सवेल ने 2001 में उसे प्रिंस एंड्रयू के पास लंदन भेजा था। तब उसकी उम्र महज 17 साल थी।

अमेरिकी विमान के मलबे तक सुरक्षा बलों को नहीं पहुंचने दे रहा तालिबान

▸ अफगान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला

▸ आतंकियों के खिलाफ हवाई कार्रवाई करने की तैयारी

काबुल, रायटर : आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य विमान के मलबे तक सुरक्षा बलों को पहुंचने नहीं दे रहा। घटनास्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे अफगान सुरक्षा बलों पर आतंकी घात लगाकर हमला कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने सोमवार को बताया था कि उसका ई-11 विमान गजनी प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसने हालांकि विमान में सवार यात्रियों और हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। अमेरिकी सेना के विपरीत तालिबान ने विमान को मार गिराने का दावा किया था।

गजनी के प्रांतीय पुलिस प्रमुख खालिद वारदाक ने बताया कि देह याक जिले में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलने के तुरंत बाद राहत और बचाव कर्मियों को रवाना कर दिया गया था, लेकिन कई जगहों पर तालिबानी लड़ाकों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। उन्होंने बताया कि जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में बैठे चार लोगों की मौत हो गई। दो लोग जीवित हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वारदाक ने कहा कि सुरक्षा बलों को पीछे हटने का आदेश दिया गया है। अब आतंकियों के खिलाफ हवाई कार्रवाई की जाएगी।

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा है कि बचाव दल को दुर्घटनास्थल से शव उठाने की अनुमति दी जाएगी। मुजाहिद ने दावा किया कि इस घटना में छह लोगों की मौत हुई है, इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं जा सकता क्योंकि आग में जलकर सबकुछ राख हो गया। नाम नहीं बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में पांच लोग सवार थे।

अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ अमेरिकी सैन्य विमान। एपी

पुलिस मुख्यालय पर तालिबान का हमला, 11 की मौत

उत्तरी अफगानिस्तान के पुलिस मुख्यालय पर तालिबान के हमले में 11 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। आतंकियों ने सोमवार देर रात मुख्यालय के पास स्थित चेक प्वाइंट पार किया और हमला करने में सफल रहे। माना जा रहा है कि उनके लिए मुख्यालय का दरवाजा एक पुलिसवाले ने ही खोला था।

ये भी जानिए

हैमिल्टन में टी-20 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। यहां पिछले चार टी-20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है।

कीवियों के गढ़ में पहली टी-20 सीरीज जीतने पर नजर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला आज, पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है भारत टीम में बदलाव की संभावना कम

हैमिल्टन, प्रेट्र: अभी तक खेल के हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला भारत बुधवार को यहां होने वाले तीसरे मैच में न्यूजीलैंड में पहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीतने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा। भारत ने ऑकलैंड में हुए शुरुआती दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रमशः छह और सात विकेट से जीत दर्ज की। भारती टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है।

सेडन पार्क में लगातार तीसरे मैच में जीत से भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार टी-20 सीरीज जीतने में सफल रहेगी। इससे पहले दो अवसरों पर वह यह उपलब्धि हासिल करने में नाकाम रही थी। भारत 2008-09 में महेंद्र सिंह धौनी की अगुआई में 0-2 से जबकि पिछले साल 1-2 से सीरीज हार गया था। भारत की यह टीम अभी बेहतरीन फॉर्म में है और 2019 वनडे विश्व कप के बाद उसने जो पांच टी-20 सीरीज खेली हैं उनमें उसने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें वर्तमान सीरीज भी शामिल है। इस बीच उसने केवल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं जीती। वह सीरीज 1-1 से बराबर छूटी थी जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

रैंकिंग में खास फायदा नहीं: टी-20 क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद आइसीसी रैंकिंग में उसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। भारत अभी टी-20 रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है और उसे चौथे स्थान पर पहुंचने के लिए वर्तमान सीरीज 5-0 से जीतनी होगी। न्यूजीलैंड अभी छठे स्थान पर है जबकि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका भारत से आगे हैं। सभी की निगाह ऑस्ट्रेलिया में इस साल के आखिर में होने वाले टी-20 विश्व कप पर है लेकिन टीम प्रबंधन को विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से पहले सही समय पर सारी चीजें ढर्रे पर आ रही हैं। राहुल और श्रेयस अय्यर के विशेषकर इस दौरे में प्रदर्शन से इन चीजों को बल मिला है।

बदलाव की संभावना नहीं: इसे देखते हुए तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास का दिन था। इसमें कप्तान विराट कोहली, केएल राहुल, युजवेंद्रा सिंह चहल, मुहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने भाग नहीं लिया। टीम प्रबंधन उन खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा है जिन्हें सीरीज में अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है। वाशिंगटन सुंदर और रिषभ पंत को मौका मिलने की संभावना नहीं है। कुलदीप यादव पहले दो मैचों में नहीं खेले थे और ऐसा मैदान छोटा होने के कारण किया गया था। छोटे मैदान पर बल्लेबाज उन्हें निशाना बन सकते थे। अब मैच बड़े मैदानों पर होंगे और देखना होगा कि कुलदीप की वापसी होती या नहीं।

ग्रैंडहोम के पास मौका: न्यूजीलैंड का सवाल है तो कोलिन डि ग्रैंडहोम के पास प्रभाव छोड़ने का यह आखिरी मौका होगा। अंतिम दो टी20 के लिए बल्लेबाज टॉम ब्रूस इस ऑलराउंडर की जगह लेंगे। ग्रैंडहोम इस सीरीज में बल्लेबाज के तौर पर खेले लेकिन उन्होंने शून्य और तीन रन बनाए। भारत के पहले दो मैचों में सफलतापूर्वक लक्ष्य हासिल किया।

विदेश में भी बेहतर हो रही है टीम इंडिया: साउथी

हैमिल्टन, प्रेट्र: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी का मानना है कि टीम इंडिया विदेशी सरजमीं पर लगातार बेहतर बनती जा रही है और इसका सबूत मौजूदा टी-20 सीरीज है जिसमें विराट कोहली की अगुआई वाली टीम 2-0 से आगे चल रही है। साउथी ने कहा, 'भारत बहुत अच्छा खेला। उनकी टीम बेहतरीन है और उसके पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं। पहला मैच हम थोड़े अंतर से हारे, लेकिन दूसरा मैच हमने आसानी से गंवाया। हम जानते हैं कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा मुश्किल होता है और वह अपने देश से बाहर भी लगातार बेहतर टीम बनती जा रही है। भारत को हराने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मैदान में बदलाव से हमें मदद मिल सकती है।'

अभ्यास सत्र के दौरान हैमिल्टन में बातचीत करते (बायें से) भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा ● ट्विटर

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित, केएल राहुल, मनीष पांडे, रिषभ पंत, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, जडेजा, कुलदीप, चहल, शमी, बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, वाशिंगटन सुंदर।

न्यूजीलैंड: विलियमसन (कप्तान), गुप्टिल, टेलर, स्कॉट कुगलेइजन, मुनरो, कॉलिन डि ग्रैंडहोम, टॉम ब्रूस, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट, हैमिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, ब्लेयर टिकनर।

विश्व कप के अहम खिलाड़ियों की पहचान हो चुकी है: विक्रम

हैमिल्टन: बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने भारतीय क्रिकेटरों की नई पीढ़ी को 'अविश्वसनीय' करार दिया और कहा कि टीम प्रबंधन अक्टूबर नवंबर में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अहम खिलाड़ियों की पहचान कर चुका है। तसीरे टी-20 से पहले राठौर ने कहा कि आखिरी क्षणों तक समायोजन जारी रहेगा। हम जानते हैं कि हमारी टीम कैसी होगी। अगर चोट या बेहद खराब फॉर्म का मामला नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक बदलाव होंगे। राठौड़ ने कहा कि क्रिकेटरों की यह नई पीढ़ी अविश्वसनीय है। वे जिस तरह से तुरंत सामंजस्य बिठाते हैं वह हैरानी भरा है। वे वास्तव में अलग प्रारूप, अलग मैदानों और अलग देशों में उतरते ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। यहां न्यूजीलैंड में जिस तरह से उन्होंने बहुत कम समय में परिस्थितियों से तालमेल बिठाया है वह वास्तव में लाजवाब है। भारत ने केएल राहुल और अय्यर की शानदार फॉर्म के दम पर ऑकलैंड में पहले दोनों मैच जीते। उन्होंने कहा, 'इन खिलाड़ियों को जितने अधिक मौके मिल रहे हैं वे दिखा रहे है कि वे काबिल हैं। वे दिखा रहे हैं कि वे मैच विजेता है। इससे निश्चित तौर पर टीम को मदद मिलती है लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

धौनी की सीट पर अब भी कोई नहीं बैठता: चहल

धौनी के साथ चहल ● फाइल फोटो, ट्विटर

हैमिल्टन: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल ने बताया कि टीम बस में अब भी महेंद्र सिंह धौनी की सीट पर कोई नहीं बैठता है और टीम को इस पूर्व कप्तान की बहुत कमी खलती है। तीसरे टी-20 से पहले टीम बस में तैयार किये गए वीडियो में चहल जसप्रीत बुमराह, रिषभ पंत, केएल राहुल जैसे टीम सदस्यों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिर में वह बस के पीछे जाते हैं और खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पिछले साल विश्व कप के बाद लंबे विश्राम पर जाने से पहले बस में यह पूर्व कप्तान का पसंदीदा स्थान था। बीसीसीआइ .टीवी पर पोस्ट किए गए वीडियो में चहल कहते हैं, 'यह वह सीट है जहां एक दिग्गज बैठते थे। माही भाई। अभी भी यहां कोई नहीं बैठता। हमें उनकी बहुत कमी खलती है।' भारत के नौ जुलाई को विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार के बाद से 38 वर्षीय धौनी ने कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। इस महीने के शुरू में बीसीसीआइ ने उन्हें केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से निकाल दिया था जिससे उनके भविष्य को लेकर फिर से कयास लगाए जाने लगे।

कोहली के स्टंट से भज्जी हैरान

नई दिल्ली: कोहली फिटनेस के मामले में दुनियाभर के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तीसरे मैच से ठीक पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। जिम में वर्कआउट के दौरान शूट किए गए वीडियो में वह एक स्टंट करते दिख रहे हैं। दरअसल, वह वर्कआउट के दौरान सामने रखे एक बॉक्स पर छलांग लगा रहे हैं। उनके इस स्टंट पर जहां फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है तो हरभजन सिंह ने भी तारीफ की है। भज्जी ने इस वीडियो को देखकर कहा वाह...।

टीम इंडिया ने अनोखे तरीके से किया अभ्यास

हैमिल्टन, आइएएनएस: विराट कोहली की अगुआई में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी-20 सीरीज जीतने से एक कदम दूर है और ऐसा लगता है कि जब टीम इंडिया बुधवार को कीवी टीम के खिलाफ उतरेगी तो वह 3-0 की अजेय बढ़त लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। टीम इंडिया ने एक अनोखे अभ्यास ड्रिल के साथ अपनी तैयारी की है। मैच की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया एक हाथ से कैच का अभ्यास करती हुई नजर आई। इसका वीडियो बीसीसीआइ ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है। बोर्ड ने इसके साथ कैप्शन लिखा, 'टीम इंडिया का नया अभ्यास ड्रिल।' इसमें खिलाड़ी एक-दूसरे को गेंद फेंकते दिख रहे हैं और उन्हें एक हाथ से कैच लपकना है। बीच में मौजूद कुछ खिलाड़ियों से गेंद में बाधा डालने के लिए भी कहा गया। कोहली की टीम पहले ही दो मैच जीत चुकी है और उसने तीनों विभागों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

09 टी-20 मैच न्यूजीलैंड ने सेडन पार्क में खेले हैं उसमें से उसने सात में जीत दर्ज की है। वह भारत को अजेय बढ़त हासिल करने से रोकने की कोशिश करेगा

25 रन अगर कोहली बना लेते हैं तो वह बतौर कप्तान टी-20 में धौनी (1112 रन) से आगे निकल जाएंगे। वह इस फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन जाएंगे

1273 रनों के साथ डु प्लेसिस इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तानों की सूची में नंबर वन पर हैं।

नोवाक जोकोविक खिताब के सबसे करीब: वुडब्रिज

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टॉड वुडब्रिज ने नोवाक की फॉर्म को देखकर लगाया अनुमान

ऑस्ट्रेलियन ओपन का रोमांच अब सेमीफाइनल में दस्तक दे चुका है। गत चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविक और स्विस स्टार रोजर फेडरर के बीच गुरुवार को सेमीफाइनल होना है। ये दोनों ही अपनी खिताबी जीत की उम्मीदों को पूरा करने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि फेडरर को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है लेकिन जोकोविक अब तक एकतरफा जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। वहीं स्पेनिश स्टार राफेल नडाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। दुनिया के सर्वकालिन सर्वश्रेष्ठ डबल्स खिलाड़ियों में से एक रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी टॉड वुडब्रिज का मानना है कि मौजूदा खेल के स्तर को देखकर लगता है कि जोकोविक की खिताब के सबसे करीब हैं।

डबल्स में 16 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले वुडब्रिज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में बिग थ्री की संभावनाओं को लेकर पूछे गए दैनिक जागरण के सवाल पर कहा कि मौजूदा स्थिति में केवल जोकोविक ही खिताब के सबसे करीब नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आने से पहले ही उनका फॉर्म दूसरे किसी भी खिलाड़ी से बेहतर था। 48 वर्षीय वुडब्रिज ने करियर में कुल 22 ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किए जिसमें से चार उन्होंने मेलबर्न पार्क पर हासिल किए। इन चारों में से सबसे खास खिताब के सवाल पर वुडब्रिज ने कहा कि मार्क वुडफोर्ड के साथ 1992 में जीता गया मेरा पहला डबल्स ग्रैंडस्लैम खिताब सबसे खास रहा। ना सिर्फ पहले ग्रैंडस्लैम खिताब की वजह से यह मेरे लिए खास रहा बल्कि घरेलू मैदान पर जीतने से यह और भी खास बन गया। एक समय था जब टेनिस कोर्ट पर वुडब्रिज और वुडफोर्ड की जोड़ी गजब ढा रही थी लेकिन मौजूदा समय में शायद ही कोई ऐसी पुरुष डबल्स की जोड़ी हो जो लगातार अपने खेल से प्रभावित कर पाई है। इसके पीछे के कारण के सवाल पर वुडब्रिज ने कहा कि हमारे खेल में ब्रायन बंधुओं के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावशाली खेल देखने को मिला। यह उनका आखिरी साल है और टेनिस सौभाग्यशाली है कि उसे इन जैसे खिलाड़ी मिले। अभी नए खिलाड़ियों के लिए जोड़ी बनाकर अपनी छाप छोड़ने का मौका है।

पीसीआइ अध्यक्ष बनीं दीपा मलिक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: रियो पैरालंपिक पदक विजेता व पद्मश्री एवं खेल रत्न अवॉर्ड से सम्मानित दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआइ) की अध्यक्ष चुनी गई हैं। इस समिति का कार्यकाल चार वर्ष का होगा। दीपा का चयन सर्वसम्मति से हुआ। उनके चुनाव में समिति के अंतरिम अध्यक्ष गुरुशरण सिंह ने विशेष भूमिका निभाई।

दीपा ने कहा कि उन्हें इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए गुरुशरण सिंह ने राजी किया था। गुरुशरण को पीसीआइ का महासचिव चुना गया। अर्जुन अवॉर्डी एम महादेव को कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। दीपा ने कहा कि फिलहाल समिति का पूरा ध्यान टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 की तैयारियों पर है। अभी इसकी तैयारी को लेकर सात माह का समय है और खिलाड़ियों के पास तैयारी को लेकर पर्याप्त समय है। गुरुशरण सिंह ने बताया कि समिति का चुनाव 10 अक्टूबर 2019 को हुआ था और चुनाव के खिलाफ पीसीआइ के उपाध्यक्ष एसपी सांगवान दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए गए थे जिस पर कोर्ट ने चुनाव के नतीजे पर रोक लगा दी थी, लेकिन मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने चुनावों को सही ठहराया।

क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 74 रन से दी करारी शिकस्त

कार्तिक के दम पर भारत सेमीफाइनल में

त्यागी ने झटके चार विकेट यशस्वी जायसवाल और अथर्व के लगाए शानदार अर्धशतक

अंडर-19 विश्व कप

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: कार्तिक त्यागी की घातक गेंदबाजी और यशस्वी जायसवाल व अथर्व अंकोलेकर के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम ने मंगलवार को पोचेस्फ्रस्ट्रूम में खेले गए सुपर लीग के पहले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 74 रनों से हराया। यशस्वी ने 82 गेंदों में छह चौके व दो छक्के की मदद से 62 रन बनाए, जबकि अथर्व ने 54 गेंदों पर पांच चौकों व एक छक्के की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेली। इसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में नौ विकेट पर 233 रन बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 43.3 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई। कार्तिक ने आठ ओवर में 24 रन देकर चार विकेट झटके। उनके अलावा आकाश सिंह ने 30 रन देकर तीन विकेट लिए।

भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले ही ओवर में तीन विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम को पारी की पहली ही गेंद पर झटका लगा, जब जैक फ्रेजर मैकगर्क (00) रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में कार्तिक ने कप्तान मैकेजी हार्वे (04) और लचलम हीर्ने (00) को भी चलता कर दिया। कार्तिक ने अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में ओलिवर डाविस (02) को यशस्वी के हाथों कैच कराकर स्कोर 17 रन पर चार विकेट कर दिया। सलामी बल्लेबाज सैम फैनिंग (75) ने पहले पैट्रिक रोव (21) के साथ मिलकर और फिर लियाम स्कॉट (35) के साथ मिलकर टीम इंडिया को थोड़ी देर के लिए मुश्किल में डाला, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए मैच जीत लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस मैच में कुछ कमजोर नजर आई। टीम इंडिया के लिए यशस्वी और दिव्यांश सक्सेना (14) ने पारी का आगाज किया। भारत ने अपना पहला विकेट 35 रनों पर दिव्यांश के रूप में गंवाया।

इसके बाद तिलक वर्मा (02) और कप्तान प्रियम गर्ग (05) सस्ते में पवेलियन लौट गए, जिससे 16वें ओवर में भारत का स्कोर तीन विकेट पर 54 रन हो गया। यहां से यशस्वी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला, लेकिन टीम को 100 रन का आंकड़ा पार कराने के बाद 102 रन के टीम स्कोर पर आउट हो गए। जल्द ही ध्रुव जुरेल (15) भी चलते बने, जिससे टीम इंडिया 31 ओवर में स्कोर पांच विकेट पर 114 रन हो गया। सिद्धेष वीर ने भी 25 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद अथर्व और रवि बिश्नोई ने टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रवि के रन आउट होने से दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए हुई 61 रन की साझेदारी का अंत हुआ। रवि ने 31 गेंद पर 30 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोरे केली और टॉड मर्फी ने दो-दो विकेट लिए।

विकेट लेने के बाद खुश कार्तिक त्यागी (बायें) ● आइसीसी

सौरभ ने उत्तर प्रदेश को संभाला

इंदौर, नईदुनिया: बायें हाथ के निचलेक्रम के बल्लेबाज सौरभ कुमार (नाबाद 98) ने शून्य पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए न सिर्फ यादगार पारी खेली, बल्कि रणजी ट्रॉफी एलीट समूह-बी के लीग मैच में उत्तर प्रदेश (उप्र) को मध्य प्रदेश (मप्र) के खिलाफ पहली पारी में 216 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचाया। मप्र ने पहली पारी में 230 रन बनाए थे। पहली पारी में मिली 14 रनों की अहम बढ़त के बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मप्र ने दूसरी पारी में तीन विकेट खोकर 105 रन बना लिए। इस तरह उसके पास कुल 119 रन की बढ़त हो गई है।

होलकर स्टेडियम में मप्र की दूसरी पारी में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और आठ रन पर जीवनदान पाने के बावजूद विकेटकीपर बल्लेबाज अजय रोहेरा (16) कुछ खास नहीं कर सके और विपक्षी कप्तान अंकित राजपूत का शिकार बन गए। इसके बाद रमीज खान (32) और रजत पाटीदार (25) ने 57 रन की साझेदारी की। दोनों को सौरभ ने पवेलियन की राह दिखाई। दिन का खेल खत्म होने के समय नमन ओझा (नाबाद 20) व यश दुबे (नाबाद 04) क्रीज पर मौजूद थे।

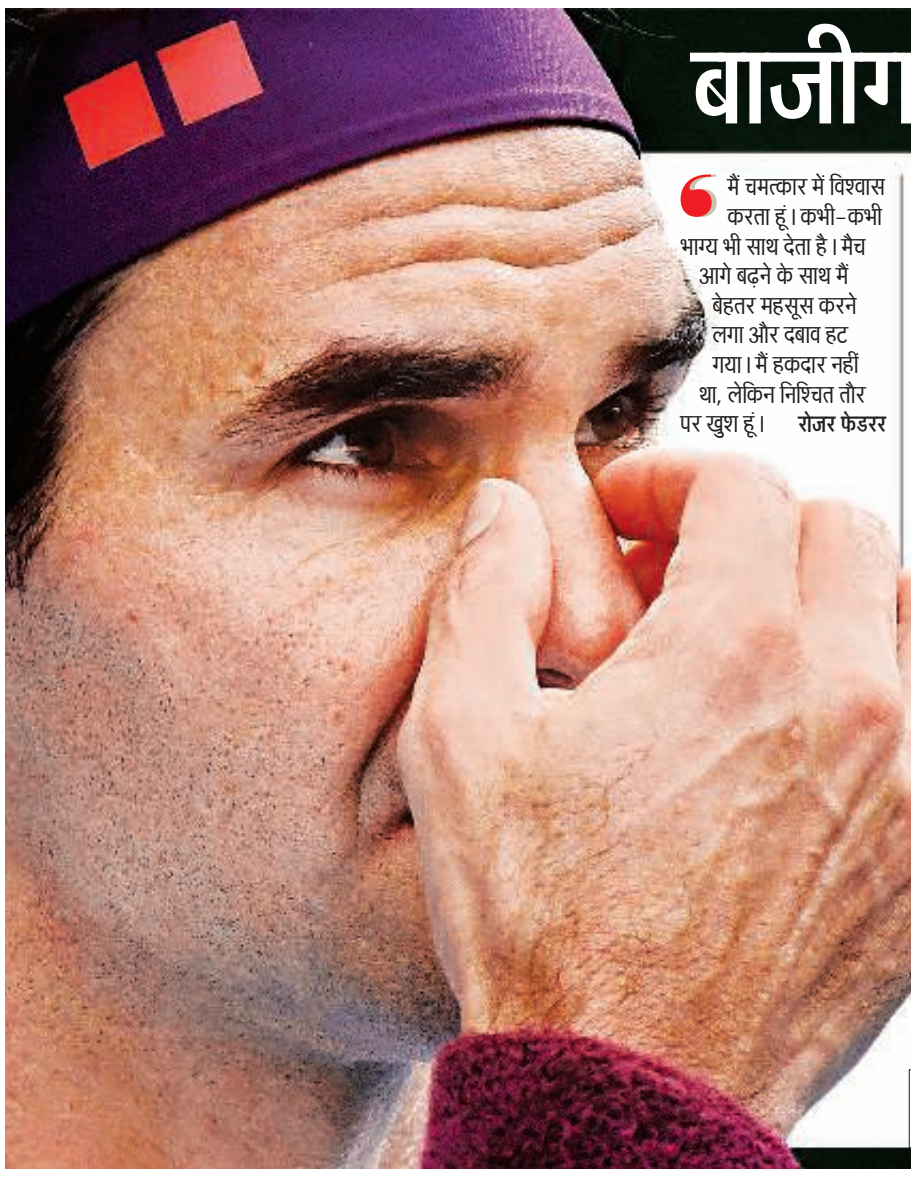

बाजीगर रोजर फेडरर

- रोजर ने सात मैच प्वाइंट बचाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई
- अंतिम चार में सर्बिया के दिग्गज जोकोविक से होगा सामना

> मैं चमत्कार में विश्वास करता हूं। कभी-कभी भाग्य भी साथ देता है। मैच आगे बढ़ने के साथ मैं बेहतर महसूस करने लगा और दबाव हट गया। मैं हकदार नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर खुश हूं। **रोजर फेडरर**

मेलबर्न, एएफपी: हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं...कुछ ऐसी ही बाजीगरी रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिखा रहे हैं। जॉन मिलमैन के खिलाफ तीसरे दौरे के मैच को टाईब्रेकर में हारने की कगार पर पहुंचने के बाद जीतने वाले फेडरर ने मंगलवार को क्वार्टर फाइनल में भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाया। अब सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत दूसरे नंबर के सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविक से होगा।

स्विट्जरलैंड के दिग्गज स्टार फेडरर चमत्कार में विश्वास करते हैं और ऐसा ही चमत्कार उन्होंने मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में दिखाया। इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने सात मैच प्वाइंट बचाकर वर्ष के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। छह बार के चैंपियन फेडरर ने चौथे सेट में 4-5 के स्कोर पर तीन और फिर टाईब्रेकर में चार मैच प्वाइंट बचाएद्ध उन्होंने करारे शॉट लगाने में माहिर व कोर्ट पर चपल विश्व के 100वें नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी टेनीस सैंडग्रेन को तीन घंटे 28 मिनट तक चले मैच में पांच सेटों में 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10-8), 6-3 से हराया। तीसरे दौर के मैच में भी फेडरर कड़े संघर्ष के बाद जीते थे जब उन्होंने घरेलू खिलाड़ी जॉन मिलमैन को 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 (10-8) से हराने में सफल हुए थे।

जीत की भूख बरकरार: चौथे सेट में एक समय ऐसा लग रहा था कि इस दिग्गज खिलाड़ी का सफर टूर्नामेंट में खत्म हो जाएगा लेकिन फेडरर ने हार नहीं मानी और अपने अनुभव से चौथे और पांचवें सेट को जीतकर सैंडग्रेन को टेनिस का अच्छा पाठ पढ़ाया। फेडरर की जीत की भूख अब भी पहले की तरह बरकरार है और उन्होंने समय-समय पर इसे जाहिर किया था। अपने से 10 साल छोटे अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ भी उन्होंने अपने जोश, जज्बे और भरोसे को दिखाकर यादगार वापसी की। अब अंतिम चार में गुरुवार को उनका सामना सर्बिया के नोवाक जोकोविक से होगा जिन्होंने मिलोस राओनिक को सीधे सेटों में 6-4, 6-3, 7-6 से हराया।

मैच प्वाइंट का खेल: हमेशा कोर्ट पर शांत दिखने वाले 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन फेडरर को अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए चेतावनी भी मिली। तीसरे सेट में वह ग्रोइन इंजरी के कारण कोर्ट से बाहर भी गए और बाद में उन्होंने दायें पैर की मालिश के लिए एक ट्रेनर की मदद ली। सैंडग्रेन ने दूसरा और तीसरा सेट जीतने के बाद चौथे सेट में 5-4 से बढ़त बना रखी थी। फेडरर की सर्विस पर उनके पास तीन मैच प्वाइंट थे। पहले पर सैंडग्रेन ने बैकहैंड नेट पर मार दिया। दूसरे में उनका फोरहैंड बाहर चला गया और तीसरे में फोरहैंड नेट पर जा लगा। यह गेम टाईब्रेकर तक खिंचा जिसमें स्कोर एक समय 3-3 से बराबर था। सैंडग्रेन ने अगले तीन अंक जीते और अब उन्हें जीत के लिए एक अंक की जरूरत थी। इस पूरे टाईब्रेकर में उन्हें चार मैच प्वाइंट मिले, लेकिन वह किसी का फायदा नहीं उठा पाए। फेडरर ने दूसरे सेट प्वाइंट पर स्कोर 2-2 से बराबर किया और फिर पांचवां सेट जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

36 साल बाद बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए रचा इतिहास: महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने पेत्रा क्वितोवा को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उनका सामना अमेरिका की 14वीं वरीयता प्राप्त सोफिया केनिन से होगा।

ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त बार्टी ने पहले सेट में जूझने के बाद चेक गणराज्य की सातवीं वरीय क्वितोवा को महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में 7-6, 6-2 से हराकर यहां पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस तरह से 23 साल की बार्टी ने दो बार की विंबलडन चैंपियन क्वितोवा से पिछले साल क्वार्टर फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हालांकि पिछले 12 महीनों से बेहतरीन फार्म में हैं। उन्होंने पिछले साल फ्रेंच ओपन जीता और पहली बार रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची। बार्टी ने कहा, 'यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है। मैं जानती थी कि मुझे पेत्रा के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। पहला सेट महत्वपूर्ण था।' बार्टी 1978 में क्रिस ओ नील की खिताबी जीत के बाद मेलबर्न में खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बनने की कवायद में है। उनकी हार्ड कोर्ट पर यह 100वीं करियर जीत है। 36 वर्षों में यह पहला मौका है जब कोई महिला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। बार्टी से पहले वेंडी टर्नबुल 1984 में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इस बीच, सोफिया केनिन ने ट्यूनीशिया की ओनस जाबेर के विजय अभियान पर रोक लगाकर पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने गैरवरीयता प्राप्त जाबेर को 6-4, 6-4 से हराया। मॉस्को में जन्मी 21 वर्षीय केनिन ने पिछले दौर में अमेरिका की 15 वर्षीय कोको गॉफ को हराया था। वहीं, 25 वर्षीय जाबेर ट्यूनीशिया की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनीं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में कोई मैच जीता था।

पेस ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर

मेलबर्न: अनुभवी भारतीय दिग्गज लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार येलेना ओस्टापेंको के मिक्स्ड डबल्स में बाहर होने के साथ इनका सफर समाप्त हो गया। पेस और लातविया की ओस्टापेंको की जोड़ी को ब्रिटेन के जेमी मरे और अमेरिका की बेथानी माटेक सैंड्स ने सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से हराया। दूसरे दौर का यह मैच एक घंटे सात मिनट तक चला।

टेनीस सैंडग्रेन *vs* रोजर फेडरर		
27	ऐस	05
05	डबल फॉल्ट	03
73	विनर्स	44
53	असहज गलतियां	56
161	कुल अंक	160

15 वीं बार स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं जबकि वह छह बार यह खिताबी ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं

102 वीं जीत विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में दर्ज की

1977 में ऑस्ट्रेलिया के केन रोशवॉल के बाद 38 वर्षीय फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं

मैं पहले भी पाकिस्तान आ चुका हूं। लाहौर शानदार शहर है। यहां के लोग बेहतरीन मेजबान हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। रावलपिंडी टेस्ट में टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी।
– महमूदुल्लाह, कप्तान, बांग्लादेश क्रिकेट टीम

आनंद संयुक्त छठे स्थान पर रहे

विच्न आन जी (नीदरलैंड्स) : पांच बार के चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के 13वें और अंतिम दौर में पोलैंड के यान क्रिस्तोफ डुडा से ड्रॉ खेला और वह 6.5 अंकों के साथ संयुक्त छठे स्थान पर रहे। फैबियानो कारूआना ने रूस के व्लादिसलाव आर्तमीव को हराकर नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैगनस कार्लसन पर दो अंकों की बड़ी बढ़त से टूर्नामेंट जीता। कार्लसन दूसरे स्थान पर रहे।

न्यूज गैलरी

50 ओवर के मैच लगे 48 छक्के व 70 चौके

ढाका : बांग्लादेश में 50 ओवरों के एक सेकेंड डिविजन मैच में बल्लेबाजों ने 48 छक्के और 70 चौके लगाए, जबकि इस मैच में कुल 818 रन बने। नॉर्थ बंगाल क्रिकेट अकादमी ने यह मैच 46 रन से जीता। उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 432 रन बनाए। जवाब में टैलेंट हंट क्रिकेट अकादमी सात विकेट पर 386 रन ही बना सकी। नॉर्थ बंगाल के खिलाड़ियों ने 27 और विरोधी टीम ने 21 छक्के लगाए। बांग्लादेश के घरेलू मैचों में कई बार अप्रत्याशित नतीजे निकलते हैं। यही वजह है कि यहां मैच फिक्सिंग के आरोप आम हैं। इस बारे में स्थानीय क्लब क्रिकेट आयोजक सैयद अली असफ ने इस पर कहा, 'यह हैरान करने वाला है। मैं ढाका के घरेलू क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं और वर्षों से देखते आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा।' यहां मैच फिक्सिंग सामान्य बात है। इससे पहले 2017 में यहां एक मैच के दौरान एक गेंदबाज ने वाइड और नोबॉल से 92 रन दे डाले थे। उस पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा था। ऐसे ही कई और मामले भी हैं। यहां तक कि अंपायर तक पर पक्षपात पर आरोप लग चुके हैं। (एएफपी)

ग्रैंडमास्टर प्रागननंदा का विजय अभियान थमा

जिब्राल्टर : भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रागननंदा का 18वें जिब्राल्टर शतरंज महोत्सव में पांच बाजियों से चला आ रहा विजय अभियान चीन के वांग हाओ से सातवें दौर में मिली हार के साथ ही थम गया। हमवतन पीवी नंदिता से पहली बाजी गंवाने के बाद लगातार पांच बाजियां जीतने वाले 14 वर्षीय प्रागननंदा ने हाओ का भी डटकर सामना किया, लेकिन आखिर में उन्हें 56 चाल तक चली बाजी में हार का सामना करना पड़ा। चीनी ग्रैंडमास्टर इस जीत से रूस के आंद्रे एस्रिपेंको और डेविड परावयान व ईरान के प्रथम मागसूदलू के साथ संयुक्त बढ़त पर पहुंच गया है। इन सभी के छह-छह अंक हैं। भारत के के शशिकिरण को हराने वाले रूस के दानिल युफा और उनके हमवतन मिहेल कोबालिया के 5.5 अंक हैं। उनके बाद दूसरी वरीयता प्राप्त मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, पूर्व विश्व चैंपियन वेसलिन टोपालोव, भारत के बी अधिबान, कार्तिकेयन मुरली, आर्यन चोपड़ा, एसएस नारायणन, प्रागननंदा और डी गुकेश का नंबर आता है। इन सभी के पांच-पांच अंक हैं। (प्रेट्र)

दोस्त कोबे को लेकर भावुक हुए नोवाक

श्रद्धांजलि ▸ टेनिस खिलाड़ी ने कहा, 10 साल से ब्रायंट के साथ उनके थे व्यक्तिगत संबंध

राओनिक के खिलाफ मैच के बाद दिवंगत कोबे ब्रायंट को लेकर भावुक हुए सर्बिया के नोवाक जोकोविक। एएफपी

बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे और उनकी बेटी का हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ था निधन

मेलबर्न, एएफपी : सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक अपने मेंटर और दोस्त अमेरिकी दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी दिवंगत कोबे ब्रायंट को लेकर भावुक हो गए। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जोकोविक ने मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल मैच के बाद ब्रायंट को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह पिछले 10 साल से उनके अच्छे दोस्त और मेंटर हैं। ब्रायंट और उनकी बेटी गियाना व सात अन्य लोगों का रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था।

जोकोविक ने मेलबर्न पार्क के रोड लेवर एरीना में साक्षात्कार में कहा, 'वह हमेशा से सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे हैं। उन्होंने मेरे अलावा विश्व में कई लोगों को प्रेरित किया है। मेरे उनके साथ पिछले 10 साल से व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं। जब भी मुझे कुछ सलाह और मदद की जरूरत होती थी तो उन्होंने हमेशा से मेरी मदद की है। वह मेरे मेंटर और दोस्त थे। जब मैंने उनके और उनकी बेटी के बारे में सुना तो मेरा दिल टूट गया था। उन्होंने कई मैच टीम को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। वह हमेशा जीत के लिए प्रतिबद्ध थे।' मैच के बाद जोकोविक ने ब्रायंट को याद करते हुए उनके केबी नाम से ट्रैकशूट पहना हुआ था। इसके अलावा उन्होंने रोड लेवर एरिया में श्रद्धांजलि के तौर पर एक प्रतिक चिन्ह भी रखा जिसमें एक दिल बना हुआ था जिसमें केबी आठ-24, गिगी लव यू लिखा हुआ था। जोकोविक के अलावा कई अन्य दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों जिसमें बिली जीन किंग और मार्टिना नवरातिलोवा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।

काली पट्टी पहनकर खेलेंगे खिलाड़ी : एसी मिलान की टीम ब्रायंट को श्रद्धांजलि देने के लिए इटली की फुटबॉल लीग सीरी-ए के मैच में टोरिना के खिलाफ एक बाजू पर काली पट्टी पहनकर खेलेंगे। क्लब ने एक बयान में कहा कि लीजेंड कभी नहीं मरते हैं। मिलान में होने वाले इस मैच के शुरू होने से पहले दो मिनट का मौन भी रखा जाएगा।

ब्रायंट की मौत की खबर सुन स्तब्ध है पिट्सबर्ग : घोषाल

कोलकाता : भारत के स्क्वॉश खिलाड़ी सौरभ घोषाल इस समय पिट्सबर्ग में हैं, जहां वह पीएसए विश्व खिताब टूर्नामेंट में जाने से चूक गए, लेकिन कोबे ब्रायंट की मौत के बाद इस शहर में पड़े सन्नाटे को वो महसूस कर रहे हैं।

पिट्सबर्ग, पेनसिल्वानिया राज्य में है और इसी राज्य के फिलाडेल्फिया में ब्रायंट का जन्म हुआ था। घोषाल ने पिट्सबर्ग से कहा, 'मुझे लगता है कि यहां हर कोई दुखी, हैरान और स्तब्ध है। हमारी पीढ़ी का एक महान खिलाड़ी बहुत जल्दी चला गया। वह बेहद अच्छे इंसान थे। जिंदगी कभी बहुत बेरहम होती है। मैं मैच के बाद एक रेस्त्रां में कुछ खाने के लिए बैठा था और तभी उनकी मौत की खबर टीवी पर आई। मैं हैरान हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं पूरे दिल से दुआ कर रहा था कि यह खबर गलत हो। यह बेहद दुखदायी है। इसने बताया है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और इसलिए हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए।'

पाकिस्तान में नहीं खेलेगा भारत : बीसीसीआइ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▸ अधिकारी ने कहा, मसला मेजबानी नहीं बल्कि आयोजन स्थल है

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने साफ कर दिया है कि उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एशिया कप की मेजबानी करने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। बीसीसीआइ ने कहा है कि एशिया कप का स्तर तटस्थ होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इस समय पाकिस्तान जाना विकल्प ही नहीं है। इसी साल एशिया कप खेला जाना है, जो इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'सवाल यह नहीं है कि पीसीबी मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट के स्थल की बात है। अभी इस समय जैसी चीजें हैं, यह साफ है कि हमें तटस्थ स्थल चाहिए होंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भारत बहुद्देशीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने भी पाकिस्तान जाए। अगर एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) इस बात से खुश है कि एशिया कप बिना भारत के हो तो यह अलग बात है लेकिन अगर भारत को एशिया कप का हिस्सा होना है तो यह जरूरी है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में न हो।' 2018 में एशिया कप भारत में होना था, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजा की समस्या हुई थी और इसी कारण एशिया कप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कराया गया था और इसकी मेजबानी बीसीसीआइ ने की थी। अधिकारी ने कहा कि पीसीबी भी यही कर सकती है। उन्होंने कहा, 'तटस्थ स्थल हमेशा से विकल्प रहते हैं और इससे टीमों को मदद मिलती है। बीसीसीआइ ने 2018 में यह किया था।'

पाकिस्तान में 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर आतंकवादियों में हमला कर दिया था तब से पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद था लेकिन हाल ही में श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा किया और अभी इस समय बांग्लादेश भी दौरे पर है। हालांकि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा इससे भी ज्यादा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के कारण यह स्थिति है कि भारत किसी भी सूरत में मौजूद हाल में पाकिस्तान का दौर नहीं कर सकता।

मैच के दौरान हुई मैदानी घटना पर नरम पड़े फाफ डु प्लेसिस और जो रूट

▸ दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने बताया मैच के दौरान का पूरा मामला

▸ फाफ व ब्रॉड के बीच हुई थी बहस, बीच में आ गए थे बटलर

जोहानिसबर्ग, एएफपी : दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने कहा कि इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर और तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड से जुड़ी घटना केवल विरोधी टीम के सामने पीछे नहीं हटने का मामला था। डु प्लेसिस चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन ब्रॉड से बहस करते हुए बटलर से टकराते हुए दिखे।

यह घटना तब घटी जब डु प्लेसिस और रेसे वेन डेर डुसेन ने 92 रन की साझेदारी निभाकर इंग्लैंड को कुछ समय के लिए परेशानी में रखा था। इंग्लैंड ने यह मैच 191 रन से जीता। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी डु प्लेसिस की रक्षात्मक शॉट खेलने के बाद गेंद को उठाने की आदत से परेशान थे। सैम कुर्रन का थ्रो उनके पैड पर लगने के बाद बहस हुई और डु प्लेसिस बटलर के पास जाते हुए दिखाई दिए। डु प्लेसिस ने कहा, 'यह मेरी आदत का हिस्सा है। अगर आप पिछले मैचों को देखेंगे तो पाएंगे कि मैं हमेशा मैच में किसी न किसी तरह से शामिल रहता हूं, टीम के अगुआ के तौर पर अपना जच्बा और यह दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप विरोधी के सामने नहीं झुकते। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ इस तरह की कुछ घटना होती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए उसने (ब्रॉड ने) मेरे लिए कुछ कहा और मैंने उसका जवाब दिया। मुझे लगता है कि जोस या मुझे इसका पता यह मेरे और ब्रॉड के बीच की बात थी और उसने हम दोनों के बीच पड़ने की कोशिश की। हमारी भावना दुर्भावनापूर्ण नहीं थी।'

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि यह कोई मसला नहीं था और तब वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे डु प्लेसिस अधिक प्रतिबद्ध हो जाएंगे।

ब्रॉड पर 15 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना

आइसीसी ने स्टुअर्ट ब्रॉड पर इस घटना के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जुड़ गया है। ब्रॉड के खाते में पिछले 24 महीने में दो डिमेरिट अंक जुड़ चुके हैं और अगर यह चार तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक मैच का निलंबन झेलना होगा।

बंगाल ने दिल्ली पर कसा शिकंजा

खेल संवाददाता, कोलकाता : अनुस्तूप मजूमदार की संकटमोचन पारी के बाद घातक गेंदबाजी के बूते बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-ए के मैच में दिल्ली पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

ईडन गार्डेंस स्टेडियम में मंगलवार को मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने 192 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे। दिल्ली के कप्तान ध्रुव शौरी ने सर्वाधिक 65 बनाए। उनके अलावा हितेन दलाल ने 40 रन की पारी खेली। बंगाल के लिए मुकेश कुमार, नीलकंठ दास और शाहबाज अहमद ने दो-दो विकेट चटकाए।

इससे पहले बंगाल की पहली पारी 318 रन पर खत्म हुई थी। बंगाल के मध्यक्रम के बल्लेबाज अनुस्तूप मजूमदार शतक से चूक गए। 99 के स्कोर पर वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए। उनके अलावा श्रीवत्स गोस्वामी ने 59 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से सिमरजीत सिंह ने 77 रन देकर चार और विकास मिश्रा ने 78 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।

रणजी ट्रॉफी

बिहार को बढ़त

जागरण संवाददाता, पटना : कप्तान आशुतोष अमन (3/17) और शिवम कुमार (4/69) की बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के दम पर बिहार ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में मेघालय के खिलाफ पलटवार करते हुए पहली पारी के आधार पर 29 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त ले ली है। मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में सोमवार को बिहार की पहली पारी 208 रनों पर सिमट गई थी। जवाब में मंगलवार को मेघालय की टीम आशुतोष और शिवम की फिरकी में फंसकर 179 रनों पर पवेलियन लौट गई। इस दौरान बिहार के कप्तान आशुतोष अमन ने मंगलवार को प्रथम श्रेणी करियर में 100 विकेट पूरे किए।

रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान मंगलवार को बंगाल के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद दिल्ली के बल्लेबाज ध्रुव शौरी। प्रेट्र

विविध

इंडिगो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर छह माह का प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडिगो ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी सवालात करने के लिए स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर छह माह का प्रतिबंध लगा दिया है। एयरलाइन ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हाल में मुंबई से लखनऊ की उड़ान 6-ई 5317 के संदर्भ में हम सूचित करना चाहते हैं कि कुणाल कामरा को इंडिगो के साथ छह महीने की अवधि के लिए उड़ान भरने से रोका जा रहा है। क्योंकि, विमान पर उनका आचरण अस्वीकार्य था।

इसमें आगे कहा गया है कि हम अपने यात्रियों को सलाह देना चाहते हैं कि वे उड़ान के दौरान व्यक्तिगत छींटाकशी से परहेज करें। इससे दूसरे यात्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को मुंबई से लखनऊ की यात्रा के दौरान कामरा ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के साथ बहस करना चाहा था। बाद में ट्विटर पर घटना का वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए उन्होंने अर्णब से पूछा कि वे कायर हैं या पत्रकार?

भारत पर्व में खाने पीने से लेकर मौजमस्ती की रही धूम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर अनरसा का लोगों ने लिया स्वाद

▸ राजस्थान के चखरी व घूमर नृत्य का लोगों ने लिया आनंद

विभिन्न राज्यों की अनूठी संस्कृतियों के संगम को दर्शाते लाल किला मैदान में आयोजित भारत पर्व के तीसरे दिन लोगों ने मेले में मौज मस्ती के साथ खाने पीने का आनंद लिया। इसमें विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पकवान लोगों की जुबान पर छाए रहे। वहीं, विभिन्न राज्यों की पारंपरिक नृत्य शैली को देखने के लिए दिन भर मेले में लोगों की भीड़ जुटी रही।

मेले में विभिन्न राज्यों के अपने अपने स्टॉल लगे हैं। जिन पर पहुंच लोग वहां की जीवन शैली से लेकर वहां के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही सेल्फी प्वाइंट्स पर भी लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दोपहर दो बजे से तमिलनाडु राज्य के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपनी करतबबाजी से दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। शाम आठ बजे तक कर्नाटक, झारखंड व मध्य प्रदेश के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। हालांकि, शाम सात बजे के बाद हुई बारिश से कार्यक्रम में खलल भी पड़ा।

लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में बिहार फूड स्टॉल पर लिट्टी चोखा लेते लोग। जागरण

मेले में छा रहा बिहार फूड स्टॉल : भारत पर्व में इन दिनों बिहार फूड स्टॉल पर बिना लहसुन प्याज का खाना लोगों को खूब भा रहा है। इसमें सेव बुनिया, लिट्टी चोखा, पिड़ुकिया, लौंगतलता, चरौरी, अनरसा, चना सत्तू, मकई का सत्तू, सत्तू कचौड़ी, सत्तू शरबत व दालपिठी शामिल है। लोगों ने बड़े चाव से बिहार के इन खानों का लुत्फ उठाया। बिहार सूचना केंद्र के सहायक निदेशक लोकेश कुमार झा ने बताया कि यहां आने वाले लोग बिहार की संस्कृति व वहां के पर्यटन स्थलों से भी रूबरू हो सके, इसके लिए बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स से लेकर पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, घोरा कटोरा, काकोलट व धुआं कुंड शामिल हैं।

राजस्थान के चखरी व घूमर नृत्य ने खींचा ध्यान

पर्व में राजस्थान के लोकप्रिय घूमर व चखरी नृत्य ने मंगलवार को लोगों को ध्यान खींचा। ढोलक, खंजरी, नगाड़ा व खंजर जैसे वाद्य यंत्रों की धुनों पर थिरकते कलाकारों के साथ लोग भी खुद को थिरकने से नहीं रोक सके।

हरमीत की पाकिस्तान में हत्या से जांच पर पड़ेगा असर

जागरण संवाददाता, अमृतसर

▸ केएलएफ आतंकी हिंदू नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड

▸ ड्रग मनी के बंटवारे पर विवाद के बाद हुई थी हत्या

खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आतंकी हरमीत सिंह हैपी उर्फ पीएचडी की पाकिस्तान में हत्या के बाद पंजाब में उससे जुड़े मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है। हरमीत पंजाब में आरएसएस व अन्य हिंदू नेताओं की हत्या का मास्टरमाइंड था। सोमवार को लाहौर स्थित डेरा चहल साहिब के साथ सटे गुरुद्वारा बेबे नानकी के बाहर दो मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार ड्रग मनी के बंटवारे के विवाद में उसकी हत्या हुई है।

अमृतसर के छेहरटा के नजदीक न्यू कबीर पार्क इलाके का रहने वाला हैप्पी पीएचडी लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ उसे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करती थी। नवंबर 2008 में हरमीत ने धार्मिक मसलों पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से शोध किया। इसी दौरान उसका संपर्क गर्मपंथी संगठनों से हुआ और वह केएलएफ से जुड़ गया। उसे पीएचडी के नाम से ज्यादा जाना जाता था।

सूत्रों के अनुसार विभिन्न जिलों के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आए हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी में भी आइएसआइ ने पीएचडी का इस्तेमाल किया था। आइएसआइ ने ही उसे गुरुद्वारा बेबे नानकी के पास शरण दी थी। वहां से वह नशीले पदार्थों के साथ-साथ हथियारों की तस्करी करता था।

परिवार ने केंद्र से लगाई गुहार, भारत लाया जाए शव : हरमीत के पिता अवतार सिंह ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि हरमीत का शव पाकिस्तान से भारत लाया जाए, ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें। पिता के मन में कहीं न कहीं इस बात की मायूसी दिखी कि उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। मंगलवार को घर के बाहर मीडिया कर्मियों को देखकर उन्होंने अपने घर का गेट बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह खुद ही घर के बाहर आए और मीडिया से बात की।

गुरमीत की हत्या की साजिश के बाद हुआ था फरार : सुरक्षा एजेंसियों को साल 2008 में सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से हथियारों की खेप भारत पहुंची है, जिससे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह की हत्या की जानी थी। पुलिस ने इस मामले में गुरसागर सिंह, सुखविंदर सिंह, कुलदीप सिंह को काबू किया था, लेकिन हरमीत पीएचडी फरार होने में कामयाब हो गया था। उसके इशारे पर ही 6 अगस्त 2017 को जालंधर में जगदीश गगनेजा हत्याकांड व अमृतसर में 18 नवंबर 2018 की सुबह निरंकारी भवन ब्लास्ट में भी हरमीत सिंह का नाम आया था।

अतुल्य भारत के संदेश के साथ सफर पर निकलेंगी 150 विंटेज कारें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित 21 गन सेल्यूट अंतरराष्ट्रीय विंटेज कार रैली इस बार दिल्ली-एनसीआर की सरहद को पार करते हुए चार राज्यों में 4000 किमी का सफर तय करेगी। इसमें देश-दुनियां से आए 150 दुर्लभ विंटेज कारें शामिल होंगी। यह 15 फरवरी को इंडिया गेट से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात के तमाम गांव-शहर होते हुए 10 मार्च को राजस्थान के उदयपुर पहुंचेंगी। इन कारों को बीच में दो दिनों के लिए गुरुग्राम के करमा लेकलैंड्स, गोल्फ कोर्स में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। यह रैली कई एतिहासिक शहरों और स्थलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान प्रतिभागी होली उत्सव का अनुभव भी लेंगे। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस रैली के नौवें संस्करण का नाम 'अतुल्य भारत' रखा गया है। आयोजन में पर्यटन मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है।

इसमें शामिल होने के लिए कारें जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका समेत देश के विभिन्न भागों से आ रही हैं। इस बारे में 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट के चेयरमैन व मैनेजिंग ट्रस्टी मदन मोहन ने कहा कि यह देश के लोगों को पूरे विश्व में कार के चरणबद्ध सफर से परिचित कराने के साथ पर्यटन बढ़ाने के भरपूर संभावनाओं वाला होगा। इस रैली को देखने के लिए 1700 से अधिक विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। इनमें भाग लेने वाले कई धनी विदेशी हैं। वहीं, कार से जुड़े विश्व के जाने माने 37 लोग बतौर ज्यूरी भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विंटेज कार रैली पूरे विश्व में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रमुख केंद्र रहा है। अब इसे विश्व के बड़े हेरिटेज मोटरिंग शो के रूप में सफल बनाने की कोशिश है। मदन मोहन ने बताया कि रैली में हर बार नई गाड़ियां होती हैं, क्योंकि एक कार को सात साल बाद मौका देने का प्रावधान है।

नई दिल्ली के भगवान दास रोड स्थित टिहरी गढ़वाल हाउस में खड़ी विंटेज कारें जो फरवरी में होने वाली 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेर कार रैली में शामिल होंगी। ध्रुव कुमार

इसमें वर्ष 1938 की रोल्स रॉयस 25/30, मासरेटी 3500 जीटी विग्नेल सिडर, वर्ष 1939 की ब्यूक रोडमास्टर कनर्वेटेबल, 1938 की लैंसिया एस्टुरा सीरीज 4, 1949 की ब्यूक रोडमास्टर, 1930 बीएमडब्ल्यू 3/15 डीए2 'कैब्रियोलेट', 1938 की डेलाहे 135 एम, 1936 रोल्स रॉयस 25/30 गुर्ने नटिंग कूपे, 1959 जगुआर एक्सके 150एस, 1936 रोल्स रॉयस 25/30, 1951 बेंटले एमके 6 फ्रीस्टोन एंड वेब, 1966 फोर्ड मस्टैंग, 1930 कैडिलैक वी. 16 रोडस्टर और वर्ष 1959 की अल्फा 2000 और कई अन्य शामिल हैं।

गुरुग्राम में बनेगा देश का पहला विंटेज कार संग्रहालय : गुरुग्राम में देश का पहला विंटेज कार संग्रहालय बनेगा। इसमें 365 से अधिक विंटेज कारें और 100 से अधिक मोटरसाइकिलें प्रदर्शनी के लिए रखी जाएंगी। इस बारे में मदन मोहन ने बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर यह संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। इसके लिए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस तरह के संग्रहालय राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी स्थापित करने की तैयारी है।

ये कारें हैं खास

- गार्डनर 1928- नीले रंग की चमचमाती डबल सीटर गार्डनर में एक कवर्ड सीट भी है, जिसे मदर सीट कहते हैं। कैलिफोर्निया पुलिस इसका विशेषकर इस्तेमाल करती थी। कैलिफोर्निया पुलिस इस कार पर इतना इतराती थी कि उसका नारा था गार्डन चेस ऐनी कार।
- 1958 की एमजीएमजीए 1600- अपने समय की यह मशहूर स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार है। यह उस समय युवाओं के दिलों पर राज करती था। इसकी छत खुल जाने वाली है।
- नेपियर कार- वर्ष 1911 की नेपियर कार के पहिए बड़े हैं। हेडलाइट बाहर निकले हुए हैं। यह रामपुर के नवाब की गाड़ी थी, जिसे बाद में इंग्लैंड को बेच दिया गया। बाद में इसे खरीद कर वापस लाया गया।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलीयुक्त रहेगा। दिन के तापमान में हल्की वृद्धि संभव है। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर गरज व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व बर्फबारी होगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा संभव है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा।

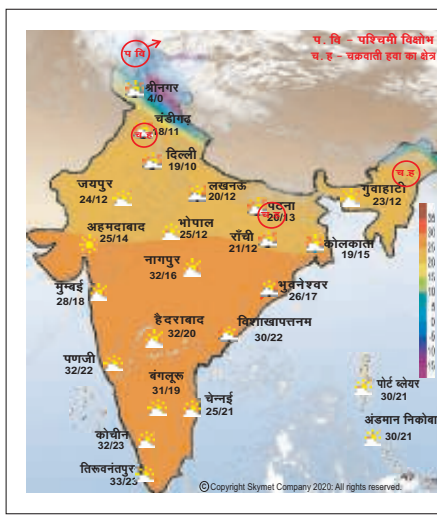

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/18/आंबा	अहमदाबाद	28/09/व
कोलकाता	21/13/व	बड़ौदा	29/11/सा
चेन्नई	33/22/आंबा	नागपुर	32/16/आंबा
हैदराबाद	32/19/आंबा	इन्दौर	28/11/आंबा
बंगलूरू	31/19/आंबा	रांची	22/10/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/23/आंबा	पटना	20/10/आंबा
गुवाहाटी	24/14/आंबा	जमशेदपुर	25/12/आंबा
जंगटोक	11/05/आंबा	पुणे	30/19/आंबा

देश के पहले अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ

आज ही के दिन 1780 में जेम्स अगस्त हिकी ने कोलकाता (तब कलकत्ता) से बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह देश का पहला अखबार था। यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का प्रबल आलोचक था। इसके प्रकाशन पर दो साल बाद रोक लगा दी गई।

अस्तित्व में आया वायु निगम अधिनियम 1994

आज ही के दिन वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994 अस्तित्व में आया। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को क्रमश: इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना गया।

ओलंपिक पदक विजेता से राजनेता राज्यवर्द्धन राठौड़

आज ही के दिन ओलंपिक पदक विजेता और सांसद कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान के जैसलमेर में 1970 में हुआ था। 9 ग्रेनेडियर (मेवाड़) रेजिमेंट में 15 दिसंबर 1990 को कमीशन हुए। 1990 से 2013 तक सेवाएं दीं। कर्नल पद से रिटायर हुए। 2004 एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग स्पर्द्धा में रजत पदक जीता। केंद्र सरकार में खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री रहे। पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद हैं।

इधर-उधर की

इसलिए नहीं मिली नागरिकता

जेनेवा, एजेंसी : स्विट्जरलैंड में 30 साल बिताने के बावजूद एक शख्स की नागरिकता के आवेदन को निरस्त कर दिया गया और सिर्फ इसलिए कि वह स्थानीय चिड़ियाघर के बारे में जानकारी नहीं रखता था। हालांकि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय कोर्ट ने नेचुरलाइजेशन कमीशन के इस निर्णय को अनुचित करार दिया है और कहा है कि इसका प्रभाव भविष्य के आवेदनों पर होगा। इटली का यह शख्स 30 साल से यहां रहकर एक छोटा व्यवसाय चलाता था। उसने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ नागरिकता के लिए आवेदन किया था। उनके परिवार के सदस्यों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए लेकिन उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। उससे कई सवाल पूछे गए जिनमें से कुछ के जवाब वो नहीं दे सका। वो नहीं जानता था कि स्थानीय चिड़ियाघर में भालू और भेड़िए पिछले 11 सालों से एक साथ रह रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे कारणों के चलते नागरिकता नही मिली है। पहले भी कई लोगों को इसी तरह के कारणों के चलते नागरिकता से वंचित किया गया है।

जैव विविधता को प्रभावित कर रही हैं मानवीय गतिविधियां

- ब्रिटेन की लंकेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा
- कहा-पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की जरूरत

प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के दबाव के कारण वैश्विक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता जा रहा है। ब्रिटेन की लंकेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। उन्होंने इस अध्ययन के लिए दुनिया भर के 100 से अधिक स्थानों का अवलोकन किया, जहां उष्णकटिबंधीय जंगलों और प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) को तूफान, बाढ़, हीटवेव (लू), सूखा और आग जैसी आपदाओं ने प्रभावित किया था।

रॉयल सोसायटी बी के जर्नल फिलोसोफिकल ट्रांजेक्शन में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कैसे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियां कितनी जिम्मेदार हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर दें तो जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है।

ब्राजील के एम्ब्रपा अमेजन ओरिएंटल के प्रमुख शोधकर्ता फिलिप फ्रेंका ने कहा, 'वैश्विक जैव विविधता के लिए उष्णकटिबंधीय वन और प्रवाल भित्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए यह बेहद चिंताजनक है कि वे जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों दोनों से प्रभावित हैं।' उन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय जंगलों और प्रवाल भित्तियों के लिए कई स्थानीय खतरे, जैसे कि वनों की कटाई, अतिवृष्टि और प्रदूषण भी जिम्मेदार हैं। इनसे पारिस्थितिक तंत्र की विविधता और कार्यप्रणाली दोनों ही प्रभावित होती है। फ्रेंका ने कहा, 'यदि इस प्रवृत्ति को बदला जाए तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र काफी हद तक जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम हो सकता है।

तूफान और लू का कारण : शोधकर्ताओं ने पाया कि जलवायु परिवर्तन अब अधिक तीव्र तूफान और समुद्री किनारों पर लू का कारण भी बन रहा है। लंकेस्टर यूनिवर्सिटी के समुद्र विज्ञानी कैसेंड्रा ई बैंकविट ने कहा, 'प्रवाल भित्तियों के लिए इस तरह का मौसम उनके बाहरी आवरण को प्रभावित करता है और इससे उनका विस्तार क्षेत्र भी कम हो जाता है। इससे मछलियों की प्रजातियां भी प्रभावित होती हैं। बैंकविट ने कहा, हालांकि प्रवाल भित्तियों को विस्तार क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ेगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितने लंबे समय तक रहा।

प्रभावी कदम उठाने की है जरूरत : शोधकर्ताओं ने बताया कि उष्णकटिबंधीय वन्य प्रजातियों को तूफान की बढ़ती आवृत्ति से भी खतरा है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के ग्वाडालूपे पेर्टा ने कहा, 'उष्णकटिबंधीय जंगलों में तूफान के बाद पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह विरूपित हो जाता है। जंगलों में पेड़-पौधों के टूटने, जानवरों, पक्षियों और कीड़ों पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता को स्वस्थ बनाए रखना है तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

वजन घटाने की सर्जरी से कम होता है कैंसर का खतरा

स्पेक्ट्रम

- शोधकर्ताओं ने दावा- सर्जरी कराने वाले मरीजों में 35 फीसद कम हो जाता है आंत के कैंसर का जोखिम

प्रतीकात्मक

दुबई, प्रेट्र : आंत के कैंसर के इलाज की दिशा में एक और उम्मीद की किरण नजर आई है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वजन घटाने की सर्जरी से कोलोरेक्टल यानी आंत के कैंसर का जोखिम एक तिहाई तक कम किया जा सकता है।

कुवैत के जबेर अल-अहमद हॉस्पिटल शोधकर्ताओं ने कहा, 'ओबेसिटी यानी मोटापा टाइप 2 डाइबिटीज, कार्डियोवस्कुलर डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारक है और इनका जोखिम भी कई गुना बढ़ा देता है।

ब्रिटिश जर्नल 'सर्जरी' में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि जो मरीज बेरिएट्रिक सर्जरी या वजन घटाने के लिए सर्जरी करते हैं, उनमें मोटापा कम करने के लिए सर्जरी न कराने वाले मरीजों की अपेक्षा कोलोरेक्टल कैंसर विकसित होने का जोखिम 35 फीसद कम होता है।

इस विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने साल साल तक कुल 1,213,727 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की। शोधकर्ताओं ने कहा ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि व्यक्तिगत परीक्षण में कई बार विरोधाभाषी परिमाण सामने आते हैं।

सर्जरी एक महत्वपूर्ण उपकरण : जबेर अल-अहमद अस्पताल से प्रमुख लेखक सुलेमान अल्माजेदी ने कहा, 'वैज्ञानिक समुदाय हर दिन वजन घटाने की सर्जरी के लाभों को बताते हैं। हमारा शोध पत्र इसकी पुष्टि करता है।' उन्होंने कहा कि आज के समय में मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है और कई बार इसके चलते मौत तक हो जाती है। अल्माजेदी ने कहा कि शोध से एक बात तो निश्चित हो जाती है कि कैंसर की महामारी से निपटने के लिए वजन घटाने की सर्जरी एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने वजन घटाने की सर्जरी करवाई थी उनमें कोलोरेक्टल कैंसर के विकास का कुल जोखिम 1,000 में से तीन लोगों में पाया गया।

वृद्धावस्था में मस्तिष्क को तीक्ष्ण रखता है अखरोट

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : वृद्धावस्था में लोगों का संज्ञानात्मक कौशल धीरे-धीरे कम होने लगता है और व्यक्ति की लोगों को पहचानने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अखरोट खाने से इस समस्या से बहुत हद तक दूर रहा जा सकता है और व्यक्ति का मस्तिष्क अपेक्षाकृत तीक्ष्ण रहता है।

क्लीनिकल न्यूट्रीशियन नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन कहा गया है अखरोट खाने का सबसे ज्यादा लाभ उन बुजुर्गों में देखने को मिला, जिनका न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्कोर बहुत कम था, जो लोग धूमपान करते थे। इसका सीधा असर उनके संज्ञानात्मक कौशल पर पड़ता है। अमेरिका की लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जोआन साबेट ने कहा, ये कम समय में जुटाए गए आंकड़ों के परिणाम थे, यदि लंबे समय तक अखरोट का सेवन किया जाए तो इसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे निष्कर्ष बुजुर्गों के लिए संजीवनी हो सकते हैं।

सूर्य के ध्रुवों के बारे में बताएगा नया मिशन

तैयारी पूरी ▸ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर मिशन लांच करेगा नासा

सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जानकारी जुटाना है इसका मुख्य उद्देश्य

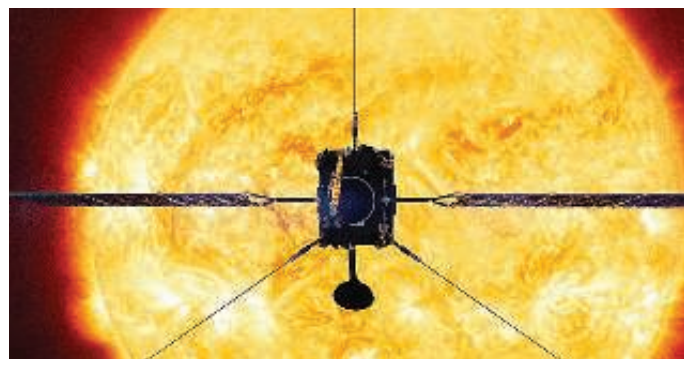
अगले महीने लांच किया जाएगा सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के साथ मिलकर अगले महीने एक नया स्पेसक्राफ्ट लांच करने जा रही है। इसके माध्यम से सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीरें ली जाएंगी।

नासा ने एक बयान में कहा कि सात फरवरी 2020 को अमेरिका के केप कैनावेरल से सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लांच किया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्पेसक्राफ्ट शुक्र और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सूर्यपथ के ऊपर-नीचे झूलता रहेगा। सूर्यपथ अंतरिक्ष की वह पट्टी है जो सूर्य के इक्वेटर के साथ संबंधित है और इसी पट्टी पर सभी ग्रहों की कक्षा है।

दस उपकरणों से लैस है स्पेसक्राफ्ट : अमेरिका में नेवल रिसर्च लैब के अंतरिक्ष वैज्ञानिक रसेल हॉवर्ड ने कहा, 'नए स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से हम सूर्य को ऊपर और नीचे से देखने में सक्षम होंगे।' सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में दस उपकरण लगाए गए हैं, जो सभी जानकारियां एकत्र करेंगे।

सौर तूफानों की निगरानी होगी आसान : सूर्य हमारे चारों ओर के अंतरिक्ष को बनाने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका विशाल चुंबकीय क्षेत्र प्लूटो से आगे फैला हुआ है। जिसके माध्यम से आवेशित सौर कण यात्रा करते हैं। जिन्हें सौर हवाएं भी कहते हैं। जब प्रचंड सौर हवाएं पृथ्वी से टकराती हैं तो यह हमारे मौसम और संचार उपग्रहों में बाधा डालती हैं, ये सौर हवाएं अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरे में डाल सकती हैं। इन सौर तूफानों से तैयारी के लिए वैज्ञानिक सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी करते हैं। हालांकि, अभी तक यह निगरानी केवल सूर्य पथ के माध्यम से सीधे-सीधे की जाती है। हम सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाते, जिससे सटीक सूचना मिलने में गड़बड़ी होती है। लेकिन अब यह समस्या सुलझ सकती है।

मौसम का सटीप पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है सूर्य का चुम्बकीय क्षेत्र : नासा के परियोजना वैज्ञानिक होली गिल्बर्ट ने कहा, 'ध्रुवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम अपनी सूचना प्रणाली को और सटीक बना सकते हैं।' शोधकर्ताओं ने बताया कि अंतरिक्ष मौसम की पूर्वानुमान के लिए हमें सूर्य के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र के सटीक मॉडल की आवश्यकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट की मदद से यह भी पता लग सकता है कि सूर्य के चुम्बकीय क्षेत्र की वास्तविक स्थिति क्या है।

11 वर्ष के सौर चक्र के रहस्य से भी उठेगा पर्दा

1843 में जर्मन खगोल विज्ञानी सैमुअल हेनरी श्वेबे ने पाया था कि सूर्य की सतह पर स्पॉट मौजूद हैं जो घटते और बढ़ते रहते हैं। दरअसल ये स्पॉट सूर्य के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को चिह्नित करते हैं। आज वैज्ञानिक इसे सौर चक्र के रूप में जानते हैं। यह 11 वर्ष का होता है। इसमें पहले चक्र में सूर्य के स्पॉट फैलते हैं तो सूर्य सक्रिय और अशांत होता है और जब ये सिकुड़ते हैं तो सूर्य शांत हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि आजतक यह नहीं पता चल पाया कि यह चक्र 11 वर्षों का ही क्यों होता है। इसलिए सूर्य के ध्रुवों का करीब से अध्ययन कर इस बारे में समझा जा सकता है।

तनाव में रहते हैं माध्यमिक स्कूलों के ज्यादातर शिक्षक

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों के 94 फीसदी शिक्षक उच्च स्तर के तनाव से ग्रस्त रहते हैं, जिसका छात्रों के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि शिक्षकों के मानना है कि शैक्षणिक और व्यावहारिक रूप से शिक्षण के बोझ को कम करना छात्रों की सफलता में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बीच तनाव का अध्ययन किए जाने पर यह बात सामने आई है कि शिक्षकों के तनाव में रहने का छात्रों के परिणाम पर नकारात्मक असर हो सकता है। अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कीथ हरमन ने कहा, 'अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि दुर्भाग्य से कई शिक्षकों को वह समर्थन नहीं मिल पा रहा जो उन्हें अपनी नौकरी के तनाव से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए जरूरी है।'

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट और व्यवहारिक है कि अध्यापकों में तनाव छात्रों की सफलता से संबंधित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्कूल के तनावपूर्ण माहौल को बेहतर बनाने के तरीके खोजें, ताकि शिक्षकों को अपनी नौकरी के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। शोधकर्ताओं का यह अध्ययन स्कूल साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

फोटो न्यूज

आउत्सविस कैंप के नरसंहार पीड़ितों को श्रद्धांजलि

तानाशाह हिटलर की बर्बरता के गवाह रहे पोलैंड स्थित आउत्सविस कैंप के नाजी जर्मनी से मुक्त कराने की 75वीं वर्षगांठ पर नरसंहार पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता जुटे। तस्वीर में सबसे आगे पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और उनकी पत्नी कोर्नहॉसर डूडा के साथ होलोकॉस्ट सर्वाइवर मैरियन टर्सकी हैं। 1940 में शुरु हुए इस मौत के कैंप को वर्ष 1945 में सोवियत की सेना ने आजाद कराया था। इस कैंप में हिटलर के आदेश पर करीब 11 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिसमें 10 लाख से अधिक यहूदी थे। रायटर

वायु प्रदूषण से बदल जाती है मस्तिष्क की संरचना

शोध अनुसंधान

वायु प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जिन बच्चों का बचपन यातायात संबंधी वायु प्रदूषण के बीच गुजरता है, 12 साल की उम्र तक उनके मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। अमेरिका के सिनसिनाटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार, जन्म से इस तरह के उच्च वायु प्रदूषण के बीच रहने वाले बच्चों में 12 साल की अवस्था तक मस्तिष्क के खास हिस्सों में ग्रे मैटर और कॉर्टिकल में कमी पाई गई। इन हिस्सों का संबंध चलने-फिरने के साथ ही देखने और सुनने जैसी गतिविधियों से होता है। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता ट्रेविक बेकविथ ने कहा, 'इस नतीजे से जाहिर होता है कि जिस तरह की आबोहवा में आप रहते हैं और सांस लेते हैं, उसका असर आपके मस्तिष्क के विकास पर पड़ सकता है।' -एएनआइ

खांसी और सांस लेने में तकलीफ लंग कैंसर के प्रारंभिक लक्षण

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि लंग (फेफड़े) कैंसर के पहले लक्षण के तौर पर सांसों की तकलीफ और खांसी आम होती जा रही है। इसलिए चिकित्सकों को इस घातक बीमारी की प्रारंभिक निशानी के तौर पर इन लक्षणों पर गौर करना चाहिए। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार, इन लक्षणों के जरिये लंग कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान कर पीड़ितों की जान बचाने के तौर-तरीकों को बेहतर किया जा सकता है। यह निष्कर्ष करीब 28 हजार रोगियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। करीब 17 साल की अवधि के दौरान किए गए इस अध्ययन में लंग कैंसर की पहचान होने से पहले पीड़ितों में खांसी और सांस की समस्या में बढ़ोतरी पाई गई। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

अब महाराष्ट्रियन किरदारों में दिखेंगे वरुण धवन

वरुण धवन लगातार अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्मों की रीमेक में काम कर रहे हैं। 'जुड़वां 2' के बाद वरुण धवन अब 'कुली नंबर 1' की रीमेक में नजर आएंगे। कहानी में नयापन लाने के लिए थोड़े-बहुत बदलाव फिल्म के किरदार में किए गए हैं। वर्ष 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'कुली नंबर 1' में गोविंदा ने नीले रंग की कुली की यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन वरुण धवन लाल रंग की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में वरुण महाराष्ट्रियन बने हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में वह मराठी बोलते भी नजर आएंगे। वरुण ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनके किरदार का नाम राजू कुली ही है। यही नहीं, अपनी दूसरी फिल्म 'मिस्टर लेले' में भी वह मराठी किरदार में हैं। जब उनसे पूछा गया कि मराठी कितनी अच्छी तरह से वह सीख पाए हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा- 'येते मला मराठी' (मुझे मराठी आती है) ठीक-ठाक बोल लेता हूं। मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं। जब मैं छोटा था, तब कार्टर रोड (मुंबई का पॉश इलाका) में मेरी एक पड़ोसन रहती थीं। उनका नाम मिसेज गोंगे था। वह मुझे मराठी सिखाती थीं। मैं इसी माहौल में पला-बढ़ा हूं। मेरे कई दोस्त हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर भी शामिल हैं, सभी महाराष्ट्रियन हैं। वरुण ने बताया कि किरदार के लिए मैंने कई जोक्स और गाली-गलौज वाली भाषा को मराठी में सीखा है। लेकिन जहां तक खालिस मराठी बोलने की बात है तो उसकी झलक 'मिस्टर लेले' फिल्म में मिलेगी। 'कुली नंबर 1' में वरुण धवन संग सारा अली खान होंगी।

...जब लता जी ने गोद में उठाया था ऋषि कपूर को

सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर और लता मंगेशकर दोनों ही काफी सक्रिय रहते हैं। इस बार दोनों ही दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर साझा की है वह तस्वीर, जो दोनों से जुड़ी हुई है। ऋषि कपूर ने एक ब्लैक ऐंड व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें वह केवल दो या तीन महीने के हैं और लता मंगेशकर ने उन्हें अपने हाथों में थाम रखा है। ऋषि कपूर ने हिंदी में लिखा, 'नमस्ते लता जी। आपके आशीर्वाद से, देखिए मुझे अपनी दो या तीन महीने वाली अपनी पिक्चर मिल गई। सदा आपका आशीर्वाद रहा है मुझ पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या मैं दुनिया को बता सकता हूं, यह तस्वीर ट्विटर पर डाल कर? यह एक बेशकीमती पिक्चर है मेरे लिए।' लता मंगेशकर ने भी इस तस्वीर को साझा करते हुए पुरानी यादों को ताजा किया और लिखा, 'नमस्कार ऋषि जी। फोटो देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी यह फोटो मिल नहीं रही थी। मुझे यह फोटो देख कर कृष्णा भाभी और राज साहब की याद आई। इस फोटो में भाभी ने आपको मेरे हाथ में दिया था। इसे सबके साथ साझा करके आपने बहुत अच्छा किया। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे यही ईश्वर से प्रार्थना है।'

अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल हुईं प्रियंका

सितारे आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर ट्रोल होते ही रहते हैं। इस बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं प्रियंका चोपड़ा। दरअसल, ग्रैमी अवॉर्ड 2020 में पहनी गई ड्रेस को लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें निशाने पर लिया। डिजाइनर राल्फ ऐंड रूसो की ड्रेस में प्रियंका की तस्वीर की तुलना उस ड्रेस से की गई, जो जेनिफर लोपेज ने कई साल पहले ग्रैमी अवॉर्ड्स के दौरान पहनी थी। प्रियंका की ड्रेस की नेकलाइन उनकी नाभि तक खुली हुई थी। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स ने लिखा, 'प्रियंका ने ग्रैमी 2020 में समां बांध दिया। वे वाकई बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल है, जहां नेकलाइन लॉस एंजेलिस से शुरू होकर क्यूबा तक जा रही है।' इस पर अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने प्रियंका का साथ देते हुए लिखा, 'वेंडल रॉड्रिक्स की टिप्पणी से मैं आहत हूं। प्रियंका अपना पेट छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। यही बात इस तस्वीर को खूबसूरत बना रही है। उनका आत्मविश्वास हर महिला को प्रेरणा देगा। मैं प्रियंका की फैन नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूं।' जेनिफर लोपेज से की जा रही तुलना को लेकर भी यूजर्स में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। एक यूजर ने लिखा, 'क्या प्रियंका चोपड़ा लो बजट वाली जेनिफर लोपेज बनना चाहती हैं? वैसे मैं मजाक कर रही हूं, प्रियंका के ड्रेस मेरे घर जितनी ही महंगी होगी, लेकिन...' जबकि एक यूजर ने प्रियंका की तारीफ करते हुए लिखा, 'वह क्या पहनती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पसंद है। अगर वह सहज हैं तो ट्रोल्स की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वह 21वीं सदी के आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनकी उपलब्धियों पर गर्व है।' इससे पहले मेट गाला में पहनी गई उनकी ड्रेसेस को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया था।

68 हजार रुपये में तैयार हुआ जेनिफर का दुपट्टा

धारावाहिक 'बेहद 2' में नया मोड़ आने वाला है। सोनी चैनल पर प्रसारित हो रहे इस शो में रूद्र माया के बिछाए जाल में फंस जाएगा और माया से भाग कर शादी करेगा। रुद्र का किरदार शिविंग नारंग निभा रहे हैं, जबकि माया का जेनिफर विंगेट। माया की ऑनस्क्रीन शादी को लेकर खास तैयारी की गई है। बताया जाता है कि ऑनस्क्रीन शादी में पहने जाने वाले दुपट्टे की कीमत करीब 68 हजार रुपये है। शो की क्रिएटीव टीम के मुताबिक, माया को 'बेहद 2' के पूरे सीजन में काले कपड़ों में देखा जाएगा, क्योंकि वह एमजे (आशीष चौधरी) से बदला लेने आई हैं, जो रुद्र के पिता हैं। चूंकि मौका शादी का है, इसलिए उनके कपड़ों में कुछ लाल होना जरूरी था। इस वजह से उनके दुपट्टे को लाल रखा गया। यह दुपट्टा विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ माया के लिए बनवाया गया है। इस दुपट्टे में चांदी के धागों से कीमती कारीगरी की गई है। इस ब्राइडल दुपट्टे को बनाने में तीन कारीगरों ने 48 घंटे की मेहनत की है। इतनी मेहनत के बाद माया का नया स्वरूप जरूर दर्शकों को चौंकाएगा।

'मैदान' में नजर आए कीचड़ में सने पैर

'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' की सफलता के बाद अजय देवगन की आगामी फिल्म 'मैदान' भी वास्तविक कहानी से प्रेरित है। अमित शर्मा निर्देशित 'मैदान' में अजय देवगन पूर्व फुटबॉल कोच सय्यद अब्दुल रहीम की भूमिका में होंगे। सय्यद अब्दुल रहीम वर्ष 1950 से 1963 तक भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर थे। उनके नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल टीम 1956 में मेलबर्न ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। अजय ने फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए एक तस्वीर साझा की है, जिसमें चेहरे तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाफ पैंट में हाथों में फुटबॉल थामे कीचड़ में सने हुए पैर नजर आ रहे हैं।

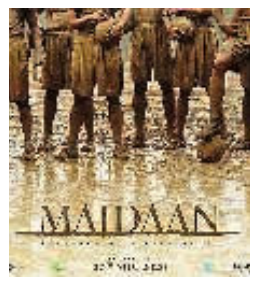

इंटरनेट के आने से हमारी याददाश्त कमजोर हुई है : सोहैल खान

इंटरनेट ने एक तरफ जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। अभिनेता सलमान खान के छोटे भाई सोहैल खान का मानना है कि इंटरनेट के आने से हमारी याददाश्त कमजोर हुई हैं। बच्चे इंटरनेट पर किसी भी सवाल का जवाब अब बड़ी आसानी से ढूढ़ लेते हैं, जबकि पहले एक सवाल का जवाब जानने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी।

मंगलवार को मुंबई में अपने बहनोई अतुल अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री के प्रोडक्शन हाउस पिक्चर पाठशाला द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। पिक्चर पाठशाला अलग-अलग स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों को फिल्म निर्माण की कला सिखाती है। सोहैल के अलावा इस समारोह में सलीम खान, अरबाज खान, कट्रीना कैफ, अतुल अग्निहोत्री और सुनील ग्रोवर समेत कई लोगों ने शिरकत की। बच्चों को फिल्म निर्माण सिखाना सोहैल सराहनीय काम मानते हैं। उनके मुताबिक, फिल्म निर्माण सीखने से बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा मिलती है। इससे बच्चों को अभिनय, लेखन, तकनीकी आदि की जानकारी होती है। फिल्म निर्माण सीखने से बच्चों की कल्पनाशक्ति भी मजबूत होती है। इससे बच्चे अपने आसपास की समस्याओं को फिल्म के माध्यम से उठा सकते हैं। सोहैल खान आखिरी बार साल 2017 में सलमान के साथ फिल्म 'ट्यूबलाइट' में दिखे थे। इसके अलावा वह फिल्म 'लवयात्री' और 'दबंग 3' में भी मेहमान भूमिका में थे।